

चिंतन

डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा को प्राथमिकता दें कंपनियां

इंटरनल के स्वामित्व वाली इकाई ब्लिंकिट ने पहले दावा किया था कि वह 10 मिनट में सामान पहुंचाएगी। अब कंपनी ने डिलीवरी कर्मियों के कल्याण से जुड़ी बढ़ती चिंताओं के बीच सभी मंच से अपना ‘10 मिनट में’ डिलीवरी का दावा हटा लिया है। कंपनी ने अपनी टैग-लाइन को 10 मिनट में 10,000 से अधिक उत्पाद पहुंचेंगे से बदलकर अब 30,000 से अधिक उत्पाद आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे कर दिया है। हालांकि यह फैसला कर्मचारियों को हड़ताल और केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद लिया गया है। सरकार डिलीवरी कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। चूंकि 10 मिनट में डिलीवरी से राइड्स की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था। इतने कम समय में सामान डिलीवर करने के लिए उन्हें तेज रफ्तार से बाइक चलानी होती है। इससे सड़क हादसों के कारण उनकी जान को खतरा हो रहा था। इसके अलावा उपभोक्ता से मिले ओटीपी के बाद ही उनका सामान डिलीवर माना जाता है। समय पर डिलीवरी न होने से राइडर्स की रैंक प्रभावित होती है। उत्तर भारत में जारी भीषण सर्दी और कोहर के बीच ब्लिंकिट के फैसले से हजारों डिलीवरी बॉयज को बड़ी रहत मिलेगी। बता दें कि इस समय भीषण ठंड के कारण लोग घरों से बाहर निकलना ठीक नहीं समझते। ऐसे में वे घर का सामान ऑनलाइन मंचों से अधिक मंगाते हैं। इसके कारण डिलीवरी बॉयज पर समय पर सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इतना कम समय होने के कारण सुबह-शाम ऑफिस के समय और रात को गिग वर्कर्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में कर्मचारियों पर भारी दबाव था, क्योंकि समय पर डिलीवरी नहीं होने से कर्मचारियों को परफॉर्मेंस प्रभावित होती थी। उन्हें अच्छी रैंक तभी मिलती थी, जब वे समय पर डिलीवरी कर उपभोक्ता के मोबाइल पर आने वाले ओटीपी को कंपनी के एप पर सेंड करते थे। ब्लिंकिट के बाद अब स्विगी और जेज्टो जैसे अन्य ‘क्विक कॉमर्स’ मंच भी इस कदम का अनुरसर कर सकते हैं। यह एक बड़ा बदलाव होगा, जो ऐसे कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करेगा। दस मिनट में डिलीवरी के वादे के कारण गिग वर्कर्स ने देशव्यापी हड़ताल की थी, जिसने कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आय की ओर ध्यान आकर्षित किया। हाल में ‘एक्स’ पर इंटरनल ग्रुप के सीईओ दीपिंदर गोयल ने लिखा था कि 10 मिनट में डिलीवरी का वादा सामान पहुंचाने वाली पर दबाव नहीं डालता है और न ही असुरक्षित ड्राइविंग का कारण बनता है, क्योंकि उन्हें एप पर 10 मिनट का टाइम नहीं दिखाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि 10 मिनट में या उससे तेज डिलीवरी मुख्य रूप से स्टोर ग्राहकों के करीब होने के कारण होती है, न कि सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण। यह फैसला डिलीवरी कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, जो अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर डिलीवरी करते हैं। यह गिग वर्कर्स के अधिकारों को मजबूत करेगा, जो अक्सर अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। कुल मिलाकर, ब्लिंकिट का '10 मिनट में डिलीवरी' का दावा हटाने का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है, जो डिलीवरी कर्मियों को सुरक्षा और उनके अधिकारों को प्राथमिकता देता है। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि कंपनियों को अपने कर्मियों की सुरक्षा और अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि सिर्फ मुनाफे को। यह फैसला अन्य कंपनियों के लिए भी एक उदाहरण हो सकता है, जो अपने कर्मियों की सुरक्षा और अधिकारों को नजरअंदाज कर रहे हैं।

दीपस्तंभ

मुरारी गुप्ता



भारतीय दर्शन से ही विश्व कल्याण संभव

विश्व के हर कोने में आज अशांति का वातावरण बना हुआ है। कई देश आपस में युद्ध में उलझे हुए हैं। कथित शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर मुल्कों पर उनके संसाधनों के लालच में बलात कब्जा करने की मंशा पाले हुए हैं। अमेरिका और वेनेजुएला का प्रकरण पूरे विश्व के सामने है। दुर्भाग्य से पूरा विश्व, संयुक्त राष्ट्र संघ और तमाम बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन इस पर चुप हैं। ईरान में वहां को जनता 1979 की तथाकथित इस्लामिक क्रांति के विरुद्ध बिगुल बजाए हुए हैं और अपनी मूल पहचान पर गर्व कर रही है। सोशल मीडिया पर ईरानी महिलाएं अपनी पहचान को खुल कर स्वीकार कर रही हैं। उधर, बांग्लादेश में वहां का अल्पसंख्यक हिंदू समूह राजनीतिक संरक्षण प्राप्त चरमपंथियों का शिकार बन रहा है। तथाकथित अमन और शांति के पैरोकार इस वक्त खामोश हैं। पश्चिम की कथित लिबरल नीतियों ने संयुक्त अरब अमीरात के शासकों को भी भयभीत कर रखा है। वे अपने छात्रों को ब्रिटेन और यूरोप के विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए भेजने से डरने लगे हैं कि कहीं उनके छात्र यूरोप के विश्वविद्यालयों में लिबरल नीतियों के कारण संरक्षण पा रही जेहादी मानसिकता के शिकार नहीं हो जाएं। आज की वैश्विक परिस्थितियां यह प्रश्न खड़ा करती हैं कि क्या केवल राजनीतिक क्रांतियां, सत्ता परिवर्तन या वैचारिक कट्टरता मानव समाज को स्थायी शांति और समानता की ओर ले जा सकती हैं। ईरान में इस्लामी शासन के विरुद्ध उठती आवाजें, महिलाओं के समान अधिकारों की मांग, धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध असंतोष और सामाजिक स्वतंत्रता की आकांक्षा इस बात का प्रमाण हैं कि जब कोई विचारधारा मानव स्वभाव, विविधता और गरिमा के विपरीत जाती है, तो अंततः उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया जन्म लेती है। ईरान की वर्तमान स्थिति केवल राजनीतिक असंतोष का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक बेचैनी को भी दर्शाती है। कट्टर धार्मिक व्याख्याओं के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश, महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन और आधुनिक जीवन मूल्यों के साथ टकराव, इन सबने समाज में असंतोष को जन्म दिया है। महिलाएं केवल वस्त्रों या बाहरी आचरण के प्रश्न पर नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व, सम्मान और समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह संघर्ष इस बात को रेखांकित करता है कि कोई भी व्यवस्था, जो समानता और मानवीय गरिमा को नकारती है, लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकती। भारत का सनातन दर्शन मूलतः “अहं ब्रह्मास्मि” और “तत्त्वमसि” जैसे सूत्रों के माध्यम से प्रत्येक जीव में एक ही चेतना को देखता है। यहां स्त्री और पुरुष के बीच मौलिक स्तर पर कोई भेद नहीं, बल्कि दोनों को सृजन के पूरक रूप में स्वीकार किया गया है। वैदिक काल से लेकर उपनिषदों तक गांधी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी विदुषी खियां इस बात का प्रमाण हैं कि ज्ञान, संवाद और आध्यात्मिक विमर्श में स्त्रियों की भूमिका केंद्रीय रही है। इसके विपरीत जब किसी धर्म या विचारधारा की संकीर्ण व्याख्या स्त्री को द्वितीय श्रेणी में धकेल देती है, तो वह समाज को भीतर से कमजोर करती है। ईरान में चल रहा संघर्ष इसी असंतुलन का परिणाम है। कट्टरता मानव का मूल स्वभाव नहीं है। मानव का मूल स्वभाव सबका साथ और सबका विश्वास और सबका कल्याण है। आज पूरा यूरोप आतंकवाद से पीड़ित है। ईरान की सामाजिक उथल-पुथल, यूरोप की आतंकवाद से पीड़ा और अमेरिका की प्रभुत्ववादी नीतियों के बीच भारत यह स्मरण कराता है कि शांति का मार्ग हिंसा, कट्टरता या वर्चस्व में नहीं, बल्कि समानता, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व में है। “वसुधैव कुटुम्बकः” केवल भारत की विरासत नहीं, बल्कि विश्व का भविष्य है। यदि मानवता को वास्तव में शांति और कल्याण की ओर बढ़ना है, तो उसे भारत के इसी सनातन दर्शन की ओर लौटना होगा, जहां सबका अस्तित्व सुरक्षित हो और सबका कल्याण सुनिश्चित हो।

(लेखक उत्कल पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)



पर्व

डॉ. बलवीर आचार्य

जब सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है तब उत्तरायण (उत्तर+अयन) कहलाता है और जब सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है तब दक्षिणायन (दक्षिण+अयन) कहलाता है। भारतीय संस्कृति में उत्तरायण केवल खगोलीय घटना नहीं, अपितु आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इसीलिए उत्तरायण को देवयान मार्ग, उत्तम मार्ग, प्रकाश का मार्ग कहा गया है। ऋतु का आधार कहा गया है। देवताओं का दिन–रात भी सूर्य की गति से जोड़ा गया है। मकर संक्रान्ति महज पतंग उड़ाने या पकवान खाने का दिन नहीं है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और जब हम प्रकृति के साथ लयबद्ध होते हैं तो हमारा जीवन आनन्द और आरोग्य से भर जाता है।

छोटे- छोटे संकल्प आत्मविश्वास बढ़ाते हैं



संकलित

दर्शन

जिस प्रकार किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पूर्व हाथ में जल लेकर संकल्प लिया जाता है उसी प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए उसे करने का संकल्प लिया जाता है। बगैर संकल्प हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संकल्प लेने के लिए इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। संकल्प के पश्चात प्रयास प्रारंभ होते हैं। जब संकल्प दृढ़ होता है तो प्रयास को हिम्मत मिलती है, विजय की राह आसान हो जाती है। हमारी सफलता हमारे संकल्प पर निर्भर करती है। हम जितना भरोसा अपने संकल्प पर करेंगे उसी अनुपात में हमें सफलता प्राप्त होगी। यदि हमारा संकल्प विजय का है तो हमारी सफलता भी निश्चित है। संकल्प सकारात्मक ऊर्जा के रूप में सह प्रेरक का काम करता है। जीवन में छोटे-छोटे संकल्प लेते रहना चाहिए। जब हम छोटे-छोटे संकल्पों को पूर्ण करते हैं तो आत्मविश्वास और हमारी क्षमता में वृद्धि होती है। दृढ़ संकल्प में असीम शक्ति होती है, जो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बाधाओं से जुझने में सक्षम बनाती है। हालांकि, संकल्प लेकर उन्हें भूलना भी आम बात है। अक्सर हम देखते हैं कि नशे के आदी लोग रोज संकल्प लेते हैं कि वे अब आगे से नशा नहीं करेंगे, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके संकल्प में दृढ़ता की कमी होती है। दृढ़ संकल्प शक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। जो संकल्प के साथ जीता है वह साधक होता है। कहते हैं कि एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में न तो योग्यता का अंतर होता है और न ही ज्ञान का, बल्कि अंतर है तो केवल दृढ़ संकल्प का और यही निर्णायक सिद्ध होता है।

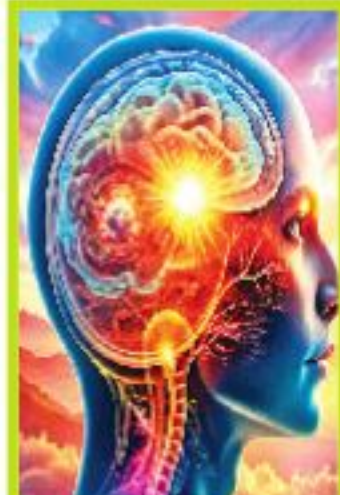
अंतर्मन



करंट अफेयर

सिंगापुर में दुर्लभ हिमालयी गिद्ध को बचाया गया

सिंगापुर में एक राजमार्ग से ‘ जल्द ही संकटग्रस्त होने वाली’ श्रेणी में शामिल एक दुर्लभ हिमालयी गिद्ध को बचाया गया है और उसे छोड़ने से पहले स्वस्थ अवस्था में लाया जा रहा है। यहां एक पशु कल्याण समूह ने यह जानकारी दी। एनिमल कंसर्न्स रिसर्च एंड एजुकेशन सोसाइटी (एसीआरईसी) ने 11 जनवरी को परेशान हालत में दिखे प्रवासी पक्षी को बचाया था। समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कलई वनन बालकृष्णन ने यह जानकारी दी। फिलहाल एसीआरईसी की पशु चिकित्सा टीम गिद्ध की देखभाल कर रही है। टीम ने गिद्ध के पूरी तरह स्वस्थ होने और फिर उसे जंगल में छोड़े जाने की उम्मीद जताई है। ‘ द स्टेट्स टाइम्स’ ने सौमवार को एक खबर में बालकृष्णन के हवाले से कहा, ‘ शरीर में पानी की कमी, कमजोरी और लंबी यात्रा के कारण थकान जैसी शुरुआती स्वास्थ्य समस्याएं गिद्ध में दिख रही हैं।’ उन्होंने कहा कि 11 जनवरी की दोपहर को एक द्यवित ने एसीआरईसी को गिद्ध के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद तीन सदस्यीय बचाव टीम ने राजमार्ग पर घूम रहे गिद्ध को सुरक्षित पकड़ लिया। इससे पहले वह एक नहर में अटका हुआ था। हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में आम तौर पर पाए जाने वाले हिमालयी गिद्ध सिंगापुर में बहुत कम देखे जाते हैं।



हार्मोन का उत्पादन, हृदयगति और शरीर का तापमान सहित कई अन्य दैनिक शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। व्यवस्थित जैविक घड़ी को अक्सर नींद की खराब गुणवत्ता से जोड़ा जाता है। विभिन्न अध्ययनों में खराब गुणवत्ता वाली नींद का डिमैथिया और दिल की बीमारियों के बढ़ते जोखिम से सीधा संबंध पाया गया है। साल 2025 में किए गए अध्ययन में प्रतिभागियों की दिल की सेहत और स्वतचाप का भी विश्लेषण किया गया, जो अन्य कारकों के साथ–साथ नींद की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं।

जितने काल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरी करती है, उसको एक ‘सौर वर्ष’ कहते हैं और कुछ लम्बी वर्तुलाकार जिस परिधि पर पृथ्वी परिभ्रमण करती है, उसको ‘क्रान्तिवृत्त’ कहते हैं। ज्योतिषियों द्वारा इस क्रान्तिवृत्त के 12 भाग कल्पित किए हुए हैं और उन 12 भागों के नाम उन-उन स्थानों पर आकाशस्थ नक्षत्र पुंजों से मिलकर बनी हुईं कुछ मिलती-जुलती आकृति वाले पदार्थों के नाम पर रख लिए गए हैं। प्रत्येक भाग व आकृति ‘राशि’ कहलाती है। जब पृथ्वी एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करती है तब उसको ‘संक्रान्ति’ कहते हैं। सूर्य सिद्धान्त (1.12) में कहा गया है- ‘राश्यन्तरं यदा सूर्यः संक्रान्तिरिति कथ्यते” लोक में उपचार से पृथ्वी के संक्रमण को सूर्य का संक्रमण कहने लगे हैं। छह मास तक सूर्य क्रान्तिवृत्त से उत्तर की ओर उदय होता रहता है और छह मास तक दक्षिण की ओर निकलता रहता है। सूर्य के उत्तर की ओर उदय की अवधि को ‘उत्तरायण’ और दक्षिण की ओर उदय की अवध को ‘दक्षिणायन’ कहते हैं। अयन का अर्थ होता है गति।



जब सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है तब उत्तरायण (उत्तर+अयन) कहलाता है और जब सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है तब दक्षिणायन (दक्षिण+अयन) कहलाता है। उत्तरायण काल में सूर्य उत्तर की ओर से उदय होता हुआ दिखता है, उसमें दिन बढ़ता जाता है और रात्रि घटती जाती है। दक्षिणायन में सूर्योदय दक्षिण की ओर दृष्टिगोचर होता है। उसमें रात्रि बढ़ती जाती है और दिन घटता जाता है। सूर्य की मकर राशि की संक्रान्ति से उत्तरायण और कर्क राशि की संक्रान्ति से दक्षिणायन प्रारम्भ होता है। प्राचीन भारत में उत्तरायण और मकर संक्रान्ति एक ही दिन होते थे। अयन चलन के कारण वे धीरे-धीरे अलग हुए। सामान्यतः मकर संक्रान्ति को उत्तरायण का आरम्भ माना जाता है।

खगोल विज्ञान के अनुसार सूर्य का उत्तरायण वह बिन्दु है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में अपनी अधिकतम स्थिति (मकर रेखा) से उत्तर दिशा की ओर लौटना प्रारम्भ करता है। यह घटना 21 या 22 दिसम्बर को घटित होती है। इसे शीत अयनान्त कहा जाता है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लम्बी रात होती है। यह घटना पृथ्वी के अक्षीय झुकाव (23.5°) तथा उसकी वार्षिक परिक्रमा का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस दृष्टि से यही समय वार्षिक या खगोलीय उत्तरायण है। भारतीय पंचांग की निरयन पद्धति के अनुसार, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रान्ति होती है। यह सामान्यतः 14 या 15 जनवरी को आती है। भारतीय ज्योतिष स्थिर नक्षत्रों को आधार मानता है। पृथ्वी की धुरी

मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य-ऊर्जा के पुनरुत्थान का प्रतीक है। यह समय आत्म-साक्षात्कार, ध्यान और संकल्प सिद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। मकर संक्रान्ति के पर्व पर दान, स्नान और जप करने का बहुत महत्व है-“मकर संक्रांती दानस्नानजपैः सहस्रगुणं फलम्”। इस दिन खिचड़ी, तिल, कम्बल और अन्न का दान किया जाता है। दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार का त्याग करना है। मकर संक्रान्ति के पर्व पर तिल और गुड़ का सेवन करने का भी महत्व है। सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ का मेल न केवल स्वादिष्ट होता है, अपितु यह आयुर्वेद भोज आधुनिक विज्ञान दोनों की दृष्टि से एक सर्वोत्तम भोजन है। इनके सेवन से होने वाले प्रमुख लाभ और उनके पीछे के वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। हड्डियों की मजबूती, तिल कैल्शियम का खजाना है और गुड़ इसमें मैग्नीशियम प्रदान करता है। तिल में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जो इन दोनों के मिश्रण में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यह ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करता है। गुड़ आयरन का प्राकृतिक स्रोत है, जबकि तिल में कॉपर और आयरन दोनों होते हैं। गुड़ शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है।

तिल में मौजूद कॉपर आयरन के अवशोषण में मदद करता है, जिससे शरीर में नया खून बनता है और थकान या कमजोरी दूर होती है। इन दोनों की प्रकृति गर्म होती है, जो शरीर को आन्तरिक गर्माहट देती है। तिल में मौजूद जिंक और सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। गुड़ शरीर के श्वसन तन्त्र को साफ करने में मदद करता है, जिससे सर्दी-खांसी और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। गुड़ पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है। तिल में मौजूद फाइबर आंतों की सफाई करने में सहायक होते हैं। तिल में ‘सेसमिन’ और ‘सेसमोलिन’ नामक तत्व पाए जाते हैं।

ये तत्व शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड प्रेशर को नियन्त्रित करने में मदद करते हैं। मकर संक्रान्ति महज पतंग उड़ाने या पकवान खाने का दिन नहीं है। यह सूर्य की भान्ति तेजस्वी बनने और गुड़ के समान मधुर वाणी बोलने का संकल्प है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और जब हम प्रकृति के साथ लयबद्ध होते हैं तो हमारा जीवन आनन्द और आरोग्य से भर जाता है।

(लेखक प्रोफ़ेसर एम्बेड्ज रोहतक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अजी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

भगवान या भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए



संकलित

प्रेरणा

एक बूढ़ी महिला गौतम बुद्ध के पास पहुंची। उस महिला की बुद्ध के लिए गहरी आस्था थी। दरअसल, उस महिला के बेटे की मृत्यु हो गई थी। महिला बहुत दुखी थी और उसने बुद्ध से कहा कि आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। महिला को लग रहा था कि बुद्ध उसके बेटे का जीवन बचा सकते हैं। बुद्ध ने महिला की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आना है, जहां कभी किसी की मौत न हुई हो। जिस परिवार ने किसी की मृत्यु का दुख नहीं देखा है, वहां से सरसों ले आओ। महिला ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है। बूढ़ी महिला गांव की ओर चल दी और एक-एक घर में जाकर पूछने लगी। महिला जिस घर में जाती, वहां कहती कि अगर आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो तो एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दीजिए। गांव के सभी लोगों का यही जवाब रहता था कि हमारे घर में मृत्यु तो हुई है। कुछ लोगों की बड़ी उम्र में हुई है तो किसी की असमय हुई। जब सभी घरों से ऐसे ही उत्तर मिल रहे थे तो महिला समझ गई कि बुद्ध ने मुझे जरूर कुछ सोचकर ही भेजा है। जब वह लौटकर बुद्ध के पास पहुंची, तब तब वह जान चुकी थी कि एक दिन मौत सबको आनी है। उसका शोक लंबे समय तक नहीं मनाना चाहिए।



इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ा

2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जिससे रोजगार सृजित हुए और विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ा। 2026 में भी यह गति जारी रहेगी क्योंकि यह सेमीकंडक्टर संयंत्र व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर देंगे।

- अटवैनी वैष्णव, केंद्रीय सूचना मंत्री



सीएसपीओसी की मेजबानी

समुद्र संसदीय लोकतंत्र का गौरवशाली प्रतीक भारत, 14 से 16 जनवरी 2026 तक राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) की मेजबानी करने जा रहा है।

- ओम किरला, लोकसभा अध्यक्ष



इनेज व्यवस्था विकसित

दिल्ली में जलभात की दसकों पुरानी समस्या को लेकर दिल्ली सरकार का काम सिर्फ बरतार के दिनों तक सीमित नहीं है। सालभर, लगातार और हिस्टोरिक के साथ एक मजबूत इनेज व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसी दिशा में 4 बड़े टंक इनेज का निर्माण युद्धस्तर पर चल रहा है।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

बजट पूर्व चर्चा

नारी शक्ति ही प्रदेश की प्रगति का आधार है। हमारी सरकार इसी विजन को विकास की घुरी बना रही है। इसी विजन को लेकर आज मुख्यमंत्री कार्यालय ने आगामी बजट के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों से आई महिला प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की।

- मजनलाल, सीएम, राजस्थान



अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फेक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से : hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

खबर संक्षेप

बंगाल में फैला जानलेवा संक्रामक रोग

कोलकाता। कुछ वर्षों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में संक्रामक

बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। पिछले साल कई तरह के संक्रामक रोग अक्सर सुर्खियों में रहे। केरल में निपाह वायरस के मामलों ने खूब परेशान किया। अब पश्चिम बंगाल में भी निपाह का संक्रमण है। 70 फीसदी रोगियों की मौत होती है।

अब पॉलीट्रॉमा आईसीयू में पानी, 14 को निकाला

जयपुर। यहां के सवाई मानसिंह अस्पताल के पॉलीट्रॉमा आईसीयू के पास सोमवार देर रात को पाइप से पानी का रिसाव हो गया, जिससे पूरे आईसीयू में पानी भर गया।

कर्मचारियों ने सूचना प्रशासन को दी। प्रशासन ने 14 गंभीर मरीजों को दूसरी जगह ट्रांसफर किया। इस अस्पताल में 3 महीने पहले न्यूरो आईसीयू में आग से 6 लोगों की मौत हो गई थी।

उपराष्ट्रपति ने नशामुक्त परिसर की शुरुआत की

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से बचाने,विकसित तथा आत्मनिर्भर भारत दृष्टियोजना साकार करने के निरंतर सामूहिक प्रयास की जरूरत पर जोर देते हुए मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में नशामुक्त परिसर अभियान आरंभ किया। साथ ही ई-संकल्प मंच और मोबाइल एप्लिकेशन का भी शुभारंभ किया।

राज ठाकरे के बयान पर भड़के अयोध्यावासी

अयोध्या। यहां के साधु-संत और स्थानीय लोगों ने बताया कि राज ठाकरे को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूरे देश में हिंदी भाषा बोली जाती है। जबरदस्ती किसी भी भाषा को नहीं बुलवाया जा सकता है। राज का बयान बेहद ही निंदनीय है और उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर राज ऐसा करेंगे, तोमहाराष्ट्र के लोगों के साथ भी ऐसा होगा।

सलेम अंतरराष्ट्रीय अपराधी, 2 दिन पैरोल दें

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बंबई हाई कोर्ट को बताया कि 1993 के मुंबई बम धमाका मामले में दोषी गैंगस्टर अबू सलेम एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी है। उसे पुलिस सुरक्षा के साथ केवल दो दिन की आपातकालीन पैरोल दी जा सकती है। सलेम ने अपने बड़े भाई की मृत्यु का हवाला देकर 14 दिन की पैरोल मांगी थी। इसी पर सवाल उठा है।

राजोरी के पास फिर दिखे ड्रोन सेना ने बरसाई गोलियां तो भागे

एजेन्सी►► राजोरी जिले में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में मंगलवार शाम को एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। सेना ने ड्रोन पर गोलीबारी की तो वे गायब हो गए। माना जा रहा है कि गोली से, ड्रोन या तो कहीं गिरे हैं या फिर पाकिस्तान की तरफ वापस चले गए। रविवार शाम को राजोरी, पुंछ और सांबा जिले में पाकिस्तानी ड्रोंनों की घुसपैठ हुई थी। शाम 7 बजे से साढ़े सात बजे के बीच पहले राजोरी के केरी सेक्टर के ड्रंग गाला और उसके बाद ठंडीकस्सी में ड्रोन देखे गए। केरी के ड्रंग गाला में दो से तीन ड्रोन दिखते ही सेना ने उनपर गोलियां दागीं। इसके बाद ड्रोन गायब हो गए।

मराठी अस्मिता और गठबंधन के मुद्दे पर यहां गरमाई सियासत

एजेन्सी►► मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति में नगर निगम चुनाव इस बार सत्ता की कठिन परीक्षा बन गया है। 15 जनवरी को राज्य की 29 नगर निगमों में मतदान होना है, जिसे लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। मराठी अस्मिता, गठबंधन की मजबूती और बीएमसी की कुर्सी समेत कई मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप सातवें आसमान पर पहुंच गया है। आज यानी मंगलवार को इस चुनावी अभियान के प्रचार-प्रसार का आखिरी दिन है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में अपनी-अपनी दावेदारी प्रबल बनाने में लगी हुई हैं। प्रचार के आखिरी दौर में भी कई बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं, जिसके चलते सियासी तापमान अपने चरम पर है। बता दें कि मतदान को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 जनवरी यानी गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी और नतीजे 16 जनवरी को आएंगे।

प्रचार समाप्त, राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप सातवें आसमान पर पहुंचे, सभी बता रहे अपनी दावेदारी

15 को मतदान 29 नगर निगमों में चुनाव 227 वार्डों में बीएमसी में मतदान, 1,700 उम्मीदवार मैदान में 7.30 बजे सुबह से होगी वोटिंग



बीएमसी में बड़ी लड़ाई पहले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई की सबसे बड़ी नगर निकाय बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के लिए मुकाबला काफी दिलचस्प है। यहां 227 वार्डों के लिए करीब 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीएमसी चुनाव को सत्ता की रेमीफाइलज लड़ाई माना जा रहा है।

नागपुर में सीएम फडणवीस ने किया रोड शो

कुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में जबरदस्त रोड शो किया। वे बुलेट बाइक पर सवार होकर रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दवा किया कि कुनाव के बाद मुंबई में महायुति का मेयर बनेगा। सीएम फडणवीस ने साफ कहा कि बीएमसी की कमान मराठी हाथों में ही रहेगी। उन्होंने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि मराठी समाज खतरे में नहीं है, बल्कि कुछ राजनीतिक दलों का अस्तित्व खतरे में है। उनका कहना था कि महाराष्ट्र किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि सभी मराठियों का है।

मराठी लोगों पर खतरा: राउत

दूसरी ओर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने फडणवीस पर तीखे हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की वजह से ही मराठी लोग खतरे में हैं। राउत ने कहा कि ठाकरे परिवार किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है और उन्हें डराने की जरूरत नहीं।

पुणे में शिवसेना अकेले मैदान में

पुणे नगर निगम चुनाव में एकमात्र शिंदे गुट की शिवसेना भाजपा से सीटों पर सहमति नहीं बनने के कारण अकेले कुनाव लड़ रही है। पार्टी नेता नीलम गोहें ने दवा किया कि शिवसेना इतनी सीटें जीतेगी कि नगर निगम के फैसलों में उसकी अहम भूमिका होगी।

शाह ने गांधीनगर में 267 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास सनातन धर्म को मिटाना आसान नहीं, ये सूरज और चांद की तरह सदैव अमर रहेगा

एजेन्सी►► गांधीनगर

पीएम ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ किया था



बीती 11 जनवरी को पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ किया था। यह पर्व सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के हमले और मंदिर के पुनर्निर्माण के 1000 हजार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। महमूद गजनी ने साल 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर के मध्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे सालभर देश में मनाया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा।

मंदिर पर नहीं हमारी आस्था पर किया था हमला

शाह ने कहा कि एक हजार साल पहले महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और इसे तोड़ा। उसके बाद अन्य हमलावरों जैसे अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, महमूद बेगड़ा और औरंगजेब ने भी हमले किए, लेकिन हर हमले के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। हमलावर तबाही में विश्वास रखते थे और मंदिर बनाने वालों का विश्वास रचना में। आज 1000 साल बाद हमलावर मिट गए हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर अभी भी पूरे गर्व के साथ खड़ा है। शाह ने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर हमला सिर्फ एक मंदिर पर हमला नहीं था बल्कि ये हमारी आस्था, विश्वास और आत्म सम्मान पर हमला था। हमले का जवाब दूसरा हमला नहीं हो सकता। इसका उत्तर आत्म-सम्मान में छिपा है।

यहां पर विश्वस्तरीय व्यवस्था होगी,अध्ययन की सुविधा भी शाह ने कहा कि दुनिया भर की बीएसएल लैब्स का अध्ययन करके यह तैयार की जा रही है। यहां पशुओं से होकर मानव तक पहुंचने वाले रोगों का भी अध्ययन करने की विश्वस्तरीय व्यवस्था होगी। एक अध्ययन के अनुसार 60 से 70 प्रतिशत बीमारियां पशुओं से होकर इंसान तक पहुंचती हैं, इसलिए भारत ने वन हेल्थ मिशन के माध्यम से मानव और पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यक्रम शुरू किया है।

गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर समग्र विकास का आधार बनेगा

शाह ने गांधीनगर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की बीएसएल-4 बायो-कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास किया। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज गुजरात की धरती से हम भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा, बायो सेफ्टी और बायोटेक विकास के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में बीएसएल-4 बायो-कंटेनमेंट फैसिलिटी के शिलान्यास से आगामी दिनों में समग्र भारत के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र का एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उमरेगा।

पुणे के बाद भारत की दूसरी उच्च स्तरीय लैब होगी

शाह ने कहा कि पुणे की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के बाद यह भारत की दूसरी उच्च स्तरीय लैब होगी। परंतु, किसी राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही यह पहली लैब है, जिसका श्रेय गुजरात को जाता है। एक विशाल कॉम्प्लेक्स में 362 करोड़ की लागत से 11 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में देश की जैविक सुरक्षा का एक मजबूत किला बने जा रहा है। हम दुनिया में हो रहे अत्याधुनिक रिसर्च से कई साल तक पिछड़े हुए थे, लेकिन बीएसएल-4 बायो-कंटेनमेंट फैसिलिटी से बायो-टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को नए मौके मिलेंगे और भारत इस क्षेत्र में आगे निकल पाएगा।

‘जन नायकन’ रोकने का प्रयास हो रहा प्रधानमंत्री तमिल जनता की आवाज को नहीं दबा सकते



एजेन्सी►► नई दिल्ली

थलापति विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है 'जन नायकन' रिलीज से पहले ही विवादों में फंसी है। अपने सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर फिल्म के मेकर्स अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस बीच विजय की फिल्म को तमिल सिनेमा के तमाम कलाकारों का समर्थन मिल रहा है। अब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने विजय की 'जन नायकन' की रिलीज अटकने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने इसको लेकर अपने एक्स पर एक पोस्ट की है। इस पोस्ट में राहुल ने पीएम मोदी का जिक्र किया है। पोस्ट में राहुल ने लिखा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'जन नायकन' को रोकने का प्रयास तमिल संस्कृति पर हमला है। पीएम मोदी आप तमिल जनता की आवाज को दबाने में कभी सफल नहीं होंगे।

अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

अब मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। उच्चतम न्यायालय में इस चुनौती के पीछे मुख्य दलील ये है कि फिल्म को रिलीज करने से पहले सभी प्रोसेस का पालन करना जरूरी है। साथ ही किसी भी तरह के सर्टिफिकेट जारी करने या रोकने के फैसले पर रिव्यू की संभावना खली रहेगी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय नहीं की है, लेकिन इस कदम ने फिल्म के रिलीज को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने संसदीय शिष्टमंडल से की मेंट भारत आए दक्षिण अफ्रीका और कैरीबियाई देश ग्रेनेडा के संसदीय शिष्टमंडल से की चर्चा

हरिभूमि ब्यूरो►► नई दिल्ली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के अवसर पर भारत आए दक्षिण अफ्रीका और कैरीबियाई देश ग्रेनेडा के संसदीय शिष्टमंडल से भेंट की। बिरला ने दक्षिण अफ्रीकी संसद की नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेज के डेय्युटी चेयरपर्सन एल. गोवेंडर, उपाध्यक्ष डॉ. एनेली लॉट्टिएट और ग्रेनेडा की सीनेट अध्यक्ष डॉ. डेसिमा विलियम्स के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल का आत्मीय स्वागत किया। शिष्टमंडल ने बिरला के साथ पारंपरिक रूप से लोहड़ी पर्व मनाया और अग्नि पूजन

की परंपरा निभाई। बिरला ने भारतीय संस्कृति और पर्वों की महत्ता बताते हुए कहा कि भारतीय त्योहार और सांस्कृतिक संवाद विश्वबंधुत्व, आपसी सम्मान और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं। बैठक में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच सौहार्द्रपूर्ण द्विपक्षीय संवाद हुआ, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय सहयोग, आपसी समझ को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बिरला ने कहा कि महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की विरासत दोनों देशों को लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समावेशन के मूल्यों से

जोड़ती है। ब्रिक्स और जी20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत-दक्षिण अफ्रीका सहयोग को दोनों लोकतंत्रों के बीच विश्वास और साझेदारी की मजबूत नींव बताया गया। संसदीय शिष्टमंडलों के नियमित आदान-प्रदान और विधायी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी सहमति व्यक्त की।बैठक में भारतीय संसद ने ग्रेनेडा की सीनेट अध्यक्ष डॉ. डेसिमा विलियम्स से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संसदीय वार्ता में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

भाजपा ने घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ममता पर साधा निशाना

टीएमसी अब ‘डेमोक्रेसी’ से हटकर ‘मोबोक्रेसी’ के रास्ते पर चलेगी: भाजपा

हरिभूमि न्यूज►► नई दिल्ली

भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर बार बार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कुचलने का आरोप लगाया है। पार्टी ने आईपैक पर ईडी की रेड रोकने की कोशिश, बीएलओ की आत्महत्या, उत्तरपारा गैंगरेप और महिला आयोग की सदस्य को धमकाने जैसी घटनाएं का जिक्र करते हुए कहा टीएमसी अब एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि अपराधियों को संरक्षण देने वाला माफिया 'मोबोक्रेसी' ने ले ली है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए ये बातें कही। सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी ने पिछले गुस्वार को

ईडी की पूरी प्रक्रिया को बाधित करते हुए, जिस तरह हिंसक रास्ता चुना, उससे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है कि टीएमसी अब 'डेमोक्रेसी' से हटकर 'मोबोक्रेसी' के रास्ते पर चलेगी। टीएमसी को जमीनी हकीकत का पूरा अंदाजा है कि किस तरह लोगों ने आक्रोश है और किस तरह एंटी-इन्कम्बेंसी चरम पर पहुंच चुकी है। सिन्हा ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में टीएमसी के कई बार यह प्रमाणित किया है कि उनका स्वभाव आधुनिक लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। जिस तरह टीएमसी ने बार-बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रौंदने का प्रयास किया है, उसी क्रम में पिछले 24 घंटों के

दौरान दो-तीन बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जो टीएमसी की हिंसात्मक प्रवृत्ति को भी दर्शाते हैं और यह दिखाते हैं कि किस प्रकार टीएमसी एक आधुनिक लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है? यह 6 दिनों से लगातार चल रहा है और इसमें एक-एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब ईडी ने आईपैक के दफ्तर में रेड की। टीएमसी स्वयं आईपैक को अपना पॉलिटिकल आर्म बताती रही है और कई वर्षों से आईपैक टीएमसी के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देख रही थी। ऐसे में जब आईपैक के ऑफिस में रेड हुई और इस बात की जांच शुरू हुई कि कोल घोटाले में सक्रिय मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से क्या आईपैक को भी

नेटवर्क का हिस्सा थी? इसी जांच के तहत ईडी कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान ममता कार्रवाई को रोकने का प्रयास करती हैं। सिन्हा ने कहा कि रेड के दौरान ममता वहां से कुछ फाइलें लेकर बाहर निकलती हैं, जो वर्ष 2022 की थीं, लेकिन आरोप यह लगा रही है कि उनके खिलाफ रेड इसलिए कराई गई ताकि 2026 के चुनाव की उनकी तैयारियों को भांपा और समझा जा सके। जबकि हकीकत यह थी कि जिन फाइलों के वे साथ लेकर निकली थीं, वे 2022 की थीं। पिछले 48 घंटों के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जो टीएमसी की मंशा पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। अब दो बड़े विषय सामने आए हैं। पहला,मुर्शिदाबाद का है,

जहां एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली।। टीएमसी ने इस मामले में भी यह आरोप लगाया कि उस बीएलओ पर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था और इलेक्शन कमीशन के दबाव के कारण उसे मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, वे इस दावे के बिल्कुल विपरीत हैं। हमीमुल इस्लाम बीएलओ अधिकारी के रूप में कार्यरत था। टीएमसी के एक स्थानीय नेता बुलेट खान ने उससे 20 लाख रुपए उधार लिए और बार-बार मांग करने के बावजूद पैसे वापस नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में हमीमुल इस्लाम गंभीर वित्तीय दबाव और उत्पीड़न में था, और उसी दबाव के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।

What is the sum of the numbers in the shaded cells?

9	6		1	4	8
	2			7	
4					2
			2		
				7	6
7			9		3
	8			4	
6		2		5	1



एक नजर में

दिसंबर में वनस्पति तेल आयात आठ प्रतिशत बढ़ा
नई दिल्ली: पिछले वर्ष दिसंबर में भारत का वनस्पति तेल आयात आठ प्रतिशत बढ़कर 13.83 लाख टन तक रहा है। साल्वेट एक्सप्रेटर्स एसोसिएशन (एएसईए) के अनुसार, यह वृद्धि सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के ज्यादा आयात के कारण हुई है। दिसंबर 2024 में 12.75 लाख टन वनस्पति तेल खरीदा था। इसमें खाद्य और गैर-खाद्य तेल शामिल है। पिछले महीने पाम तेल आयात 20 प्रतिशत घटकर 5.07 लाख टन रहा है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में, 6.32 लाख टन था। सूरजमुखी तेल का आयात 32.19 प्रतिशत बढ़कर 3.49 लाख टन रहा है। (भट्ट)

वेनेजुएला के घटनाक्रम का तेल कीमतों पर असर नहीं

नई दिल्ली: रेंटिंग एजेंसी क्रिसिल रेंटिस ने मंगलवार को कहा कि वेनेजुएला के हालिया घटनाक्रम का कच्चे तेल की कीमतों पर निकट भविष्य में कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। इसका कारण यह है कि वैश्विक आपूर्ति में इस लेटिन अमेरिकी देश की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है। क्रिसिल ने एक नोट में कहा कि अगर स्थिति बिगड़ती है और वेनेजुएला में कच्चे तेल उत्पादन में बाधा आती है, तो भी वैश्विक तेल कीमतों पर इसका असर सीमित रहने की संभावना है। (भट्ट)

चीथी तिमाही में 2.6% से कम रहेगी उपभोक्ता महंगाई

नई दिल्ली: यूनियन बैंक आफ इंडिया ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के दौरान औसत उपभोक्ता या खुदरा महंगाई 2.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। यह आरबीआइ के अनुमान 2.9 प्रतिशत से कम है। रिपोर्ट में अपने उस अनुमान को भी बरकरार रखा है जिसमें फरवरी या अप्रैल 2026 में रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटाती की संभावना जताई गई थी। बता दें कि दिसंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर 1.33 प्रतिशत रही है जो नवंबर 2025 की 0.71 प्रतिशत से ज्यादा है। (एफ्नाइ)

आरटीई के तहत 25% आरक्षण लागू करना राष्ट्रीय मिशन हो: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग (इंडब्ल्यूएस) के बच्चों को शिक्षा में प्रवेश देना ‘राष्ट्रीय मिशन’ होना चाहिए। कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे निजी गैर-अल्पसंख्यक, अनुसूच-रहित स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण के प्रविधान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्पष्ट नियम और विनियम तैयार करें। न्यायमूर्ति पीएम नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल पस चंद्रकर की पीठ ने कहा कि इंडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को प्रवेश देना संबंधित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का बायत है। पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक व्यक्ति ने शिक्षा वत की थी कि 2016 में सीटें उपलब्ध होने के बावजूद उसके बच्चों को आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा में प्रवेश नहीं मिला। (भट्ट)

बहुदिव्यांगता से जुड़ा रही महिला को तुरंत नौकरी दे कोल इंडिया : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोल इंडिया को बहुदिव्यांगता से जुड़ा रही महिला को तुरंत नौकरी देने का मौलवार को आदेश दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस कैवी विश्वनाथन की पीठ ने कोल इंडिया के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वह बहुदिव्यांगता से जुड़ा रही महिला सुजाता बोरा के लिए असम के तिबुसुकिम में मार्घेरिटा कार्यालय में सुपरन्यूमेरी (अतिरिक्त) पद सृजित करे और उसे नियुक्त करे। (भट्ट)

आरबीआइ ने यूसीबी को फिर से लाइसेंस देने का प्रस्ताव पेश किया

मुंबई: आरबीआइ ने मंगलवार को करीब 22 वर्ष बाद गहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए फिर से लाइसेंस देने का प्रस्ताव दिया है। यह कई रेग्युलेटरी जरूरतों के अधीन होगा, जिसमें 300 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी सीमा शामिल है। आरबीआइ ने 2004 में यूसीबी के लिए लाइसेंस देने पर रोक लगा दी थी। इसका कारण यह था कि नए लाइसेंस पाने वाले बैंकों में से बड़ी संख्या में कम समय में ही आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे। नए प्रस्ताव पर 13 फरवरी तक टिप्पणियां मांगी गई हैं। (भट्ट)

2025 में 44.90 लाख यात्री वाहनों की थोक बिक्री

जीएसटी सुधारों के कारण कीमतों में कमी ने यात्री वाहनों की थोक बिक्री को उच्च स्तर पर पहुंचाया

5 प्रतिशत बढ़ी पिछले कैलेंडर वर्ष में यात्री वाहनों की कुल थोक बिक्री

29,54,279 **यूटिलिटी वाहनों की डिलीवरी की कंपनियों ने डीलरों को**
2,05,00,639 **इकाई रही दोपहिया की थोक बिक्री पिछले कैलेंडर वर्ष में**
10,27,877 **इकाई रही वाणिज्यिक वाहनों की डिलीवरी वर्ष 2025 में**

सियाम के डाटा के अनुसार, पिछले वर्ष यूटिलिटी वाहनों की डिलीवरी 29,54,279 इकाई रही है जो 2024 में 27,49,932 इकाइयों की तुलना में सात प्रतिशत अधिक है। यात्री कारों की थोक बिक्री में मामूली वृद्धि हुई और यह 13,79,884 इकाइयों पर पहुंच गई, जबकि वैन की डिलीवरी में पिछले वर्ष 2024 की तुलना में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। तीन पहिया

पिछले वर्ष इलेक्ट्रानिक्स निर्यात चार लाख करोड़ रुपये के पार

नई दिल्ली, भट्ट : कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान भारत का इलेक्ट्रानिक्स निर्यात चार लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस वर्ष चार सेमीकंडक्टर संयंत्रों में उत्पादन शुरू होने से निर्यात में और वृद्धि की उम्मीद है।

आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्ट्रानिक उत्पादन लगभग 11.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जबकि निर्यात 3.3 लाख करोड़ रुपये के आसपास रहेगा। वैष्णव ने एक रिपोर्ट साझा की है, जिसमें कहा गया है कि भारत का आइफोन का निर्यात 2025 में 2.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा, जो 2024 में एपल द्वारा निर्यात किए गए 1.1 लाख करोड़

केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स मंत्री ने कहा, इस वर्ष चार सेमीकंडक्टर संयंत्रों में उत्पादन शुरू होने से निर्यात में और वदोतरी रहेगी

रुपये से लगभग दोगुना है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इलेक्ट्रानिक्स निर्यात नीतियों का सुविज करेगा और विदेशी मुद्रा लाएगा। उद्योग के अनुमान के अनुसार, इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में 25 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएशन के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के अंत तक देश में मोबाइल फोन उत्पादन 75 अरब डालर (लगभग 6.76 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें 30 अरब डालर या लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है।

तीसरी तिमाही में रही रिकार्ड थोक बिक्री

नई दिल्ली, आइएनएस: चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) के दौरान आटोमोबाइल उद्योग

का प्रदर्शन बेहतर शानदार रहा है। त्योहारी मांग और नीतिगत मदद के कारण बाती तिमाही में सभी प्रमुख वाहन श्रेणी में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री रही है। तीसरी तिमाही में यात्री वाहनों की बिक्री 20.6 प्रतिशत बढ़कर 12.76 लाख इकाई रही है, जो अब तक की सबसे अच्छी तिमाही बिक्री है।

के साथ रही और और उद्योग ने आपूर्ति पक्ष की चुनौतियों का सामना करना जारी रखा। आयकर रहत, लगातार रेपो दर में कटौती और जीएसटी 2.0 के कार्यान्वयन जैसे कई संरचनात्मक नीति सुधारों ने सकरात्मक मांग की नींव रखी। जीएसटी दरों में कमी ने वाहनों के अधिक सुलभ बनाया और क्षेत्र में नई गति का संचार किया। वर्ष के

सियाम के प्रेसिडेंट जैलेश चंद्र का कहना है कि 2025 भारतीय आटो उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। वर्ष की शुरुआत सुस्ती

बीसीसीएल के आइपीओ में 146 गुना आवेदन

नई दिल्ली, भट्ट : कोल इंडिया की सफिाडिल्वरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के आरंभक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) को निवेशकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस आइपीओ को सक्साक्रिशन के अंतिम दिन मंगलवार को कुल 146.81 गुना आवेदन मिले।

एनएसई के डाटा के अनुसार, इस आइपीओ में 34,69,46,500 शेयर बिक्री के लिए पेश किए गए थे। इसके सप्पेक्ष 50,93,44,51,200 आवेदन खरीदने के लिए आवेदन मिले हैं। योग्य संस्थगत खरीदारी (व्यूआइबी) श्रेणी में 310.81 गुना, गैर-संस्थगत निवेशक श्रेणी में 258.04 गुना और खुदरा व्यक्तिगत निवेशक श्रेणी में 49.26 गुना आवेदन मिले हैं। इस आइपीओ का आवक 1,071 करोड़ रुपये है और यह कैलेंडर वर्ष 2026 का पहला आइपीओ है।

राष्ट्रीय जागरण

सावरकर की तस्वीर हटाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इन्कार

नई दिल्ली, भट्ट : सुप्रीम कोर्ट ने संसद और अन्य सार्वजनिक स्थानों से विनाशक दामोदर सावरकर की तस्वीरें हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मंगलवार को इन्कार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को जुर्माना लगाने की चेतावनी दी, हालांकि याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची व जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने निरर्थक याचिका दायर करने के लिए, याचिकाकर्ता सेवनिवृत्त भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी बी. बालमुर्गन को चेतावनी दी कि अदालत का समय बर्बाद करने के लिए भारी लागत लगाई जा सकती है। बालामुर्गन ने याचिका में संसद के केंद्रीय कक्ष और अन्य सार्वजनिक स्थानों से सावरकर के चित्र हटाने का निर्देश देने की मांग की थी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, कुपया इन सब में न पड़ें। आप अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लें। परिणाम को भांपते हुए, बालामुर्गन ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन देने की तैयारी, उच्च स्तरीय समिति गठित

- पेंशन के लिए दिशानिर्देश और नियम बनाएगी समिति**
- इसमें कानून, वित्त, पूंजी बाजार, जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल**

एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। यह समिति नियमित पेंशन भुगतान पर स्थायी सलाहकार समिति के रूप में गठित की गई है। इसके मुख्य कार्यों में नियम बनाना, सुनिश्चित पेंशन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना, बाजार आधारित गारंटी यानी मार्केट के उतार-चढ़ाव के बावजूद सुनिश्चित पेंशन मिले पैसा मिले, इसका रास्ता खोजना।

जोखिम प्रबंधन करना शामिल है। सरकार ने पुरानी पेंशन को खत् कर साल 2004 में एनपीएस को पेश किया था। एनपीएस में जमा पैसों को इक्विटी, डेट और अन् एसेट में निवेश किया जाता है और इससे मिले रिटर्न को वापस खाते में जमा कर दिया जाता है। इसी बीच, राजकोट पर स्थायित दूसरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में पीएफआरडीए ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच एनपीएस के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाले सत्रों का आयोजन किया।

अब 2.71 लाख रुपये किलो के नए उच्च स्तर पर चांदी

नई दिल्ली, भट्ट : स्टाकिस्ट की ओर से लगातार खरीदारी के कारण घरेलू बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। आल इंडिया सरागन एसोसिएशन के अनुसार, मंगलवार को राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमतों में छह हजार रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब इसका मूल्य 2.71 लाख रुपये प्रति किलो के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को चांदी 15 हजार रुपये बढ़कर 2.65 हजार रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। इसी तरह, सोने के मूल्य में 400 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह 1.45 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। कैलेंडर वर्ष 2026 में अब तक चांदी 32 हजार रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। 31 दिसंबर 2025 को चांदी का मूल्य 2.39 लाख रुपये प्रति किलोग्राम था। बीते दो सत्रों में ही चांदी की कीमत 21 हजार रुपये बढ़ गई है।

करोबारी इस तेजी की वजह बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित संपत्तियों की मांग है। सोमवार को यह 4,586.49 डालर प्रति औंस हो गया है। सोमवार को यह 4,630.47 डालर प्रति औंस पर पहुंच गया था। हालांकि, चांदी 0.58 प्रतिशत बढ़कर 85.64 डालर प्रति औंस रही है।

करोबारी इस तेजी की वजह बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित संपत्तियों की

एसआइपी के जरिये पिछले वर्ष 3.34 लाख करोड़ रुपये का निवेश

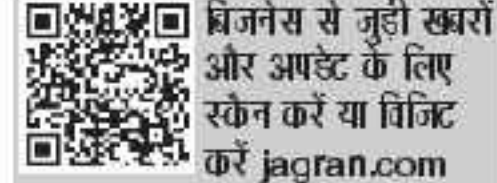
नई दिल्ली, भट्ट : सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स (एसआइपी) के जरिये 2025 में म्यूचुअल फंड में कुल निवेश 3.34 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह अनुशासित और लंबी अवधि में संपति सृजन के लिए निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के कारण संभव हुआ है।

एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अनुसार, एसआइपी के जरिये म्यूचुअल फंड में 2024 में 2.68 लाख करोड़ रुपये और 2023 में 1.84 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। दिसंबर में एसआइपी निवेश 31 हजार करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा है। 2025 के अंत म्यूचुअल फंड उद्योग का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 80.23 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो 2024 के अंत में 67 लाख करोड़ रुपये था।



- दिल्ली में दो दिन में 21 हजार रुपये किलो बढ़ी सफेद धातु**
- सोना 1.45 लाख रुपये प्रति ग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंचा**

लगातार मांग को बता रहे हैं। वैश्विक बाजारों की बात करें तो सोने में 10.93 डालर की गिरावट रही है और यह 4,586.49 डालर प्रति औंस हो गया है। सोमवार को यह 4,630.47 डालर प्रति औंस पर पहुंच गया था। हालांकि, चांदी 0.58 प्रतिशत बढ़कर 85.64 डालर प्रति औंस रही है।



एसआइपी के जरिये पिछले वर्ष 3.34 लाख करोड़ रुपये का निवेश

नई दिल्ली, भट्ट : सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स (एसआइपी) के जरिये 2025 में म्यूचुअल फंड में कुल निवेश 3.34 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह अनुशासित और लंबी अवधि में संपति सृजन के लिए निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के कारण संभव हुआ है।

एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अनुसार, एसआइपी के जरिये म्यूचुअल फंड में 2024 में 2.68 लाख करोड़ रुपये और 2023 में 1.84 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। दिसंबर में एसआइपी निवेश 31 हजार करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा है। 2025 के अंत म्यूचुअल फंड उद्योग का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 80.23 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो 2024 के अंत में 67 लाख करोड़ रुपये था।

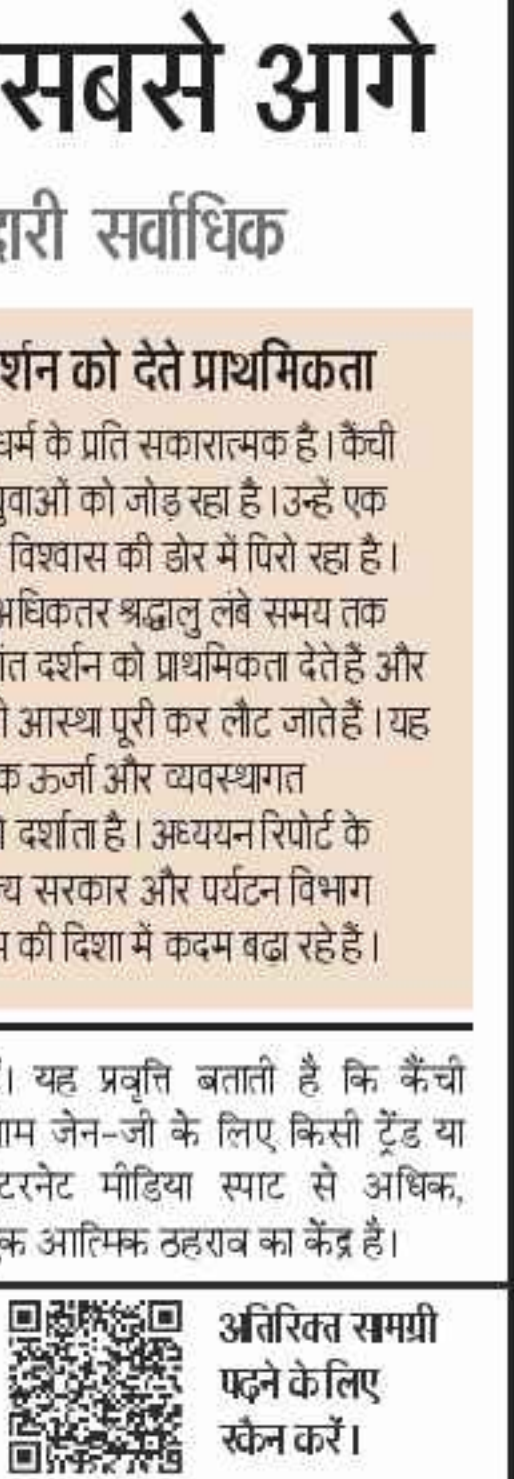
शब्बीर शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआइए को लगाई फटकार

नई दिल्ली, भट्ट : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह से जुड़े आतंकी फंडिंग मामले में अपना पक्ष ठीक से प्रस्तुत न करने के लिए एनआइए को फटकार लगाई और एजेंसी से छह साल से अधिक समय तक उनकी हिरासत को उचित ठहराने को कहा है। शब्बीर अहमद शाह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर भारत के पांच प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की थी और उनके भाषण ज्यादातर राज्य के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते थे।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ शब्बीर शाह की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने उन्हें आतंकी फंडिंग मामले में जमानत देने से इन्कार कर दिया था। शब्बीर शाह 2019 से हिरासत में हैं। पीठ ने एनआइए से उनके कुछ भाषणों और मामले से संबंधित तथ्यों को पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआइए को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। मामले की सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

कोशल विकास निगम घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू को वलीनचिट

अमरमठी, भट्ट : कोशल विकास निगम घोटाले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को रहत मिली है। विजयवाड़ा की एक अदालत ने निगम की धनराशि की हेराफेरी में संलिप्तता को लेकर नायडू के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को बंद कर दिया है। आरोप है कि इस हेराफेरी के कारण राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। मामले से उतके कुछ भाषणों और मामले से संबंधित तथ्यों को पेश करने के बाद एजेंसी ने यह कहते हुए रिपोर्ट दाखिल की कि नायडू की भूमिका के संबंध में ठोस सबूत नहीं हैं।



हजार श्रद्धालुओं के अंकिड़ों का विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन में यह तथ्य उभरकर आया कि धाम पहुंचने वालों में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवा 67.17 प्रतिशत हैं। यह वही पीढ़ी है जो सार्वजनिक मंचों पर अपने अधिकारी, सुविधाओं और जवाबदेही को लेकर मुखर रहती है,

साथ ही आध्यात्मिक संतुलन की तलाश में भी पीछे नहीं है। अध्ययन बताता है कि कैंची धाम की ख्याति अब सीमाओं से परे है। देश के अलग-अलग हिस्सों से ही नहीं, बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु सबसे अधिक हैं,



जिनकी भागीदारी लगभग एक-तिहाई के आसपास है। इसके बाद दिल्ली और बिहार का स्थान आता है। बिहार में भी बाबा के प्रति आस्था दिखाई देती है। नेपाल से लेकर नीदरलैंड तक से अनुयायी बढ़ी संख्या में दर्शन के लिए कैंची धाम पहुंच रहे हैं।

अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 95 प्रतिशत से अधिक श्रद्धालु केवल आध्यात्मिक उद्देश्य से ही धाम पहुंचे। अधिकांश ने स्वीकार किया कि उनका मुख्य लक्ष्य दर्शन और मन की शांति था, न कि पर्यटन। बढ़ी संख्या में श्रद्धालु एक ही दिन में दर्शन कर लौट जाते

प्रेरणा

जो व्यक्ति धैर्यवान है वह दुनिया की हर चीज हासिल कर सकता है। - जॉर्ज सेविल

संपादकीय

जर्मनी से मेलजोल का बढ़ना हमारे लिए अच्छा है

यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक-सामरिक शक्ति और दुनिया की फिलहाल तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी के साथ व्यापार और रक्षा समझौतों ने भारत के लिए नया विश्वास पैदा किया है और इसे अमेरिका के विकल्प के रूप में लिया जा रहा है। भले ही पनडुब्बी डील का जिक्र साझा बयान में न हो, लेकिन कुल 19 साझा घोषणाओं का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आगामी 27 जनवरी को भारत और 27 यूरोपीय देशों के संगठन वाले ईयू के बीच प्रो ट्रेड अग्रीमेंट पर अंतिम मुहर लगनी है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर दो मेहमान- ईयू आयोग की अध्यक्ष और ईयू परिषद के अध्यक्ष-मुख्य अतिथि होंगे। सामूहिक अर्थव्यवस्था वाले इस संगठन से एफटीए का मतलब है कि भारत अमेरिकी टैरिफ दवाब से काफी हद तक मुक्त हो जाएगा। जर्मनी भारत के टैलेंट को अपने यहाँ आकर्षित करना चाहता है। यूएस इससे असहज होगा। स्टील, हथियार और सेमी-कंडक्टर निर्माण की दिशा में जर्मनी से डील भारत के लिए हर मयने में हितकर साबित होगी। हालाँकि ईयू जानता है कि भारत रूस का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी और ईयू का भारत के करीब आना ट्रम्प के मनमाने रवैये के लगाम के रूप में लिया जा सकता है। ग्रीनलैंड पर कब्जे के मंसूबे के बाद अब यूएस से ईयू का मोहभंग हो चुका है और यह भी सच है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के बाद नाटो का अस्तित्व बेमानी हो जाएगा, क्योंकि तब वह डेनमार्क के हितों की रक्षा नहीं सकेगा।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com



बातचीत, सहयोग व एकांत से खत्म होता है अकेलापन

एक छत के नीचे कई सदस्य रहते हों तो भी उनमें से कुछ को लगता है कि हम अकेले हैं। घर के बाहर की दुनिया में लोकप्रियता हो, प्रतिष्ठा रहे, उसके बाद भी कुछ लोगों को लगता है हम अकेले हैं। जो लोग भीड़ से घिरे रहते हैं, उनको भी अकेलापन काटता है। तो समझ लें कि अकेलापन हलात नहीं, बीमारी है। और अकेलापन लंबे समय टिक जाए तो अवसाह आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अकेलेपन का इलाज तुरंत ही कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले यह समझें कि अकेलापन एक एहसास है। जितना महसूस करेंगे, यह उतना बढ़ता जाएगा। और यह भी तय है कि यह एहसास खत्म नहीं होगा। इस अनुभूति का मुंह मोड़ना पड़ेगा। तो पहला काम यह करिए कि दूसरों से दिल खोलकर बातें करिए। इससे हम हल्के हो जाते हैं, क्योंकि भीतर का भारीपन अकेलेपन का समर्थन करता है। दूसरा, लोगों की खूब सहजता कीजिए। सहयोग की वृत्ति अकेलेपन में आनंद भर देती है। और तीसरा काम करें कि अकेलेपन को एकांत से जोड़ें। अकेलापन हम दूसरों से भस्कर मिटाते हैं, एकांत में हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं।

•Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

पाठकों के पत्र

परीक्षा से ठीक पहले तबादले गलत

राजस्थान में मतदाता सुविधों के एसआईआर के बाद अब जब बोर्ड परीक्षाओं का समय निकट है तो शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाचार्यों व व्याख्याताओं के तबादले करना विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं। अनेक शिक्षकों का तबादला राजनीतिक द्वेष के चलते भी हुआ है। अगर शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही चलती रही तो शैक्षणिक विकास की बात बेमानी रह जाएगी। -मदनलाल लंबोरीया, गिरानी, राजस्थान

चाइनीज मांझे को लेकर और सख्ती हो

प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे के इस्तेमाल के चलते कुछ लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पुलिस और प्रशासन को इस बारे में और अधिक कठोर कदम उठाते हुए चाइनीज मांझा बेचने और उपयोग करने वालों के प्रति गंभीर रवैया अपनाना चाहिए। उन्हें ऐसा कठोरतम दंड देना चाहिए कि कोई चाइनीज मांझा बेचने और उपयोग करने का दुस्साहस न कर सके। -रमेशचंद्र कर्नविट, इंदौर, मध्य प्रदेश

फिर से मराठी अस्मिता का मुद्दा?

मनसे प्रमुख राज ठाकरे के मराठी एकता के आह्वान और हिंदी थोपे जाने के खिलाफ चेतवनी ने स्पष्ट कर दिया कि मनसे फिर उसी राजनीतिक राह पर जा रही है, जहां मराठी अस्मिता, बाहरी बनान स्थानीय का विमर्श और भाषा का प्रश्न चुनावी रणनीति का केंद्र रहा है। बीएमपी चुनाव तय करेगा कि मराठी अस्मिता का विमर्श सुरक्षा की सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ेगा या विरोध की नकारात्मक राजनीति की ओर। -क्यातिलाल मांडवत, सूरत, गुजरात

ट्रम्प के बयान अस्थिरता बढ़ा रहे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इंगन में सैन्य हस्तक्षेप के संकेत केवल कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह ताकत का अंतरराष्ट्रीय सहमति से ऊपर रखने की प्रवृत्ति का विस्तार है। वेनेजुएला को लेकर उनके दावे और खुद को वहां का कार्यवाहक राष्ट्रपति तक बताने वाली सोशल मीडिया पोस्ट ने इस प्रवृत्ति को और उचाड़ दिया है। ऐसे बयानों का असर वैश्विक राजनीति में भ्रम और अस्थिरता बढ़ाने वाला है। -सुभाष बुड़ावनवाला, रत्नाम, मध्य प्रदेश

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

ऑस्ट्रेलिया में जमीन के नीचे

घर बना कर रहते हैं लोग

ऑस्ट्रेलिया में एक अनोखा कब्जा है- कूबर पेडी। इस जगह पर आधा से ज्यादा आबादी जमीन के नीचे अपने घर बनाकर रहती है। कारण, गर्मियों के दिनों में इस इलाके का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस असहनीय गर्मी से बचने के लिए लोगों ने भूमिगत मकान बनाने का तरीका अपनाया है। मकानों के साथ ही यहां भूमिगत दुकानें, आर्ट गैलरी और चर्च भी हैं, जहां तपमान हमेशा 23 डिग्री के आसपास बना रहता है। कूबर पेडी मुख्यतः ओपल खदानों के लिए प्रसिद्ध है, जहां उच्च गुणवत्ता वाले कीमती रंगीन रत्नों का खनन होता है।

2500 के आसपास की आबादी है कूबर पेडी की। यहां अधिकतर आबादी ने जमीन से 4 मीटर तक नीचे जाकर अपने घर बनाए हैं।

बामुलाहिजा •

यैंत्यू मिस्टर ट्रम्प, हमें फ्री ट्रेड और आर्थिक सुधारों का डर छोड़ने का मौका देने के लिए

यह सुधारों को तेज करने का अवसर है

ट्रेड डील

शेखर गुप्ता

एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिंट'

✉@ShekharGupta



मेरा एक मन यह कहना चाहता है कि ‘शुक्रिया मिस्टर ट्रम्प, जो आप भारत के साथ व्यापार समझौते पर लगातार टालमटोली कर रहे हैं!’ क्योंकि आप ऐसा न करते तो यहां महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार फटाफट न किए जाते, जैसा 1991 के बाद अब तक नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए नए श्रम नियमों को ही ले लींजिए।

सरकार ने इससे पहले नया भूमि अधिग्रहण विधेयक, कृषि कानून, सबको वापस ले लिया था और जोखिम से बचने के लिए श्रम कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल रखा था। आर्थिक प्रशासन, मसलन सरकारी बैंकों को बेलेंस शीटों की सफाई, उनकी मजबूती और दिवालिया कानून आदि के मामले में कुछ सुधार जरूर किए गए। लेकिन इस बीच ‘सस्कार ही माई-बाप’ वाला संरक्षणवाद फिर लौट आया। टैरिफ में वृद्धि हुई और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के रूप में भारी-भरकम नॉन-टैरिफ सुल्हा दीवार खड़ी कर दी गई। भारतीय उद्योग के हर सेक्टर ने इनके लिए पैरवी की औरइन्हें हासिल कर लिया।

तेजतरंग भारतीय सिविल सेवाओं को मिलाकर बनी अंदरूनी मंडली ने ही इन्हें तैयार किया होगा। ट्रम्प शायद भारत की इन्हीं नॉन-टैरिफ बाधाओं का जिक्र कर रहे थे। दरअसल, इनका समय बीत चुका है। इन्हें अब हड़बड़ी से नहीं, तो मुस्तीदे से वापस किया जा रहा है। अनुभवी और भरोसेमंद अधिकारी इस वापसी परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान उन्हें और शक्ति दे !

लेकिन, ट्रम्प साहब आकाफि से शुक्रिया। शुक्रिया नरभी नहीं, बल्कि ऐसा अहंकार दिखाने के लिए कि आपने एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंध को सिर्फ इस हठ के लिए खराब कर लिया कि किसी ने आपको फोन किया था या नहीं! ट्रम्प न होते तो व्यापार से मुंह मोड़ने वाले हमारे सत्तातंत्र को ट्रेड डील के जादू का पता

नजरिया • दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं...

अमेरिका-यूरोप के गठजोड़

में टूट का हम फायदा उठाएं

कूटनीति

मिन्हाज मर्चेट

लेखक, प्रकाशक और सम्पादक
mmleditorial@gmail.com



डेनमार्क के समग्रभू क्षेत्र ग्रीनलैंड पर ट्रम्प की हमले की धमकी ने नाटो के सदस्य देशों के बीच सैन्य टकराव का खतरा पैदा कर दिया है। 32 सदस्यीय नाटो गठबंधन के अनुच्छेद-5 के तहत यदि किसी सदस्य देश पर हमला हो तो दूसरे सदस्यों को उसकी रक्षा करनी होती है। हालांकि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे नाटो सदस्य अमेरिका से टकराने का जोखिम शायद ही उठाएंगे।

लेकिन आखिर अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? क्योंकि इस आर्कटिक द्वीप की तीन बड़ी खूबियां हैं। पहली, आर्थिक : ग्रीनलैंड में पर्याप्त तेल और खनिज भंडार हैं। दूसरी, सुरक्षागत : ग्रीनलैंड रूसी और चीनी नौसेनाओं तथा उनके लड़कू विमानों पर लगातार गिरावनी रख सकता है, क्योंकि वे लगातार इस द्वीप के ऊपर से गुजरते हैं। तीसरी, लॉजिस्टिक्स सम्बंधी : ग्रीनलैंड यूरोप व एशिया के बीच कम समय लेने वाले आर्कटिक समुद्री मार्ग मुख्या करता है। ये व्यापार के साथ भविष्य के सैन्य अभियानों के लिए भी अहम है।

ट्रम्प कहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करेगा, चाहे सख्त रास्ता ही क्यों ना अपनाता पड़े। यूरोपीय देश इससे चिंतित हैं। ग्रीनलैंड की आबादी मात्र 57 हजार है, लेकिन उसके लोग अमेरिका का हिस्सा बनने के खिलाफ हैं। 18वां सदी से ही ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने अपना रुख साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड पर बलपूर्वक कब्जे की कोशिश नाटो के अंत की घोषणा होगी।

नाटो के सदस्य अन्य यूरोपीय नेताओं ने भी फ्रेडरिकसन का समर्थन किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि 'ग्रीनलैंड का भविष्य वहां के लोगों और डेनमार्क द्वारा ही तय किया जाएगा।' लेकिन ट्रम्प ने यूरोप की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। उन्हें तो अमेरिका-यूरोप गठबंधन के संभावित विघटन की भी ज्यादा चिंता नहीं है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही पश्चिम के तमाम भू-राजनीतिक सिद्धांतों का आधार रहा

न चला होता। अब तो ब्रिटेन और 'यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन' (ईएफटीए) के साथ व्यापार समझौता भी झोली में आ चुका है और ईयू के साथ भी समझौता होने वाला है। चीन को छोड़ (उसके लिए भी प्रतिबंधों को हटाना जा रहा है) 'आरसीईपी' (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी) का लगभग हर सदस्य देश साथ आ गया है। इसके बाद व्यापार को लेकर भारत का दिमाग भी बदल गया है। इसलिए मिस्टर ट्रम्प, आपको फिर से धन्यवाद !

किसी भी कम सीधे और कम आक्रामक कदम से अपनी पीठ खुद ठोकरे रहने वाला हमारा सत्तातंत्र सुकून की नींद लेने लगता। 7% की आर्थिक वृद्धि के साथ नाण्य मुद्रास्फीति दर, इसके साथ हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद और जनकल्याण की कार्यकुशल डिलीवरी का मेल जबरदस्त चुनावी फोर्मूला तो तैयार कर ही देता है। फिर अपनी नाव को जोखिम में क्यों डालें? लेकिन ट्रम्प ने हमें याद दिलाया कि बच-बच के खेलना कोई विकल्प नहीं है। इसलिए स्कोर बढ़ाओ, चाहे जो जोखिम हो !

यह तो उम्मीद की ही जा रही थी कि ट्रम्प व्यापार को अपनी नीति का औजार बनायेंगे। लेकिन भारत यह अनुमान नहीं लगा पाया कि वे टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। वैसे, सच कहें तो बक्की दुनिया भी यह अनुमान नहीं लगा पाई। भारत सबसे ज्यादा आमतुष्ट और व्यापार के प्रति उदासीन था और यह मान बैठा था कि ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में आपसी संबंध रणनीतिक हितों से संचालित होते रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत यह रणनीतिक पहलू हमारे लिए तब फलट गया, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान व्यापक हड़स में वापस पहुंच गया। मोदी और ट्रम्प के बीच सद्भावना का जो भी थोड़ा-सा पानी बचा था, वह 'मेरा नोबेल पुरस्कार कहाँ है?' की गरमी में भाप बनकर उड़ गया।

भारत उनके नाम की सिफारिश तो नहीं ही कर सकता था लेकिन हम पाकिस्तानियों को सबक सिखाते, इससे पहले ही उन्हें होश में लाने और युद्धविषम की यह बनाने के लिए ट्रम्प को धन्यवाद कहने पर विचार तो किया ही जा सकता था। इससे इनकार करना रणनीतिक भूल थी।

मेरा दूसरा मन इस बात को कबूल करता है कि यह जो

नजरिया •

अमेरिका-यूरोप के गठजोड़

में टूट का हम फायदा उठाएं

है। ट्रम्प के लिए अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र वाले पश्चिमी गोलार्ध का महत्व अटलांटिक महासागर के पार वाले पुराने यूरोप से कहीं अधिक है।

भू-भागों पर जबरन कब्जा करने का अमेरिका का लंबा इतिहास रहा है। अमेरिका में आए शुरुआती ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने वहां सदियों से रह रहे मूल अमेरिकियों से उनकी जमीन हथिया ली थी। आजादी के बाद अमेरिका ने 1846-48 में मैक्सिको से युद्ध लड़ कर कैलिफोर्निया और टेक्सास समेत उसकी आधी भूमि कब्जा ली थी। उससे पहले 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से लुइसियाना और 1867 में रूस से अलास्का खरीद लिया था। ऐसे में ग्रीनलैंड पर कब्जा करना भी उसके औपनिवेशिक डीएनए का ही हिस्सा है।

अमेरिका और यूरोप के बीच ऐतिहासिक रिसतों का कमजोर होना भारत के लिए भू-राजनीति के नए विकल्प खोलता है। 2030 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। भारत का 60

आज जब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप का पश्चिमी गठबंधन टूट रहा है तो भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हम आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में कस्टम ड्यूटी में और छूट दे सकते हैं।

करोड़ मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं का बाजार अमेरिका और ईयू के कुल उपभोक्ता बाजार से भी बड़ा है। चीन में अहम तकनीकी उद्योगों से बहिष्कृत और अमेरिका का भी टैरिफ का सामना कर रही यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत का यह विशाल बाजार एक अद्वितीय पेशकश करता है। हालांकि, भारतीय उपभोक्ताओं की खरीद-शक्ति अभी सीमित है, लेकिन उनकी खर्च योग्य आय अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के उपभोक्ताओं की तुलना में तेजी से बढ़ रही है।

आज जब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका-यूरोप का पश्चिमी गठबंधन टूट रहा है तो भारत को इस मौके का फायदा उठाते हुए 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में कस्टम ड्यूटी में और छूट देनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि इस निर्णायक दौर में आर्थिक सुधारों की रफ्तार और तेज कर दी जाए।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

डिफ्रेंट एंगल • ‘रिस्पॉन्सिबल एआई’ यानी कृत्रिम मेधा की जवाबदेही पर भी अब होने लगी हैं चर्चाएं

कहीं हम अपनी ही पृथ्वी पर ‘सेकंड सिटीजन’ ना बन जाएं!

एआई

नन्दितेश निलय

वक्ता, एथिक्स प्रशिक्षक एवं लेखक
nanditeshnilay@gmail.com



अगर हम पिछले साल और इस साल के बीच उस परिघटना को ढूंढने की कोशिश करें, जिसका 2026 और आने वाले वर्षों में और भी प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप होने जा रहा है तो वह एआई है। इस हस्तक्षेप का साक्षात्कार तो पर ही में हो जाता है। बोर्ड, नीट, जेईई या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करता छात्र अब कोई ओढ़ा हुआ मीन नहीं पालता, बल्कि एआई से दिनभर बातें करता रहता है। उसके शिक्षक या परिवार के सदस्य उसके प्रश्नों का उत्तर देने में समय लगा सकते हैं, यहां तक कि खीझ भी सकते हैं, पर एआई तनिक भी नहीं झुंझलाता। वह अभिव्यक्त का जवाब अभिवादन से देता है। उसके माध्यम से ‘मेटावर्स’ की

वस्तुअल दुनिया वास्तविक नजर आती है। वह नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाता, बल्कि यूजर्स के लिए कुछ भी ढूंढ लाने के लिए सेवाभाव से तैयार रहता है।

ऐसे में युवावल हयरी को इस बात की चिंता होती है कि क्या हम हमो सेंपेंस या बुद्धिमान श्रृंखला की अंतिम पीढ़ी हैं? अगर पढ़ना-लिखना, सोचना-समझना, प्रश्न करना-उत्तर तलाशना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बाजार आदि क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में सारे कार्य एआई ही करेगा तो हमारी क्या उपयोगिता रह जाएगी? कहीं हम अपनी ही पृथ्वी पर सेकंड सिटीजन तो नहीं बन जाएंगे?

जिस तरह से एआई सूचना की शक्ति का केंद्र बन बैठा है और हमें धीरे-धीरे भावनात्मक रूप से भी अपनी दुनिया में समेट रहा है, तो चिंता तो होनी ही चाहिए। एआई की दुनिया के विशेषज्ञ भी इसके खतरे को समझ रहे हैं और ‘रिस्पॉन्सिबल एआई’ पर गहन चर्चा शुरू हो चुकी है। ऐसे में भारत में भी एआई दक्षता को शैक्षणिक और आर्थिक विकास का अहम हिस्सा बनाने के



इस तरह का मौका पीढ़ियों में एकाध बार ही आता है...

आज दुनिया बदली हुई है और यह नया भारत है। आज भारत आर्थिक और रणनीतिक रूप से अमेरिका तथा वैश्विक व्यवस्था से बहुत जुड़ चुका है। ऐसे में ठोस आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ऐसा संकट पीढ़ियों के बीच एकाध बार ही आता है।

संकट जारी है, वह कम वेतन वाले लाखों रोजगारों को किस तरह खत्म कर रहा है और बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाले मछली पालन, गार्मेंट्स, होजियरी, रत्न और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब तक ये क्षेत्र कुछ तो सरकार की मदद से और कुछ अपनी अब तक की रफ्तार के बूते बचे रहे हैं। लेकिन तीन महीने और बीतने के बाद इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छंटी हो सकती है। इसलिए भारत इसे लंबे समय तक नहीं झेल सकता। समाधान ढूंढने पड़ेंगे।

इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ट्रम्प के सामने गिड़गिड़ाए, जिसकी अपेक्षा वे जिनिफिंग और पुतिन को

मुद्दा • कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा का सवाल

रात की शिफ्ट में काम करने

वाली स्त्री को क्या डराता है?

आधी आबादी

मेघना पंत

पुरस्कृत लेखिका, पत्रकार-वक्ता
meghnapanat@yahoo.com



नए श्रम कानून सुधारों ने महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी है। लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि महिलाएं रात में काम कर सकती हैं या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या हम अब उन्हें काम करते समय सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? क्योंकि सुरक्षा को केवल महिलाओं के साहस पर छोड़ दिया जाए, तो ये सुधार असफल हो जाएंगे।

सुरक्षा के उपाय न तो नारे हो सकते हैं और न ही दफ्तरी संकुलन। वे व्यावहारिक, लागू किए जाने योग्य और गैर-समझौतावादी होने चाहिए। वास्तविक सुरक्षा का मतलब है अनिवार्य एस्कॉर्ट नीतियां- कैवल्रिफक नहीं, मांगे जाने पर नहीं- बल्कि अनिवार्य। इसका यह भी अर्थ है कि ‘लाइट-महल’ तक सुनिश्चित परिवहन। इसमें वेरिफाइड ड्राइवर, जीपीएस से ट्रैक किए जाने वाले वाहन, बदलते रूट्स, रेशन पार्किंग परिया और निष्कास मार्ग शामिल हैं। पैनिक्-बटन सजावट के लिए नहीं होने चाहिए, वे पुलिस और आंतरिक प्रतिक्रिया टीमों से सीधे जुड़े हों। आपातकालीन एप महानगरों के डेमो तक सीमित न रहें; वे दूसरे राज्यों में भी काम करें। शिकार्यत अधिकारी 24 बाय 7 उपलब्ध हों और सुरक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो।

और सबसे अहम बात- जवाबदेही स्पष्ट हो। अगर किसी महिला को क्षति पहुंचती है तो इसके लिए निवेदना सिर्फ ‘चिंतित’ नहीं हो सकता। उसकी जिम्मेदारी तय हो। क्योंकि हकीकत यही है कि रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिला को एक्सेल शीट से डर नहीं लगता, उसे डर लगता है यात्रा से। वाहनों के इंटरजन से। मदद के लिए पुकारने के बाद छा जाने वाली खामोशी से।

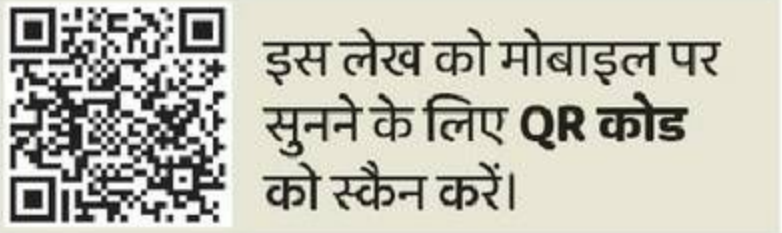
लेकिन सुरक्षा भी तस्वीर का एक हिस्सा ही है। कामकाजी महिलाओं को किफायती चहारूडकेयर की भी जरूरत है, ताकि मातुत्व उनके करियर को समाप्त कर देने वाली घटना न बन जाए। लचीले वर्क-मॉडल अपराधबोध से भरे अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य व्यवस्था होने चाहिए। महिलाओं के लिए नौकरियां

छोड़ दुनिया के हर नेता से रखते हैं। लेकिन भारत उन कई मामलों में ज्यादा लचीला रख अपना सकता है, जो ट्रम्प के लिए काफी संवेदनशील हैं। उदाहरण के लिए, उनकी फार्म लॉबी। मैं जानता हूं कि भारत में इसका स्वाभाविक विरोध इस डर के कारण होता है कि यह भारतीय कृषि का सफाया कर देगा या यहां उन ‘जीएम’ उत्पादों की बाढ़ ला देगा, जिन पर भारत ने रोक लगा रखी है (जिसे मैं लंबे समय से अनुचित मानता रहा हूं)।

आक्रामक हुए बिना भी रास्ता निकाला जा सकता है। जरा देखिए कि छाका में अमेरिकी दूतावास वहां मात्र 58,000 टन मक्के की आमद पर कितना खुश है। यह मुर्गियों का चारा है। भारत भी मुख्यतः मुर्गियों के लिए ही चारे का आयात करता है। केवल थैरैनील बनाने या चारे के लिए मक्का आयात करने में क्या दिक्कत है? अब यह मत कहिए कि हम अपनी मुर्गियों को ‘जीएम’ वाला चारा नहीं खिला सकते। ‘जीएम’ कपास की भूरी हमारी मवेशियों का प्रमुख चारा है। और इससे निकाला जा रहा तेल हमारी ‘फूड चेन’ में 23 वर्षों से मौजूद है।

पुरी दुनिया ट्रम्प से निबटने के उपाय तलाश रही है। अब तक तो आप उनके तीर-तरीके और शैली को समझ ही चुके होंगे। बिना प्रचार किए उन्हें कुछ अहनिंकर जीत का श्रेय लेने दिया जा सकता है। कुछ शोर हो सकता है और टक्कर भी हो सकती है, जैसी इंदिरा और नक्सन के बीच हुई थी। लेकिन वह दूसरा दौर था। तब शीतयुद्ध चरम पर था। आज दुनिया बदली हुई है और यह नया भारत है। आज भारत आर्थिक और रणनीतिक रूप से अमेरिका तथा वैश्विक व्यवस्था से बहुत जुड़ चुका है। ऐसे में ठोस आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ऐसा संकट पीढ़ियों के बीच एकाध बार ही आता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)



इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।



सिर्फ गुजर-बसर नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा का भी साधन हैं। और निर्णय लेने वाली मेजों पर महिलाओं की मौजूदगी भी अनिवार्य है, क्योंकि जिन शहरो, परिवहन प्रणालियों और दफतरो की डिजाइन महिलाओं के बिना की जाती है, वे कभी महिलाओं को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। यह महिलाओं को रात में काम के लिए मजबूर करने का सवाल नहीं है। यह महिलाओं को वास्तविक विकल्प देने का सवाल है- ऐसे विकल्प, जिन्हें अच्छे बुनियादी ढांचे, कानूनों के सख्त अमल और मानवीय गरिमा का समर्थन प्राप्त हो।

महिलाओं की सुरक्षा एक आर्थिक मुद्दा भी है। जब महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं तो वे काम से बाहर हो जाती हैं। जब वे काम करना छोड़ती हैं, तो परिवारों की आय घटती है। और जब परिवारों की आय घटती है, तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। भारत अपने कार्यबल के आधे हिस्से को शांति के शांति लिए बिना 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता।

एक अरसे से हम महिलाओं के रोजगार के सवाल को पाबंदियों के जरिये हल करते आ रहे हैं- यह कि देर तक काम मत करो, कहीं दूर काम करने मत जाओ, जोखिम मत लो। नए श्रम कानून सुधार इस स्थिति को बदल सकते हैं?

यह साल 2026 है और आज भी भारतीय महिलाओं में से केवल लगभग एक-तिहाई ही श्रमबल में भाग लेती हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा लगभग तीन-चौथाई है। इन एक-तिहाई कामकाजी महिलाओं का अधिकांश हिस्सा भी अनौपचारिक और असुरक्षित नौकरियों में है और आर्थिक झटकों के समय सबसे पहले उन्हीं पर चोट पड़ती है। स्नातकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 51% होने के बावजूद- मैकिन्से के एक अध्ययन के अनुसार- भारत में वे एंटी-लेवल भूमिकाओं में 29% ही हैं। वरिष्ठ प्रबंधन में तो यह संख्या घटकर 9% रह जाती है और सीईओ स्तर पर तो यह 1% से भी कम है। आश्चर्य नहीं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जेंडर समानता के मामले में भारत को 153 देशों में 112वां स्थान दिया है। ये हालात बदलने चाहिए।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

करने के लिए डिजाइन की गई एआई सेवाओं पर निगरानी को सख्त करेंगे। इस ड्राफ्ट में एक रगुलेटरी तर्कका यह भी बताया गया है, जिसके तहत प्रोवाइडर्स को यूजर्स को ज्यादा इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देनी होगी और यूजर्स में लत के संकेत दिखें तो दखल भी देना होगा। उन एआई प्रोवाइडर्स को यूजर्स की मानसिक और भावनात्मक स्थिति की पहचान करनी होगी। अगर यूजर्स में भावनात्मक अस्थिरता पाई जाती है तो प्रोवाइडर्स को दखल देने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। एआई को रगुलेट करना आज सबसे महत्वपूर्ण हो चला है। ग्रेक को लेकर भारत सरकार सख्त होती दिख भी रही है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुल-मिलाकर तो तो एक मशीन ही, जो डेटा से संचालित होती है। उसमें मानवीय भाव और बोध तो है नहीं। बुद्धिमान होना, भावुक होना इंसानी गुण हैं। तो हम एआई को कौमूर्यों की जगह क्यों लेने दें?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आज का पंचांग

पंडित प्रो. विनोद शास्त्री

तिथि संवत् : माघ, कृष्ण पक्ष एकादशी, बुधवार सायं 05:53 तक रहेगी। विक्रम संवत् 2082, शके 1947, हिजरी 1447, मुस्लिम माह रज्जब, तारीख 24, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, 14 जनवरी।

सूर्योदय कालीन नक्षत्र : अनुराधा नक्षत्र रात्रि 03:04 तक, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। गंड योग सायं 07:56 तक, इसके बाद वृद्धि योग रहेगा। बालव करण सायं 05:53 तक, इसके बाद कौलव करण रहेगा।

ग्रह विचार (प्रातः 05:30) : सूर्य-धनु, चंद्र-वृश्चिक, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरु-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुंभ, केतु-सिंह राशि में स्थित है।

राहुकाल : दोपहर 12:00 से 01:30 तक रहेगा।

दिशाशूल : उत्तर दिशा : यदि जरूरी हो तो मिश्री या सीफ खाकर यात्रा कर सकते हैं।

शुभाशुभ ज्ञानम : मकर संक्रांति, सूर्य मकर में प्रवेश दोपहर 03:07, पुण्यकाल प्रातः 08:43 से संपूर्ण दिन, बटितला एकादशी व्रत, मकर संक्रांति पर्व, गंगा सागर स्नान व यात्रा, धनु मलमास समाप्त, पौर्णल दक्षिण भारत में, माघ बिहु आसाम, गंडमूल प्रारंभ रात्रि 03:04 से

चौधडिया मुहूर्त : प्रातः 07:21 से 09:59 तक लाभ व अमृत का, प्रातः 11:17 से दोपहर 12:36 तक शुभ का, दोपहर 03:13 से 04:31 तक चर का, सायं 04:31 से 05:50 तक लाभ का चौधडिया रहेगा।

आज विशेष : आज मकर संक्रांति, अयन संक्रांति है। इस संक्रांति में पुण्यकाल 40 घटी बाद का होता है लेकिन सायंकाल संक्रांति होने से इस दिन प्रातः 08:43 से संपूर्ण दिन पुण्यकाल रहेगा। इस दिन गर्म वस्तुओं, कंबल, तिल, गुड़ एवं अंगिन का दान विशेष फलदायी होता है। बुधवार को गणेशजी की गंध, फल, पुष्प, दूध, दही, घी, दूदा, धूप और दीप आदि से पूजा करें। मोदक का भोग लगाने से बुध जनित दोष दूर होते हैं और रिद्धि-सिद्धि की प्राप्ति होती है। आज गंड योग में नमक का दान करना शुभ फलदायी होता है।

आज जन्मे बच्चों के नामाक्षर व राशि				
समय	नक्षत्र	चरण	पाया	राशि नामाक्षर
07:21	अनुराधा	2	ताम्र	वृश्चिक नी
13:36	अनुराधा	3	ताम्र	वृश्चिक नू
20:20	अनुराधा	4	ताम्र	वृश्चिक ने
03:04	ज्येष्ठा	1	ताम्र	वृश्चिक नो

मैनैजमेंट फंडा

एन. रघुरामन

मैनैजमेंट गुरु, raghu@dbcorp.in

सिर्फ पानी ही नहीं, आपके लिए सुरक्षित वाई-फाई भी जरूरी है

हाल ही में मेरी इंडीय यात्रा में मुझे पूछा गया कि 'क्या मैं आपको पीने के लिए पानी दूँ?' मैंने 'नहीं' कहा। वजह पानी में मिलावट की खबरें नहीं थीं, बल्कि बाहर ठंड थी और सच में मेरा पानी पीने का मन नहीं था। मेजबान ने मजाक में कहा कि 'हमारा पानी सुरक्षित है।' मैंने हंसकर कहा कि 'आज का दौर हमें पानी से ज्यादा वाई-फाई सुरक्षित रखने की चेतावनी देता है। मेहमाननवाजी में अब वाई-फाई पहले नंबर पर आ गया है और पानी दूसरे नंबर पर।' मेजबान ने भी सहमत होकर कहा कि 'हां, आप सही हैं। आजकल हर मेहमान पहले वाई-फाई पासवर्ड पूछता है। कभी मेहमाननवाजी में सबसे ऊपर होने वाला पानी अब दूसरे नंबर पर आ गया है।' यहीं से हमारी चर्चा शुरू हुई कि आज के समय में गेस्ट वाई-फाई नेटवर्क की जरूरत क्यों है? और इसका जवाब यह है।

वाई-फाई पासवर्ड : किसी को यह चाहिए, कोई पूछता है और कोई शेरार कर देता है। सच में तो आज के डिवाइसेस ने इन लॉगिन्स को शेरार करना आसान बना दिया है। बस, किसी के पास खड़े हों और आपके गैजेट्स उनके नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। लेकिन यह खतरनाक है। इसलिए नहीं कि मेहमान की मंशा गलत है, बल्कि जब आपका नेटवर्क उनसे जुड़े तो अनजाने में कुछ ऐसा डाउनलोड हो सकता है, जो आपके पूरे सिस्टम को संक्रमित कर दे।

आजकल अधिकतर घरों में सिर्फ फोन ही नहीं, बल्कि प्रिंटर, टीवी, कैमरे, डोबेल्ड तक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। कई संजघ घरों में तो वॉशिंग मशीन, स्पीकर और एलेक्सा जैसे असिस्टेंट भी जुड़े होते हैं, ताकि रोजमर्रा के काम आसान हो सकें। ज्यादातर मेहमानों को आपके घर के अन्य गैजेट्स का नहीं, सिर्फ इंटरनेट का एक्सेस चाहिए होता है। लेकिन नेटवर्क से जुड़े गैजेट्स बिना पूछे एक्सेस दे देते हैं। इसलिए अलग गेस्ट वाई-फाई नेटवर्क न सिर्फ मेहमानों को इंटरनेट की सुविधा देता है, बल्कि मेहमानों के जाने के बाद आप पासवर्ड भी बदल सकते हैं। घर के अन्य गैजेट्स को डिस्टर्ब किए बिना ऐसा आप कितनी ही बार कर सकते हैं।

गेस्ट वाई-फाई नेटवर्क कैसे सेटअप करें? चूंकि अलग-अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इसलिए सभी पर लागू होने वाला कोई एक दिशानिर्देश नहीं है। नेटवर्क सेटिंग्स में सर्विस प्रोवाइडर का एप इसे शुरू करने का बेहतर स्थान होता है। अगर वहां गेस्ट नेटवर्क का विकल्प न मिले, तो अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से वेब सर्च करें। आप अपने राउटर के बिल्ट-इन फीचर का इस्तेमाल कर रेगुलर केबल इंटरनेट से आसानी से एक अलग गेस्ट वाई-फाई नेटवर्क बना सकते हैं, जो मेहमानों को इंटरनेट देता है और आपके मुख्य नेटवर्क व डिवाइसेस को सुरक्षित और प्राइवेट भी रखता है। इसके लिए बाउजर या एप के जरिए राउटर की सेटिंग्स में जाएं, 'गेस्ट नेटवर्क' विकल्प चालू करें। इसका यूनिक नाम और पासवर्ड सेट करें और सेटिंग्स को अपडेट कर दें। इसमें अक्सर बैकवर्ड्स लिमिटेड और डिवाइस आईपेस के विकल्प भी होते हैं। तो इसे कैसे करें? राउटर सेटिंग्स में जाएं। वेब ब्राउजर में राउटर का आईपी एड्रेस डालें (जैसे 192.168.1.1) या फिर अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) एप इस्तेमाल करें।

1. 'गेस्ट नेटवर्क' या 'गेस्ट वाई-फाई' विकल्प ढूंढ़ें और ऑन करें, जो आमतौर पर वायरलेस या एडवांस्ड सेटिंग्स में होता है।

2. इसे अलग नाम दें, जैसे 'घोर होम गेस्ट' और मजबूत पासवर्ड बनाएं।

3. क्लाइंट आईसोलेशन चालू करें, ताकि मेहमान आपके निजी डिवाइसेस को एक्सेस ना कर सकें। मुख्य नेटवर्क को तेज रखने के लिए कुछ लोग गेस्ट नेटवर्क स्पीड कम भी कर देते हैं।

4. ये बदलाव अप्लाय करें और जांच लें। अगर समझ नहीं आए तो सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके मदद लें।

फंडा यह है कि सुरक्षित पानी पीना तो हम सब जानते हैं, लेकिन वाई-फाई पासवर्ड के मामले में वही सेपटी फीचर हम भूल जाते हैं। चूंकि वाई-फाई आज हमारे जीवन में अधिक जरूरी हो गया है तो इसे सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना सुरक्षित पानी पीना।

हत्यारी नातिन को 7 साल की सजा, नाना को नौद की दवा खिलाकर प्रेमी संग भाग गई थी

खातिर | नाना व अन्य परिवर्जनों को मैगी में नौद की दवा मिलाकर खिलाने वाली नातिन काजल सखवार को न्यायालय ने 7 साल के कारावास की सजा दी। हृदय व टीबी रोग से पीड़ित नाना किशनलाल ने घटना के 3 दिन बाद मौत हो गई थी। काजल को गैर इरादत हत्या का दोषी ठहराया गया, जबकि उसके प्रेमी गौतम को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला पुलिस थाना सिरोल का है। 28 जुलाई 2023 को रात्रि 8 बजे के लगभग सोनू अपने घर पहुंचा तो देखा कि पिता सो रहे हैं। काजल ने मामा सोनू से कहा कि नाना किशनलाल भोजन खाने के बाद ही सोने चले गए। आप और नानी भी भोजन कर लें।

राशिफल

मेष वाले आध्यात्मिक कार्यों में समय व्यतीत करेंगे, वृष वालों का भाग्योदय

मेष शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी : पूजा-पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में समय व्यतीत होगा। प्रॉपर्टी में निवेश के अवसर मिलेंगे। भाग्यवत्ता में लिए फैसले मुश्किल में डाल सकते हैं। आपसी तालमेल से आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी।

वृष शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल : पुनः झगड़े सुलझने से रहत मिलेगी। नई योजनाओं की शुरुआत लाभ दिला सकती है। भाग्योदय के अवसर मिलेंगे। नए संपर्क में सावधानी बरतें। परिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं।

मिथुन शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद : महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा की स्थिति बनी रहेगी। राजकाज में आ रही बाधा दूर होगी। मित्रों के व्यवहार से खिन्नता बढ़ेगी। प्रॉपर्टी में निवेश सोच-समझकर करें, धोखा हो सकता है।

कर्क शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला : मित्रों के सहयोग से मुश्किल दूर होगी। परिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए यात्रा संभव है। सामाजिक जीवन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। राजकीय मामले सुलझ सकते हैं।

सिंह शुभ अंक 3, शुभ रंग बादामी : कार्यस्थल पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुख-सुविधा पर खर्च की संभावना है। भावनात्मक संबंधों में निकटता बढ़ेगी। तरक्की व झिञ्झत पद मिलने की उम्मीद है। धैर्य रखें।

कन्या शुभ अंक 9, शुभ रंग नारंगी : कानूनी मामलों में सावधानी बरतें। कार्यस्थल पर कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं। विवादास्पद मामले सुलझने के आसार हैं। संतान के भाग्योदय से प्रसन्नता मिलेगी। अटकल धन मिल सकता है।

तुला शुभ अंक 4, शुभ रंग आसमानी : मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा। विरोधियों को अपनी बात समझाने में सफल रहेगी। प्रॉपर्टी के क्रय-विक्रय से लाभ संभव है। अनुभवी लोगों का साथ कार्यक्षेत्र में तरक्की दिला सकता है।

वृश्चिक शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला : विवादास्पद मसले सुलझने से रहत मिलेगी। मित्रों से मुलाक़ात होगी। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। नए लोगों से संर्क कैरियर को बढ़ावा देगा। समय पर काम पूरा करने का दबाव रहेगा।

धनु शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा : छोटे-छोटे झगड़े बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। परिणय चर्चाओं में सफलता मिलेगी। धैर्य के साथ आगे बढ़े कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। दौड़धूप के चलते स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।

मकर शुभ अंक 8, शुभ रंग स्लेटी : भय की स्थिति बनी रहेगी। अपनी बातों पर अडिग रहें सबका सहयोग मिलेगा। अनुभवी लोग आपके काम में मदद करेंगे। आय-व्यय में तालमेल की कमी परेशान करेगी। नए सौदे मिल सकते हैं।

कुंभ शुभ अंक 5, शुभ रंग काला : राजनीति से जुड़े लोग पद व प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं। दूसरी की बातों में आकर अपनी की विरोधी बना लेंगे। करोबारी विस्तार के लिए समझौता करना लाभदायक रहेगा। धर्म में रुचि बढ़ेगी।

मीन शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा : विवाद से दूर रहें नुक़सान हो सकता है। परिवारिक संबंधों में टकराव की स्थिति बनेगी। लेन-देन के मामलों में आरोप लग सकते हैं। तनाव से छुटकारा मिलेगा। सझेदारी टूटने से नुक़सान संभव है।

मकर संक्रांति आज : संयम, सहयोग और सामूहिकता के संदेश का पर्व

जीवन को दिशा देने वाला चेतना उत्सव मकर संक्रांति



हेमंत कासट
ज्योतिष और वैदिक विषयों के जानकार



दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ मकर संक्रांति का पर्व आरंभ होगा। यह पर्व धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ज्योतिष, आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का गहरा समन्वय छिपा हुआ है। भारतीय वैदिक परंपरा में सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि काल, कर्म और चेतना के अधिष्ठाता माने गए हैं। सूर्य के बारह स्वरूपों को 12 आदित्य कहा गया है, जिनका सीधा संबंध वर्ष के 12 महीनों और सूर्य की संक्रांतियों से है। इन्हीं संक्रांतियों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। यह वह खगोलीय क्षण है, जब सूर्य धनु

12 आदित्य सूर्य की 12 चेतन शक्तियां हैं

12 आदित्य सूर्य की 12 चेतन शक्तियां हैं, 12 माह उनका कार्यक्षेत्र है और मकर संक्रांति वह दिव्य बिंदु है जहां काल, प्रकृति और मानव चेतना एक साथ ऊर्ध्वगामी होती है। इसलिए मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला चेतना उत्सव है। वेदों और पुराणों के अनुसार मित्र, वरुण, अर्यमन्, भग, अंश, धाता, इन्द्र, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु-ये बारह आदित्य वर्ष के बारह महीनों में क्रमशः पृथ्वी पर प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक आदित्य सूर्य की विशिष्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऋतु परिवर्तन, कृषि, मानव शरीर और मन की अवस्था को प्रभावित करती है। 12 माह समय की इकाई ही नहीं, बल्कि सूर्य-चेतना के 12 चरण हैं।

मानव शरीर के 12 ऊर्जा द्वारों के प्रतीक आदित्य

आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो 12 आदित्य मानव शरीर के 12 ऊर्जा द्वारों के प्रतीक हैं। मकर संक्रांति इन ऊर्जाओं के ऊर्ध्वगमन का पर्व है। इसी कारण इस दिन स्नान, दान, जप, तप और साधना का विशेष महत्व बताया गया है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- 'आदित्यानामहं विष्णुः' यानी आदित्यों में मैं विष्णु हूं। यह वाक्य सूर्य-तत्त्व में नारायण की व्यापक सत्ता को दर्शाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से मकर संक्रांति मानव मन को आलस्य से सक्रियता की ओर ले जाती है।

दाखिले के नाम पर चल रहे संगठित फर्जीवाड़े के सिंडिकेट का खुलासा

एमबीबीएसमेंप्रवेशकेलिए कोलकाता चंडीगढ़-बनारस में बनवाए प्रमाणपत्र

मनोहर कुमार | पूर्णिया

मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर चल रहे एक संगठित फर्जीवाड़े के सिंडिकेट का परत दर परत खुलासा हो रहा है। जांच में सामने आया है कि दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों ने कोलकाता, चंडीगढ़ और बनारस जैसे शहरों से फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाए थे। जीएमसीएच पूर्णिया में सात मामले सामने आए हैं जिसके दिव्यांगता सर्टिफिकेट फर्जी मिले हैं। यह अंतरराज्यीय फर्जी सर्टिफिकेट सिंडिकेट की ओर इशारा कर रहा है। मेडिकल कॉलेज में सीतामढ़ी निवासी एमबीबीएस छात्र कार्तिक यादव को तीन महीने से लगातार ऑब्जर्व किया जा रहा था। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के दौरान उसने कान से विकलांग होने का फर्जी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था। दस्तावेजों की बारीकी से जांच और उसके क्रियान्वलों को वाँच करने के बाद सच्चाई सामने आया कि वह स्वस्थ है। सूत्रों का कहना है कि कार्तिक सिर्फ एक चेहरा है, जबकि इसके पीछे पूरा नेटवर्क सक्रिय है जो किसी कोर्स में दाखिले के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करता रहा है।

■ दिव्यांगों के 5% सीट पर एडमिशन हुआ है। इसमें भारत सरकार द्वारा अधिकृत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है। फर्स्ट व सेकेंड बैच में 7 छात्रों का सर्टिफिकेट फर्जी मिला है। सभी ने कान से दिव्यांग का सर्टिफिकेट दिया था। -प्रो. डॉ. हरिशंकर मिश्र, ब्रिक्सफर, जीएमसीएच

कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं रैकेट के तार

जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी फर्जी सर्टिफिकेट रैकेट के तार कई राज्यों से जुड़ते दिख सकते हैं। सात छात्रों के द्वारा दिए गए कागजातों की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि अलग-अलग राज्यों के शहरों जैसे कोलकाता, चंडीगढ़, बनारस से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई है। क्योंकि प्रमाण पत्र देने वाले संबंधित संस्थान से जब इसकी जानकारी मांगी गई तो उसने हाथ खड़े कर दिए। कहा गया कि उनके यहां से ऐसा कोई सर्टिफिकेट दिया ही नहीं गया है।

फर्जीवाड़े से वास्तविक दिव्यांग के हक पर डाका

यह फर्जीवाड़ा सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि उन अभ्यर्थियों के हक पर सीधा हमला है जो वास्तव में दिव्यांग हैं और कठिनाइयों के बावजूद मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। फर्जी दस्तावेजों के सहारे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चिंता का विषय है।

प्रवेश प्रक्रिया व शामिल जिम्मेदारों पर भी सवाल

मेडिकल कॉलेज में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर दाखिले का मामला अब सिर्फ हमला है जो वास्तव में दिव्यांग हैं और कठिनाइयों के बावजूद मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। फर्जी दस्तावेजों के सहारे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चिंता का विषय है।

भास्कर इनसाइट कान से दिव्यांग का बनवाया था सर्टिफिकेट

सीतामढ़ी के कार्तिक यादव ने कान से दिव्यांग के सर्टिफिकेट पर आरक्षित कोटे पर एडमिशन ले लिया। वह क्लास में बिना हियरिंग एड लगाए पढ़ाई करता था। इसके अलावा कुछ बोलने पर वह आसानी से सुन पा रहा था। इसके बाद जब कॉलेज प्रशासन को शक हुआ तो उसपर नजर रखी जाने लगी। उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। फिर संबंधित संस्थान को सर्टिफिकेट की सत्यता की जांच के लिए इसे भेजा गया।

पेज एक के शेष

भ्रष्टाचार: अफसरों पर ...

‘प्रावधान हटाना नहाने के पानी संग बच्चा फेकने जैसा’

■ जस्टिस नागरला ने कहा, यह धारा 17ए पहले ही सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों-विनोद नारायण और सुब्रमण्यम स्वामी केस में खारिज की जा चुकी है। उन्होंने कहा, ‘यह प्रावधान जांच को रोकता है और ईमानदार अफसरों की बजाय भ्रष्टों को बचाता है। ईमानदारों को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती।’

■ जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, ‘धारा 17ए को पूरी तरह खत्म करना ऐसा होगा जैसे बच्चा को नहलाते वक्त पानी के साथ उसे भी फेंक देना। हमें ईमानदार अफसरों को झूठे मामलों से बचाना होगा, लेकिन साथ ही सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी भी बनाए रखनी होगी।’

क्या है धारा 17ए? जुलाई 2018 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 में जोड़ी गई धारा 17ए के तहत किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ उसकी इ्यूटी के दौरान लिए गए फैसलों को लेकर जांच, पूछताछ या जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी लेना जरूरी है।

डिजिटल अरेस्ट पर ...

गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कमेटी में शामिल सभी पक्षों से विस्तृत सुझाव मिलने के बाद एक समेकित रिपोर्ट पेश करने के लिए एक महीने का वक्त दें, ताकि डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ सरकारी रणनीति अदालत के सामने रखी जा सके। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। इसकी बैठकों में भारत के अटॉर्नी जनरल भी शामिल होंगे, ताकि अदालत के आदेशों और एमिकस क्यूरी की सिफारिशों को एक साथ लागू किया जा सके। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने 76 वर्षीय नलिनी मिश्रा से जुड़े डिजिटल अरेस्ट के मामले की जांच दिल्ली पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई

ने नई प्राथमिकी दर्ज की है। नलिनी से 1.64 करोड़ रु. ठग लिए गए थे, जिसमें फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड दिखाकर उन्हें डराया गया और पैसे ट्रांसफर कराए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डिजिटल अरेस्ट की पीड़ित 76 वर्षीय नलिनी की आवाज बैंक और जांच एजेंसियों तक नहीं पहुंची, इसलिए जांच सीबीआई को सौंपी गई।

सख्ती जरूरी है, क्योंकि... देशभर में 2024 में डिजिटल अरेस्ट के 1.23 लाख मामले आए। इनमें 1935 करोड़ रु. की ठगी हुई। ■ यदि फोन करके आपसे कोई पैसे मांगे या डराए-धमकाए तो कॉल काटकर तुरंत 112/1930 (राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन) पर सूचना दें।

सहपाठी ने न्युड डीपफेक तस्वीरें...

■ स्कूलों के लिए जरूरी कदम: डिजिटल सेप्टी को पाठ्यक्रम में जोड़ें। शिकायत का स्पष्ट और सुरक्षित सिस्टम बनाएं। पीड़ित की पहचान गोपनीय रखें।

डीपफेक की पहचान

1. चेहरे में गड़बड़ी: आंखें, होंठ या नाक अजीब तरीके से पिछे हों। चेहरे का अनुपात शरीर के हिसाब से गलत लगे। बालों की लाइन या गर्दन के पास कटाव दिखें।

2. स्किन कलर: चेहरे और शरीर का रंग अलग दिखे। चेहरे की त्वचा स्मूद और शरीर की अलग दिखे। स्किन पर अजीब धब्बे, ब्लर या पैच नजर आए।

3. रोशनी और छाया: चेहरे पर रोशनी एक तरफ से, शरीर पर दूसरी तरफ से हो। छाया गलत दिशा में पड़े। बैकग्राउंड और शरीर की रोशनी अलग लगे।

4. किनारों पर कटे-कटे निशान: गर्दन, कंधे या बालों के पास फोटो कटी लगे। शरीर और बैकग्राउंड के बीच साफ बॉर्डर न हो। जूम करने पर ब्लर या पिक्सल टूट दिखें। चेहरे के हाव-भाव शरीर से मैच न करें। आंखें स्थिर या अजीब लगे।

भास्कर न्यूज़ | यमुनानगर

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धान घोटाले की जांच में हो रही देरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रविवार को कैल में भाकियू नेता दिलबीर सिंह के आवास पर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि इस घोटाले में व्यापारी, नेता और अधिकारी आपस में मिले हुए हैं,

तभी सस्ती दर पर खरीदी गई फसल को एमएसपी के नाम पर महंगे दामों में बेचा जा रहा है। किसान उगा जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि धान घोटाले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है, ताकि बड़े चेहरे बच निकलें।

भास्कर APPOINTMENT

से मेरे ऑफिस के लिए मिले अनुभवी और प्रतिभाशाली लोग



दैनिक भास्कर में स्टाफ हायरिंग संबंधित विज्ञापन बुकिंग का सबसे सरल माध्यम

BhaskarAd.com

बनाए विज्ञापन बुकिंग आसान

● घर बैठे ऐड बुकिंग ● आसान ऑनलाइन पेमेंट

9772019222

अब आप क्लासीफाइड, देवाहिंदी, शोक संदेश और जाहिर सूचना के विज्ञापन भी सीधे बुक कर सकते हैं

Notice : Ads have not been verified factually and Bhaskar does not stand responsible for the sales propositions.

भास्कर CLASSIFIED

आवश्यकता

APPOINTMENT

कार्यालयकर्म

वन विभाग तहसील स्तरीय भार्ती, पद- 1148, प्रभागीय अधिकारी, बुधवारोपण अधिकारी, फीडर ऑफिसर, वन सिपाही, क्लर्क, ड्राफ्टर, योग्यता- (8वीं- ग्रेजुएट) वेतन- (28500- 42500) आवेदनकर्ता- नाम पता, फ़ोनकोड/ WHATSAPP 7607890065

ज्योतिष

ASTROLOGY

ज्योतिष

फीस नहीं ईमान न लूं। पंडित रविशंकर (गोल्ड मेडलिस्ट) मनवावा (प्यारशही), गुल्बर्गेश, पति-पत्नी अजयब, सैतान-दुश्मन छुटकारा, प्रेमविवाह। घर बैठे सभी समाधान #7055429792

आवश्यकता

APPOINTMENT

से मेरे ऑफिस के लिए मिले अनुभवी और प्रतिभाशाली लोग



दैनिक भास्कर में स्टाफ हायरिंग संबंधित विज्ञापन बुकिंग का सबसे सरल माध्यम

BhaskarAd.com

बनाए विज्ञापन बुकिंग आसान

● घर बैठे ऐड बुकिंग ● आसान ऑनलाइन पेमेंट

9772019222

अब आप क्लासीफाइड, देवाहिंदी, शोक संदेश और जाहिर सूचना के विज्ञापन भी सीधे बुक कर सकते हैं

Notice : Ads have not been verified factually and Bhaskar does not stand responsible for the sales propositions.

बिजनेस ब्रीफ

ब्लूमबर्ग इंडेक्स: भारतीय सरकारी बॉन्ड अभी नहीं

मुंबई। ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज (बीआईएसएल) ने फिलहाल भारतीय सरकारी बॉन्ड को ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है। मुख्य कारण ऑपरेशनल और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां बताई गई हैं। इनमें ऑटोमैटेड ट्रेडिंग सिस्टम की कमी, सेटलमेंट, पोस्ट-ट्रेड टैक्स प्रक्रियाओं में देरी और जटिल नियम शामिल हैं। आला आउडेट 2026 के मध्य तक होने की उम्मीद है।

भारत की विकास दर

6.5% रहेगी: वर्ल्ड बैंक

नई दिल्ली | वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार को भारत के लिए वित्त वर्ष 2027 के विकास पूर्वानुमान को पिछले वर्ष अक्टूबर में अनुमानित 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। यह वृद्धि मजबूत घरेलू मांग और निर्यात प्रदर्शन के कारण हुई है, जो पहले की अपेक्षा अधिक लचीला साबित हुआ है। विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम 'वैश्विक आर्थिक संभावनाएं' रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ₹4 लाख करोड़ पार: वैण्णव

नई दिल्ली | देश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2025 में 4 लाख करोड़ रु. को पार कर गया। इसमें स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हिस्सा रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, केवल आईफोन का निर्यात 2024 के मुकाबले दोगुना बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रु. तक पहुंच गया। इस साल देश में स्मार्टफोन उत्पादन करीब 30 करोड़ यूनिट तक पहुंच सकता है। इसमें से एक चौथाई स्मार्टफोन निर्यात होंगे।

भारत कोकिंग कोल का आईपीओ 144 गुना भरा

मुंबई। भारत कोकिंग कोल का 1,071 करोड़ रु. का आईपीओ आधिकारी दिन 143.85 गुना सब्सक्राइब हुआ। 34.69 करोड़ शेयरों के लिए 4,990 करोड़ से भी अधिक शेयरों की बोलियां मिलीं। योग्य संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 310.81 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 240.49 गुना और रिटेल निवेशकों का 49.37 गुना सब्सक्राइब हुआ। प्रति शेयर कीमत 21-23 रुपए है।

बीएसई ने 4 नए मिडकैप फैंक्टर इंडेक्स लॉन्च किए

मुंबई | बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने बीएसई 150 मिडकैप इंडेक्स पर आधारित चार नए फैंक्टर इंडेक्स शुरू किए हैं। इनमें एन्हांस्ड वेल्यू 30, मोमेंटम 30, लो वोलैटिलिटी 30 और क्वालिटी 30 इंडेक्स शामिल हैं। हर इंडेक्स मिडकैप कंपनियों में से 30 शेयरों को अलग-अलग मानकों पर ट्रेक करेगा। इन इंडेक्स में हर तीन महीने में बदलाव होगा। इनका इस्तेमाल निवेश के पैसिव विकल्पों के लिए बेंचमार्क के रूप में होगा।

उदय कोटक ने अमेरिकी स्टैक्स ब्रांड गो-रॉं खरीदा

मुंबई | बैंकर उदय कोटक के फैमिली ऑफिस यूएसके कैपिटल ने अमेरिका की प्रोलेट्रड फूड्स इंग्लैण्ड एलसी में बहुमत हिस्सा हासिल कर लिया है। ये स्नेक्स ब्रांड गो-रॉं की मूल कंपनी है। यह यूएसके के पि ट ल का पहला विदेशी निवेश और उपभोक्ता उत्पाद क्षेत्र में पहली डील है। सौदा कितने में हुआ, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

बिजनेस एंकर

56% टॉप लीडर्स बर्नआउट के शिकार; ऐसे में नेटफ्लिक्स, ओरेकल जैसी कंपनियां ‘दो बॉस, एक विजन’ वाला फॉर्मूला अपना रही हैं...

भास्कर न्यूज़ | लंदन

क्या एक असात कर्मचारी से 122 गुना ज्यादा सैलरी पाना सीईओ की सेहत और वकालत बलेंस पर भारी पड़ रहा है? आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया के 60% सीईओ अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। लीडरशिप एग्जाइजरी फर्म आईबीईओ के सर्वे के मुताबिक 2024 में 56% शीर्ष अधिकारियों ने खुद को थका हुआ (बर्नआउट) बताया।

इस संकट से निपटने के लिए अब ग्लोबल बिजनेस जगत में 'पावर थैरापी' का ट्रेंड बढ़ रहा है। कंपनियां एक ही व्यक्ति पर पूरा बोझ डालने के बजाय जिम्मेदारी साझा करना ज्यादा टिकाऊ मॉडल मान रही हैं। इसे बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया में को-सीईओ मॉडल कहा जा रहा है,

फैंसला • जीएसटी में 10% कटौती से 30% तक कीमत घटने का असर...

छोटी कारों के दिन लौटे, 5 लाख से कम दाम वाली कारों की बिक्री 92% तक बढ़ी

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

छोटी कारों का दौर लौट आया है। सरकार ने बीते साल दिसंबर में छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% कर दी थी। इससे कीमतें 25-30% कम हो गईं। नतीजतन 5 लाख रुपए से कम की एंटी-लेवल कारों की मांग में उछाल आया। 6 साल बाद छोटी कारों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। अक्टूबर-दिसंबर 2025 में हैचबैक कारों की बाजार हिस्सेदारी 24.4% हो गई, जो साल के पहले 9 महीनों में 23.5% थी। बीती तिमाही मारuti सुजुकी के मिनी सेगमेंट (अल्टो, एस-प्रेसो, सेलेरियो, वेगनआर -सभी 5 लाख रुपए से कम) की बिक्री 92% बढ़ गई। बुकिंग इतनी ज्यादा है कि 1.5 महीने से डिलीवरी पेंडिंग चल रही है। इस बीच टाटा मोटर्स की टियागो की बिक्री 22% बढ़ गई। इसके सीएनजी वैरिएंट की बिक्री 34.5% और सीएनजी ऑटोमैटिक की बिक्री 41% बढ़ गई। कंपनी के मुताबिक, टैक्स घटने के बाद मासिक रिटेल बिक्री औसतन 50% बढ़ी है।

6 साल में पहली बार छोटी कारों का बाजार बढ़ा

दिसंबर में कार बिक्री 27% बढ़ी, 2025 की सबसे बड़ी मासिक उछाल, 84 लाख ज्यादा कारें बिकीं



- ब्लैक कार का क्रेज... मार्केट शेयर 14.8% से बढ़कर 21%
- बिक्री बढ़ी कारों से ज्यादा बढ़ने से 6 साल बाद छोटी कारों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी
- अक्टूबर-दिसंबर में हैचबैक की बाजार हिस्सेदारी 24.4% हो गई, जो 2025 के पहले 9 महीनों में 23.5% थी
- छोटी कारों की बिक्री में उछाल के चलते बीते दिसंबर में कारों की कुल बिक्री सालाना 27% बढ़कर 3.99 लाख हो गई, जो पिछले साल 3.15 लाख थी
- वाहन कंपनियों के संगठन सियाम के आंकड़ों के मुताबिक, यह 2025 के दौरान किसी एक महीने की बिक्री में सबसे बड़ा
- मासिक उछाल था।
- बीते दिसंबर में दिसंबर 2024 के मुकाबले करीब 84 लाख ज्यादा कारें बिकीं
- युवा खरीदारों और प्रीमियम एंड़ेशन की वजह से ब्लैक कार का क्रेज बढ़ा है। 2025 में इनकी बाजार हिस्सेदारी 14.8% से बढ़कर 20.76% हो गई।
- 2025 में बिकीं करीब 30% एसयूवी काले रंग की थी, हैचबैक सेगमेंट में इस रंग की सिर्फ 6.77% कारें बिकीं
- सबसे ज्यादा बिकने वाली सफेद कारों की बाजार हिस्सेदारी 43.9% से घटकर 40.7% रह गई।

नवाचार • 39% इंटेलिजेंट ऑटोमेशन एआई के जिम्मे

एआई 40% तक तकनीकी काम कर रहा, पर इंसानी निगरानी जरूरी

भास्कर न्यूज़ | बेंगलुरु

देश के तकनीकी संगठनों में अब 20-40% काम एआई संचाल रहा है। आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एआई का दखल इससे भी ज्यादा है। आईटी कंपनियों की प्रतिनिधि संस्था नैसकॉम और जॉब प्लेटफॉर्म इंडीज के एक सर्वे में शामिल 45% कंपनियों ने कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का 40% से ज्यादा हिस्सा एआई संचाल रहा है। इंटेलिजेंट ऑटोमेशन का 39% और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का 37% काम या तो पूरी तरह एआई कर रहा है या बड़ी भूमिका निभा रहा है।

‘प्युचर वर्क 2025’ नाम के सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि एआई अब सिर्फ सहायक टूल नहीं रहा, बल्कि रोजमर्रा के नियमित काम में गहराई से जुड़ गया है। 97% एचआर (मानव संसाधन) लीडर्स का मानना है कि 2027 तक काम की प्रकृति इंसान और एआई के सहयोग से तय होगी। 95% से ज्यादा संगठन एआई एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसा करने की योजना बना रहे हैं।



एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, पर नए हुनर की दरकार

सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा कंपनियों ने कहा कि एआई के आउटपुट अधूरे या कम क्वालिटी वाले होते हैं, इसलिए मानव निगरानी बहुत जरूरी बनी हुई है। एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, बल्कि भूमिकाएं तेजी से बदल रही है। एंटी-लेवल जॉब्स में अब लाइव प्रोजेक्ट्स, हैकथॉन और पोटेंफोलियो को डिश्री से ज्यादा महत्व मिल रहा है।

77% नियोक्ताओं को सुरक्षा की चिंता

- 77% एम्प्लॉयर्स को सिक्युरिटी और प्राइवेसी रिस्क की चिंता, 40% एचआर लीडर्स कर्मियों में एआई-रेडिनेस की समस्या से परेशान हैं।
- **कारियर का असली मौका लोगों को एआई के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार करने में है।**
- **केतकी कर्णिक**, रिसर्च हेड, नैसकॉम

बाजार टूटे संसेक्स में 933 अंकों का उतार चढ़ाव, 83,628 पर बंद हुआ

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट आई। संसेक्स 13 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार में काफी तेजी से गिरावट आई। संसेक्स सुबह के 84,258 के ऊंचे स्तर से 933 अंक गिरकर 83,325 तक नीचे आया। अंततः 250 अंकों की गिरावट के साथ नीचे 83,628 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 25,900 की ऊंचाई से 296 अंक गिरकर 25,603 के स्तर तक लुढ़कने के बाद 25,732 पर बंद हुआ, जिसमें 58 अंकों की गिरावट आई। यह उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली की वजह से आया। विदेशी संस्थाओं ने करीब 3,443 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। टुप की तरफ से नए टेरिफ एलान से वैश्विक चिंता और बड़े शेयरों में मुनाफा वसूली से भी बाजार नीचे आया। बैंक और आईटी जैसे कुछ सेक्टरों में थोड़ी मजबूती रही।

केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता चर्चा में

11 केंद्रीय बैंकों ने अमेरिकी फेड रेजर पॉवेल से एकजुटता दिखाई

एजेंसी | वॉशिंगटन

दुनियाभर के 11 प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के साथ पूरी एकजुटता दिखाई है। यह समर्थन तब आया, जब अमेरिकी न्याय विभाग ने पॉवेल के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की। बैंक ऑफ इंग्लैंड के एंड्रयू बेली, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ कनाडा के टिफ मैकलम सहित 11 बैंकों ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें पॉवेल की इमानदारी, जनहित में काम और ब्याज दर तय करने में उनकी स्वतंत्र सोच की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि पॉवेल एक सम्मानित सहकर्मी हैं और केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है।



60% सीईओ ने कहा- इससे परिवार को पर्याप्त समय दे सकते हैं

लंदन स्थित कंपनी बोर्ड इंटेलिजेंस की सह-सीईओ पिप्पा बेग के अनुसार, दो लोगों के साथ फैसले लेने से गलतियां और अहंकार की संभावना कम हो जाती है। उन्होंने बताया कि सह-सीईओ मॉडल की वजह से वे पांच साल में तीन बार मातृत्व अवकाश ले सकीं, जो किसी सीईओ के लिए आम बात नहीं है। एनजीक्यूटिव सर्व फर्म रसेल रेंनोल्ड्स के मुताबिक, 60% सीईओ मानते हैं कि वे परिवार को वक्त नहीं दे पाते। ये मॉडल इस समस्या को कम कर सकता है।

जिसमें दो लोग मिलकर कंपनी का नेतृत्व करते हैं। ऐसे मॉडल वाली कंपनियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। इंटेलिजेंस फर्म मायलॉजिक्व्यू के मुताबिक, 2015 में अमेरिका की बड़ी कंपनियों के रसेल3000 इंडेक्स में सिर्फ 11 कंपनियों में सह-सीईओ थे। 2024 तक यह दोगुना बढ़कर 24 हो गई। नेटफ्लिक्स, ओरेकल, कॉमकास्ट और स्पाटिफाई जैसी कंपनियों ने भी यह मॉडल अपनाया है। लीडरशिप कोच ऑर्डे हैमेटनर के अनुसार, सह-सीईओ मॉडल से काम का बेहतर बंटवारा संभव होता है। कई कंपनियों में एक सह-सीईओ मार्केटिंग और प्रोडक्ट की

बड़ी तैयारी...

ईवी उत्पादन बढ़ाने की रक्रीम में बदलाव होगा!

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई गई एसपीएमईपीसीआई योजना में सरकार बदलाव कर सकती है। मार्च 2024 में शुरू हुई इस स्क्रीम में ग्लोबल ईवी कंपनियां 35,000 डॉलर से ज्यादा दाम वाली इलेक्ट्रिक कारें 15% शुल्क पर 5 साल इम्पोर्ट कर सकती हैं। बदले में भारत में कम से कम 4,150 करोड़ रुपए निवेश करके फैक्ट्री लगानी होती है। लेकिन जनवरी, 2026 तक कोई आवेदन नहीं आया। इसलिए इसमें डाप्रेक्ट इंसेंटिव्स जोड़े जा सकते हैं। वाहन कंपनियों ने सरकार को बताया है कि अगर मुक्त व्यापार समझौते के तहत इलेक्ट्रिक कारों आयात की जाएं तो बिना भारत में फैक्ट्री लगाए ही विस्तार किया जा सकेगा। ऐसे में सरकार की रक्रीम बेकार हो जाएगी।

ईपीएस • पेंशनर्स को राहत

डाकिया घर आकर निशुल्क बनाएगा जीवन प्रमाण पत्र

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) जमा करने की 'फ्री डोरस्टेप' सेवा शुरू की है। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के साथ हाथ मिलाया गया है। अब बुजुर्गों को बैंक या ईपीएफओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। डाकिया या डाकसेवक खुद घर आकर बायोमेट्रिक मशीन से सर्टिफिकेट बनाएगा।

ईपीएफओ के 9 जनवरी 2025 के सर्कुलर के अनुसार, इस सेवा का पूरा खर्च संगठन उठाएगा और पेंशनर से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे पेंशन रेशा रुकावट जारी रहेगी। पेंशनर्स आईपीपीबी के नंबर 033-22029000 पर कॉल कर यह सर्विस बुक कर सकते हैं। डाकिया घर आकर फिंगरप्रिंट या चेहरा स्कैन कर 'जीवन प्रमाण' दर्ज करेगा। वह आधार और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) नंबर का मिलान कर प्रक्रिया पूरी करेगा। सर्टिफिकेट तभी सफल माना जाएगा जब आईपीपीबी का डेटा ईपीएफओ सिस्टम से मैच होगा। सिस्टम से मंजूरी मिलते ही डीएलसी आगे एक साल के लिए वैध हो जाएगी। ईपीएस पेंशनर्स साल में कभी भी यह सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। 'जीवन प्रमाण' आधार-आधारित बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट होता है। यह पेंशनर के जीवित होने की पुष्टि करता है। ईपीएस पेंशनर्स इसे साल में कभी भी जमा कर सकते हैं, और यह जमा करने की तारीख से 1 साल तक वैध रहता है।

स्टॉक घटने से बढ़ सकते हैं दाम

नवंबर-दिसंबर में देश का खाद्य तेल आयात 11.6 फीसदी घटा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

तेल वर्ष 2025-26 के पहले दो महीनों (नवंबर-दिसंबर) में भारत का खाद्य तेल आयात 11.6% घट गया। इस दौरान कुल 25.13 लाख टन तेल आया, जो पिछले साल 28.43 लाख टन था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के मुताबिक, रिफाईंड तेल का आयात 5.17 लाख टन से घटकर मात्र 3,500 टन रह गया। इसके विपरीत, कच्चे खाद्य तेल (सीपीओ) का आयात 23.26 लाख टन से 7.87% बढ़कर 25.09 लाख टन पहुंच गया। इससे कुल आयात में कच्चे खाद्य तेल की हिस्सेदारी बढ़कर 99.86% हो गई है। यह घरेलू रिफाईनिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा संकेत है। जानकारों का कहना है कि सप्लाई में कमी से बाजार में स्टॉक घट सकता है। इससे आने वाले दिनों में तेल की कीमतें बढ़ने का डर है।

रणनीति • 2 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीद सकता है केंद्रीय बैंक

आरबीआई बैंकों की पूंजी लागत कम कर रहा, ताकि ब्याज दरें कम ही रहें

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

कर्ज की लागत घटाने के लिए रिजर्व बैंक (आरबीआई) बॉन्ड खरीद की रणनीति अपना रहा है। अप्रैल 2025 से अब तक आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) के तहत 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के सरकारी बॉन्ड खरीद चुका है। मकसद सिस्टम में नकदी बढ़ाकर ब्याज दरों को काबू करना है। हालांकि, संकेत अब भी चुनौतीपूर्ण हैं। एक महीने में तीन महीने वाले सरकारी बॉन्ड की यील्ड 0.57% और 10 साल वाले बॉन्ड की 0.80% बढ़ी है। एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर डॉ. सोम्य कांति घोष के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितता और विदेशी निवेश में कमी को देखते हुए मार्च 2026 तक आरबीआई को 2 लाख करोड़ के और बॉन्ड खरीदने पड़ सकते हैं। अप्रैल 2024 से अब तक सिस्टम में 7.7 लाख करोड़ रुपए की नकदी डाली जा चुकी है। इस दौरान रेपो रेट में भी 1.25% की कटौती की गई। इसके बावजूद बॉन्ड यील्ड उम्मीद के मुताबिक नहीं घटी। इससे कर्ज की लागत कम नहीं हो पा रही।

प्रक्रिया: बॉन्ड खरीदकर नकदी बढ़ाई जाती है

ओएमओ नकदी नियंत्रित करने का प्रमुख टूल है। जब बाजार में पैसा कम होता है, तो आरबीआई बैंकों से सरकारी बॉन्ड खरीदकर उन्हें नकदी देता है। बैंकों के पास फंड बढ़ने से वे कम ब्याज दर पर कर्ज देने की स्थिति में आते हैं। इससे आम आदमी के लिए होम, कार और बिजनेस लोन लेना सस्ता होता है।

असर: महंगा कर्ज निवेश और खपत के लिए बाधा

बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बैंकों के लिए फंड जुटाना महंगा हो गया है। इस वजह से होम लोन, ऑटो लोन और कॉरपोरेट लोन की दरें ऊंची बनी हुई हैं। यह निवेश और खपत दोनों को प्रभावित कर रहा है। आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए अब आरबीआई को बॉन्ड खरीद का दायरा बढ़ाना ही होगा।

संकट: राज्यों की भारी उधारी से नकदी पर दबाव

केंद्र ने उधारी योजना में 10,000 करोड़ की कटौती की है, लेकिन राज्य सरकारें मार्च तक 5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में हैं। बॉन्ड की निरंतर सप्लाई बाजार की नकदी सोख लेती है। जब सरकार बहुत ज्यादा लोन लेती है, तो बाजार में फंड कम होने से आम आदमी के लिए भी लोन महंगा हो जाता है।

अनुमान: इस साल दरें 0.50% घटा सकता है आरबीआई

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक देश में लोगों की आमदनी और कंपनियों का मुनाफा कमजोर है। ऐसे हालात में जब रिटेल महंगाई नियंत्रण में है रिजर्व बैंक के पास 2026 में रेपो रेट में 0.25-0.50% तक कटौती करने की गुंजाइश बनी हुई है। आने वाले महीनों में सब्जियों के दाम धीरे-धीरे सामान्य होंगे, जिससे महंगाई थोड़ी बढ़ सकती है। इसके बावजूद महंगाई के आरबीआई की तय सीमा में रहने की उम्मीद है।

बर्फ के नीचे लज्जरी: नॉर्वे में बर्फ का होटल बनकर तैयार, एक रात का किराया 46,755 रुपए से शुरू



नॉर्वे | नॉर्वे में सोरिसनिवा इग्लू होटल बनाया गया है। इसके 13 कमरे बर्फ से बने हैं, जहां अंदर का तापमान माइनस 4-7 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। होटल के आसपास बर्फ की कलात्मक मूर्तियां देखी जा सकती हैं। हर कमरे की अपनी एक कलात्मक थीम है। बिस्तर ठोस बर्फ से बने हैं और मेहमानों को रात भर आरामदायक रखने के लिए इनके ऊपर गद्दे और बारहसिंगे की खाल बिछाई गई हैं। 2,500 वर्ग मीटर में बने इस होटल को बनाने में 250 टन बर्फ और 7,000 घन मीटर स्नो (हैम) का इस्तेमाल हुआ है। यहां एक रात ठहरने का किराया 46,755 रुपए से शुरू होता है। यहां दुनियाभर के सैलानी आते हैं।

ट्रेडर्स को फायदा • सेबी पैनल से मिली मंजूरी

कैश सेगमेंट में मार्जिन घटने से कम पूंजी में ज्यादा ट्रेड हो सकेगा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

शेयर मार्केट में नकद लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सेबी ने कैश सेगमेंट में मार्जिन घटाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव को सेबी के पैनल ने मंजूरी दे दी है। हालांकि पैनल ने सलाह दी है कि मार्जिन 12.5% से कम नहीं होना चाहिए। अभी इस पर अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। सेबी के प्रस्ताव को कैश मार्केट को बढ़ावा देने के प्रमुख उपाय के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में, अधिकांश शेयरों का वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन (एलएलएम) 12.5 से 20% के बीच है। वीएआर मार्जिन बाजार में अस्थिरता से होने वाले अधिकतम संभावित नुकसान की भरपाई के लिए वसूला जाता है। इंग्लैण्ड सामान्य मार्जिन आवश्यकताओं के अतिरिक्त एक्सचेंजों द्वारा लिया जाता है।

नियमों में ढील से ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक ये कदम ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा। मार्जिन नियमों में ढील से ट्रेडिंग वॉल्यूम में बहुत देखने को मिल सकती है। बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ सकता है,रिटेल और छोटे निवेशकों को बेहतर सुविधा जैसे फायदे मिलेंगे।

ट्रेडर्स को अभी 20% तक मार्जिन रखना होता है

पहले जहां ट्रेडर्स को 15-20% तक मार्जिन जमा करना होता था, अब कम मार्जिन लगाए। इससे उनके पास ज्यादा फंड ट्रेडिंग के लिए खाली रहेगा। ज्यादा ट्रेडर्स कैश मार्केट में शामिल होंगे, खरीद/बिक्री का वॉल्यूम और बाजार में सक्रियता बढ़ेगी। ट्रेडिंग लागत घटेगी।

चांदी पहली बार 2.63 लाख रु. किलो के पार

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

घरेलू बाजार में चांदी मंगलवार को एक बार फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गई। चांदी 6,256 रुपए की छल्लांग लगाकर 2,63,032 रुपए प्रति किलो के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इसके उलट, सोने में हल्की नरमी देखी गई। 24 कैरेट सोना 165 रुपए गिरकर 1,40,284 रुपए और 22 कैरेट (जेवराती) सोना 151 रुपए सस्ता होकर 1,28,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चार दिन में ही चांदी 23,038 रुपए चढ़ चुकी है, जबकि जनवरी के शुरुआती 13 दिनों में यह 32,612 रुपए (14.15%) प्रति किलो महंगी हो चुकी है। वहीं, इस अवधि में 24 कैरेट सोने की कीमतों में 7,089 रुपए (5.32%) की बढ़त दर्ज की गई है।

रिटायरमेंट • पीएफआरडीए का फैसला

एनपीएस: निश्चित पेंशन के नियमों के लिए समिति बनी

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत निश्चित पेंशन भुगतान का ढांचा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसका मकसद रिटायरमेंट के बाद पेंशनधारकों को निश्चित और सुरक्षित आय उपलब्ध कराना है। यह पहल एनपीएस में निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगी। यह कदम पीएफआरडीए एक्ट के अनुरूप है और रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी को मजबूत करने पर केंद्रित है। समिति की अध्यक्षता आईबीबीआई

कमेटी तय करेगी कि पैसा कब तक जमा रहेगा

कमेटी यह तय करेगी कि पैसा कितने समय तक जमा रहेगा, कितना पैसा निकाला जा सकेगा, पेंशन की कीमत कैसे तय होगी और सेवा देने वाली कंपनियां कितनी फीस लेंगी। इसके अलावा, पेंशन पर लगने वाले टैक्स और जोखिम से जुड़े नियमों की भी समीक्षा होगी।

के पूर्व चेयरमैन एम. एस. साहू करण। 15 सदस्यीय पैनल में कानून, बीमा, फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं।

समाधान की राह

देश में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं अब आम लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए गली-मोहल्लों में सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। पिछले कई वर्षों से यह मसला सत्ता के गलियारों से लेकर सड़क तक उठता रहा है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, लेकिन नतीजा ‘ढाक के तीन पात’ जैसा ही है। यही वजह है कि मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय को यह कहना पड़ा कि कुत्ते के काटने की घटनाओं में राज्यों को भारी मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि पिछले पांच वर्षों में आवारा पशुओं से संबंधित नियमों के क्रियान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। साथ ही यह भी कहा कि कुत्तों को सड़क पर भोजन खिलाने वालों को भी जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस संकट से निपटने के लिए न तो राज्य सरकारों की ओर से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और न ही कुत्तों को सड़क पर भोजन परोसने पर रोक लग पाई है।

केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तरफ से पिछले वर्ष जारी आंकड़ों पर गौर करें, तो देश में जनवरी, 2024 से लेकर दिसंबर तक कुत्ते के काटने के सैंतीस लाख से अधिक मामले सामने आए। इनमें पांच लाख से ज्यादा मामले पंद्रह साल से कम उम्र के बच्चों के थे। जबकि कुत्ते के काटने से करीब सैंतीस लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर मामले रेबीज संक्रमण के थे। इन आंकड़ों से स्थिति की गंभीरता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इस समस्या से निजात पाने का सरल एवं प्रभावी उपाय आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना माना जाता है। इसके लिए विभिन्न राज्यों में टीकाकरण के जरिए कुत्तों का बंध्याकरण करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही और इच्छाशक्ति के अभाव में यह मुहिम कागजों में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और इंसानों को काटने की घटनाओं में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

शीर्ष अदालत ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पिछले दिनों आक्रामक आवारा कुत्तों को सड़क से हटाकर आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया था। साथ ही गली-मोहल्लों में कुत्तों को सड़क पर भोजन नहीं परोसने की हिदायत भी दी थी। मगर पशु प्रेमियों को यह फैसला रास नहीं आया और यह मामला फिर से सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। इसमें दोराय नहीं है कि आवारा कुत्तों को सुरक्षित और खुला वातावरण मिलना चाहिए, लेकिन इस बात को भी समझना जरूरी है कि मानव सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने भी यह सवाल उठाया है कि अगर पशु प्रेमियों को आवारा कुत्तों से लगाव है, तो वे उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते? दरअसल, कुत्तों को सड़क पर भोजन परोसे जाने से वे वहीं आसपास घूमते रहते हैं और स्थानीय लोगों को काटते और डराते हैं। ऐसे में इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से ही इस समस्या से निपटने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

असमानता की खाई

कि सी भी राष्ट्र के संतुलित विकास के लिए आर्थिक समानता का होना बेहद जरूरी है। जब तक सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं होंगी, तब तक विकास के तमाम दावे अधूरे ही साबित होंगे। मगर, चिंताजनक बात है कि दुनिया भर में आर्थिक असमानता का दायरा बढ़ता जा रहा है। इससे न केवल आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है, बल्कि आमजन की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी आधारभूत जरूरतों तक पहुंच भी सीमित हो रही है। इससे कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। विश्व आर्थिक मंच की नई सर्वेक्षण रपट में भी इस बात को उजागर किया गया है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर के युवा असमानता से चिंतित हैं। मगर इसकी आलोचना करने के बजाय, वे इसमें बदलाव चाहते हैं। सवाल है कि आखिर अमीर-गरीब के बीच खाई घटने की बजाय बढ़ क्यों रही है? क्या शासन और प्रशासन को इस बात का भान नहीं है कि इस असमानता के परिणाम न केवल किसी एक देश, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकते हैं? इसमें दोराय नहीं कि आर्थिक असमानता के मामले में भारत भी पीछे नहीं है। विश्व असमानता पर हाल में जारी की गई एक रपट के मुताबिक, देश की कुल संपत्ति का करीब चालीस फीसद हिस्सा महज एक फीसद लोगों के पास है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में आर्थिक असंतुलन का स्तर कहां पहुंच गया है। युवा वर्ग भी इससे प्रभावित हो रहा है और वह व्यवस्था में बदलाव तो चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे सही मंच और अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच की रपट में कहा गया है कि सर्वेक्षण के दौरान सत्तावन फीसद युवाओं ने इस असमानता पर गंभीर चिंता जताई है। आर्थिक असमानता बढ़ने की चेतावनी पहले भी दी जाती रही है, लेकिन इस पर गंभीरता दिखाने की पहल दुनिया के किसी कोने में नजर नहीं आई है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब किसी देश की संपत्ति का बड़ा हिस्सा चंद लोगों के हाथों में आ जाएगा, तो उसका परिणाम क्या होगा।

दूषित पेयजल से गहराता संकट

देश में जल आपूर्ति अवसंरचना की जर्जर स्थिति और गुणवत्ता परीक्षण की कमजोर व्यवस्था ने शहरी और ग्रामीण जीवन के स्वास्थ्य को जोखिम में डाल दिया है। इंदौर की त्रासदी एक चेतावनी है कि व्यवस्था में अब सुधार की नितांत आवश्यकता है।

अतुल अग्रवाल

जल प्रदूषण आज मनुष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। यह प्रबंधन में लापरवाही बरतने का भी नतीजा है। जल के संरक्षण और उसकी स्वच्छता को लेकर योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने में गंभीरता एवं कुशलता का अभाव रहता है। घर-घर जल पहुंचाने की योजना जरूर अच्छी है। मगर इसी के साथ नदियों की सफाई और जल आपूर्ति करने करने वाली पाइपलाइनों की समय-समय पर जांच की जाती, तो समस्या गंभीर नहीं होती। इंदौर में दूषित पेयजल के सेवन से हुई लोगों की मौत ने एक बार फिर यह उजागर कर दिया है कि भारत का जल संकट केवल मात्रा का नहीं, बल्कि गुणवत्ता, निगरानी और शासन की गंभीर विफलताओं का परिणाम है। यह घटना किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य संकट का प्रतीक है, जो देश के लगभग हर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्र में अलग-अलग रूपों में मौजूद है। जल, जिसे जीवन का आधार माना जाता है, जब वही जीवन के लिए ही घातक बन जाा, तब यह प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि संस्थागत असफलता का संकेत है।

संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल रपट 2024 के अनुसार, विश्व की लगभग 2.2 अरब आबादी को आज भी सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। भारत, जहां विश्व की अठारह फीसद जनसंख्या निवास करती है और जहां मीठे जल संसाधनों का मात्र चार फीसद हिस्सा उपलब्ध है, वह इस वैश्विक जल संकट के केंद्र में है। मगर इंदौर की घटना स्पष्ट करती है कि चुनौती केवल जल की उपलब्धता तक सीमित नहीं, बल्कि यह सवाल भी उतना ही अहम है कि जो जल उपलब्ध कराया जा रहा है, वह कितना सुरक्षित और उपयोग के योग्य है। घरों तक पहुंचाए जा रहे जल की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी का अभाव अब भी बन हुआ है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है।

नीति आयोग की जल प्रबंधन रपट 2023 में यह चेतावनी है कि भारत के इक्कीस से अधिक बड़े शहर अगले दशक में पानी खत्म होने की भयावह स्थिति का सामना कर सकते हैं। मगर इंदौर का अनुभव बताता है कि संकट भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि वर्तमान की भयावह वास्तविकता है। जल आपूर्ति अवसंरचना की जर्जर स्थिति, पेयजल और सीवेज लाइनों का आपसी संपर्क तथा जल गुणवत्ता परीक्षण की कमजोर व्यवस्था ने शहरी और ग्रामीण जीवन के स्वास्थ्य को जोखिम में डाल दिया है। ‘नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स’ के अनुसार भारत के शहरी जल तंत्र में 35 से 40 फीसद जल पाइपलाइन में रिसाव के कारण बर्बाद हो जाता है। यह केवल संसाधनों की हानि नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक खतरा भी है, क्योंकि इन्हीं रिसाव बिंदुओं से दूषित तत्त्व पेयजल में जाते हैं।

इंदौर जैसे शहर, जो स्वच्छता और शहरी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाते रहे हैं, वहां ऐसी घटना यह दर्शाती है कि दृश्य उपलब्धियों के पीछे एक गहरी तकनीकी और निगरानी संबंधी कमी छिपी हुई है। यह समस्या केवल इंदौर तक सीमित नहीं है। देश के विभिन्न बड़े शहरों में समय-समय पर दूषित जल से फैलने वाली बीमारियों के मामले सामने आते रहते हैं। अंतर केवल इतना है कि हर बार परिणाम इतने गंभीर रूप में दर्ज नहीं हो पाते या सरकारी फाइलों में दब जाते हैं। इस उपेक्षा की कीमत नागरिकों को जान देकर



चुकानी पड़ती है। निराशाजनक बात यह है कि औद्योगिक और शहरी प्रदूषण इस संकट को और गहराता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की वर्ष 2023 की एक रपट के अनुसार देश की साठ फीसद से अधिक औद्योगिक इकाइयां अपने अपशिष्ट जल का समुचित उपचार नहीं करती। अनुमान है कि भारत का

संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल रपट 2024 के अनुसार, विश्व की लगभग 2.2 अरब आबादी को आज भी सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। भारत में जहां मीठे जल संसाधनों का मात्र चार फीसद हिस्सा उपलब्ध है, वह इस वैश्विक जल संकट के केंद्र में है। मगर इंदौर की घटना स्पष्ट करती है कि चुनौती केवल जल की उपलब्धता तक सीमित नहीं, बल्कि यह सवाल भी उतना ही अहम है कि जो जल उपलब्ध कराया जा रहा है, वह कितना सुरक्षित और उपयोग के योग्य है। घरों तक पहुंचाए जा रहे जल की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी का अभाव अब भी बना हुआ है।

लगभग सत्तर फीसद औद्योगिक अपशिष्ट जल बिना उपचार के नदियों और जल स्रोतों में प्रवाहित होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के

रिश्तों की नींव

संध्या अग्रवाल

हम जब किसी रिश्ते में प्रवेश करते हैं, तो अक्सर यह सोचकर नहीं आते कि हम क्या महसूस करते हैं, बल्कि यह सोचकर आते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। धीरे-धीरे रिश्ते भावनाओं का नहीं, अपेक्षाओं का मंच बन जाते हैं। हम यह मान लेते हैं कि अच्छे रिश्ते वही हैं, जहां कोई शिकायत न हो, कोई असहमति न हो और कोई थकान दिखाई न दे। यहीं से शुरू होती है ‘परिपूर्ण बनने’ या संपूर्णता की मांग की अदृश्य दौड़। हम हर भूमिका में खुद को ढालने लगते है- बेटी, पत्नी, मां, मित्र, सहकर्मी। और इस ढलने की प्रक्रिया में हम यह भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान हैं, जिसकी अपनी सीमाएं, अपनी जरूरतें और अपनी भावनाएं हैं। संपूर्ण बनने की यह मानसिकता अचानक विकसित नहीं होती। इसका बीज बचपन में ही बो दिया जाता है, जब हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे कैसे होते हैं। जो बच्चे ज्यादा सवाल न करें, जो बड़ों की हर बात मान लें और जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना सीख लें।

लड़कियों के लिए यह सीख और भी सख्त होती है। उन्हें बताया जाता है कि ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, अपनी बात मन में रखना ही समझदारी है और रिश्ते निभाने के लिए खुद को पीछे रखना पड़ता है। यही बातें आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। हर रिश्ता थोड़ा-बहुत समझौता मांगता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है, जब समझौता आदत बन जाए और अपनी बात रखना स्वार्थ समझा जाने लगे। कई लोग अपनी नाराजगी, थकान और असंतोष को भीतर ही दबाए रखते हैं, ताकि सामने वाला असहज न हो। धीरे-धीरे यह चुप्पी रिश्ते की भाषा बन जाती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक खालीपन जन्म लेने लगता है। व्यक्ति महसूस करता है कि वह हर रिश्ते में मौजूद है, लेकिन अपनी ही जिंदगी में अनुपस्थित है।

असौ के समय में सोशल मीडिया ने परिपूर्णता या संपूर्णता की कसौटी वाले रिश्तों की एक झूठी तस्वीर हमारे सामने रख दी है। हर तरफ मुस्कुराते चेहरे, आदर्श जोड़े और खुशहाल परिवार दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों के पीछे की थकान, मतभेद और चुप्पी कभी दिखाई नहीं देती। इन सबको देखकर हम अपने वास्तविक रिश्तों से असंतुष्ट होने लगते हैं। हमें लगता है कि कहीं हम ही कम पड़ रहे हैं, हमारा रिश्ता ही अधूरा है। मन में इसी भावना के कारण हम खुद को और ज्यादा बदलने की कोशिश करने लगते हैं- खुद को बेहतर नहीं, बल्कि ‘संपूर्ण’ या ऐसा बनाने के लिए, जिसमें कोई भी कमी न हो।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

धनी होने का अर्थ श्रेष्ठ होना नहीं है, श्रेष्ठ वही है जो सिद्धांतों के प्रति दृढ़ है और ईमानदारी के रास्ते पर अडिग है।

- विलियम एलेरी

आंकड़े बताते हैं कि गंगा और यमुना जैसी नदियों में जैव-रासायनिक आक्सीजन मांग (बीओडी) स्तर मानकों से कहीं अधिक है। यही जल जब शोधन की अपर्याप्त प्रक्रिया से गुजर कर नागरिकों तक पहुंचता है, तो स्वास्थ्य संकट अवश्यंभावी हो जाता है। स्वाभाविक है कि अब इसके उपाय सोचने होंगे। जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। ऐसे में दोराय नहीं कि जल संकट आने वाले समय में और भी गहराएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बीते पांच दशकों में देश में औसत वर्षा में गिरावट और चरम वर्षा घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। इससे जल स्रोतों की स्वाभाविक पुनर्भरण और शुद्धीकरण क्षमता प्रभावित हुई है। अचानक होने वाली भारी वर्षा के दौरान यदि वर्षा जल का वैज्ञानिक ढंग से संचय न किया जाए, तो वह प्रदूषकों को अपने साथ बहा कर जलाशयों और नदियों में पहुंचा देता है, जिससे जल की गुणवत्ता और अधिक खराब हो जाती है।

इन परिस्थितियों में स्पष्ट है कि जल प्रबंधन को केवल राज्य या राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि सूक्ष्म स्तरीय जल प्रबंधन को नीति के केंद्र में लाया जाए। प्रत्येक वार्ड, मोहल्ले और प्रत्येक जल आपूर्ति मंडल के स्तर पर जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी, पाइपलाइन नेटवर्क का पृथक्कीकरण और वास्तविक समय के आंकड़ों पर आधारित चेतावनी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। जल सुरक्षा को अब ‘एक समान नीति’ के बजाय ‘स्थान-विशिष्ट समाधान’ के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत का जल संकट सर्वव्यापी समस्या है, जिसे सामान्य नीतियों से नहीं, बल्कि स्थानीय और सूक्ष्म स्तर पर लक्षित हस्तक्षेप से ही सुलझाया जा सकता है।

इसके साथ ही, ‘हर घर नल’ जैसी योजनाओं को ‘हर नल सुरक्षित’ की अवधारणा से जोड़ना भी अनिवार्य है। जल आपूर्ति की सफलता केवल ‘कनेक्शन की संख्या’ से नहीं, बल्कि जल की गुणवत्ता, निरंतरता और पारदर्शिता से मापी जानी चाहिए। स्थानीय निकायों को तकनीकी क्षमता, वित्तीय संसाधन और उत्तरदायित्व, तीनों स्तरों पर सशक्त किए बिना यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इस दिशा में समन्वित प्रयास करने होंगे। नागरिकों की भूमिका इस संकट में गौण नहीं है। जल उपयोग, संरक्षण और निगरानी को सामुदायिक उत्तरदायित्व के रूप में विकसित करना होगा। स्थानीय स्तर पर जल परीक्षण, शिकायत निवारण और सामाजिक परीक्षण जैसी प्रक्रियाएं इस दिशा में प्रभावी साधन बन सकती हैं। जल केवल सरकार द्वारा प्रदत्त सेवा नहीं, बल्कि समाज की साझी संपदा है और उसकी सुरक्षा भी सामूहिक प्रयास से संभव है।

इंदौर की त्रासदी एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही यह अवसर भी है उस सोच को बदलने का, जिसमें जल संकट को केवल भविष्य की समस्या माना जाता रहा है। यदि आज भी जल की गुणवत्ता, अवसंरचना और स्थानीय निगरानी को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो ऐसी घटनाएं अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य होती जाएंगी। जल संकट अब केवल पर्यावरणीय या तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और शासन की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुका है। भारत के लिए यह समय आत्ममंथन का है। जल प्रबंधन को आंकड़ों और घोषणाओं से आगे बढ़ा कर जमीन पर, गली-मोहल्ले के स्तर पर उतारने की आवश्यकता है। अन्यथा, हर शहर संभावित इंदौर बन सकता है और तब चेतावनियां का मूल्य केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि जनहानि के रूप में चुकाना पड़ेगा।

सुरक्षा की चिंता

‘लक्षित हिंसा’ (संपादकीय, सात जनवरी) पढ़ा। यह बेहद ही दुःखद है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बर्बर सलूक किया जा रहा है। अब तक कई लोगों की हत्या की जा चुकी है और यह सिलसिला जारी है। वहां हिंसक भीड़ निरंकुश तरीके से पेश आ रही है। बांग्लादेश की सरकार भी इस अराजकता पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। यह निराशाजनक है कि हमारी सरकार बांग्लादेश को कोई ठोस कार्रवाई करने का संदेश देने में देर कर रही है। भारत को अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के समक्ष यह मुद्दा प्रमुखता से उठाना चाहिए। बांग्लादेश का अस्तित्व भारत के प्रयासों से ही संभव हुआ और यह ऐसा एहसान है, जिसका ऋण बांग्लादेश कभी नहीं चुका सकता। वहां की जनता को भी यह सच्चाई कभी नहीं भूलनी चाहिए। आइडिपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के बहिष्कार जैसे हल्के कदमों से वहां की सरकार की तंत्र नहीं टूटेगी। भारत को ठोस कूटनीतिक प्रयासों से वहां किसी भी तरह अनियंत्रित हिंसा को अविलंब रुकवाना चाहिए।

- इशरत अली कादरी, भोपाल

निष्पक्षता पर सवाल

पिछले कुछ वर्षों से केंद्रीय जांच एजंसियों, खासकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भूमिका को लेकर लगातार बहस होती रही है। विपक्ष का आरोप है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने और चुनौती फायदे के लिए किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति से जुड़ी संस्था पर एक बार हलिया कार्रवाई इसी बहस को एक बार फिर तेज करती है। कुछ महीने बाद होने वाले बंगाल

समय का पाठ

समय कभी गुरु बन कर हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाता है, कभी परीक्षा-निर्णायक बन कर हमारे कायों की गुणवत्ता को उजागर करता है, और कभी दार्शनिक बन कर हमें मूल्य और नश्वरता का बोध कराता है। जिन्होंने समय की इस भाषा को समझा, वे युग-निर्माता बने। उन्होंने अपने विचारों, कर्मों और संघर्षों के समय की धारा के साथ सामंजस्य में रखा और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। ऐसे कई लोग हैं, जो समय के विरुद्ध नहीं,

- समराज चौहान, सिलवर, असम

ताकत का वर्चस्व

वे नेजुएला के राष्ट्रपति को बलपूर्वक पकड़ कर अपने नियंत्रण में लेने की घटना और ग्रीनलैंड को हथियाने की लालसा, अमेरिका की वर्चस्ववादी मानसिकता को उजागर करती है। यह आचरण न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवता और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सिद्धांतों के भी सर्वथा विपरीत है। यह वही मानसिकता है, जो सभ्यता के प्रारंभिक दौर में कबीलों के बीच देखने को मिलती थी, जहां शक्ति ही न्याय का पैमाना होती थी और ताकतवर का वर्चस्व ही अंतिम सत्य माना जाता था। चिंताजनक तथ्य यह भी है कि अमेरिका चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर पांच सौ फीसद शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे उसकी मंशा पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि वह निष्पक्ष प्रतियर्था में नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति में विश्वास रखता है।

- खुमानसिंह चुंडावत, मंदसौर

वेनेजुएला के घटनाक्रमों से तेल की कीमतें प्रभावित होने के आसार नहीं: क्रिसिल रेटिंग्स

क्रिसिल रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा कि वेनेजुएला के हालिया घटनाक्रमों से कच्चे तेल की कीमतों पर निकट भविष्य में कोई ठोस प्रभाव पड़ने के आसार नहीं है क्योंकि वैश्विक आपूर्ति में इस लातिन अमेरिकी देश की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत बेहद कम है। जनवरी की शुरुआत में अमेरिकी सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मादक पदार्थों से जुड़े आरोपों में पकड़ लिया गया था। इस घटना ने देश में अनिश्चितता उत्पन्न कर दी। वेनेजुएला के पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े प्रमाणित कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने बयान में कहा कि यदि स्थिति बिगड़ती भी है और वेनेजुएला में कच्चे तेल का उत्पादन बाधित होता है, तब भी वैश्विक तेल कीमतों पर इसका प्रभाव सीमित रहने का अनुमान है। भारत के संदर्भ में, वेनेजुएला के घटनाक्रमों का उसके वैश्विक व्यापार या भारतीय कंपनियों की साख पर कोई खास प्रभाव पड़ने का अनुमान नहीं है।

केंद्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की संख्या कम हुई

सुशील राघव

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत देश भर में चलने वाले 1,256 केंद्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या में एक वर्ष की कमी दर्ज की गई है। 31 दिसंबर, 2024 को केंद्रीय विद्यालयों में एससी विद्यार्थियों की संख्या 2,83,592 थी जो केंद्रीय विद्यार्थियों में उस समय पढ़ रहे विद्यार्थियों का 20.39 फीसद थी। 31 दिसंबर, 2025 को इन विद्यालयों में पढ़ने वाले एससी वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या कम होकर 2,63,332 हो गई जो कुल विद्यार्थियों का 19.49 फीसद ही रह गई।

केंद्रीय विद्यालयों का संचालन करने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) की वार्षिक रपट के मुताबिक इस एक वर्ष के दौरान केंद्रीय विद्यालयों में एससी वर्ग के 20,260 विद्यार्थियों (0.9 फीसद) की कमी हुई। रपट के मुताबिक इस अंतराल में अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांग वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। रपट के अनुसार एसटी वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या में पिछले एक वर्ष में 6.70 फीसद से 6.74 फीसद हो गई। ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 27.94 फीसद से 32.29 फीसद और दिव्यांग वर्ग वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 0.49 फीसद से 0.59 फीसद पहुंच गई।

रपट के मुताबिक इस अंतराल में कुल विद्यार्थियों की तुलना में छात्रों के फीसद में कमी और छात्राओं के फीसद वृद्धि भी दर्ज की गई है। 31 दिसंबर, 2024 को केंद्रीय विद्यालयों में 53.45 फीसद (7,43,217) छात्र पढ़ रहे थे जबकि 31 दिसंबर, 2025 को पढ़ने वाले छात्रों का फीसद घटकर 53.14 फीसद (7,18,113) हो गई। छात्राओं की बात करें तो रपट के मुताबिक 31 दिसंबर, 2024 को 46.55 फीसद (6,47,300) छात्राएं केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रही थीं जबकि 31 दिसंबर, 2025 को पढ़ने वाली छात्राओं का फीसद बढ़कर 46.86



फाइल फोटो

तीन वर्षों में 5.50 फीसद से ज्यादा विद्यार्थियों में आई कमी

केंद्रीय विद्यालयों में तीन वर्षों से लगातार विद्यार्थियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। वार्षिक रपट के मुताबिक 2021-22 में जहां विद्यार्थियों की कुल संख्या 14,30,442 थी, वहीं यह संख्या 2024-25 में घटकर 13,51,446 हो गई है। यह कमी 5.50 फीसद से अधिक की रही। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र और छात्राओं का अनुपात 1:0.88 है। इस दौरान देश में आठ नए केंद्रीय विद्यालय खोले गए।

केंद्रीय विद्यालयों में वर्षवार कुल विद्यार्थियों की संख्या

वर्ष	केंद्रीय विद्यालय	कुल विद्यार्थी
2021-22	1248	14,30,442
2022-23	1252	14,25,164
2023-24	1254	13,90,517
2024-25	1256	13,51,446

(6,33,333) हो गया। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षाकेंद्रीय विद्यालयों में सभी नए प्रवेशों के लिए अनुसूचित जाति के लिए 15 फीसद, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसद सीटें और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-एनसीएल) के लिए 27 फीसद सीटें आरक्षित हैं। उपलब्ध सीटों का तीन फीसद दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है।

सबसे अधिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में

केंद्रीय विद्यालयों की मौजूदगी देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 122 केंद्रीय विद्यालय हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश 112 विद्यालय हैं। इन दोनों प्रदेशों में ही 100 से अधिक केंद्रीय विद्यालय हैं। इसके अलावा राजस्थान में 77, ओड़ीशा में 67, पश्चिम बंगाल में 62, महाराष्ट्र में 59, कर्नाटक में 52, गुजरात व दिल्ली में 46-46 केंद्रीय विद्यालय हैं। केंद्रीय शासित प्रदेश लक्ष्यद्वीप में केवल एक केंद्रीय विद्यालय है।

पंकज रोहिला

आ

म जनता की सुविधा के लिए केंद्र सरकार जल्द ही मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) में बदलाव करेगी। इन बदलावों से परिवहन संबंधित कामकाज की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। नई तकनीक विकसित हो जाने के बाद इन संशोधनों की जरूरत महसूस की जा रही है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक इन कानूनों में संशोधन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत होगी। इस मंजूरी से पहले से संशोधन कानून केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली विशेष समिति के सामने पेश किए जाएंगे। इससे कामकाज की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी।

हाल ही में देश भर के परिवहन मंत्रियों की बैठक में ऐसे करीब 61 संशोधन सामने आए हैं। नई तकनीक के आने के बाद जिन पुराने प्रावधानों में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। उन विभागों सड़क सुरक्षा, आम जनता से जुड़ी आन लाइन सेवाएं, नई प्रक्रियाएं और कई अन्य अधिनियम शामिल हैं। इन अधिनियम के माध्यम से ही देश भर में परिवहन मंत्रालय से संबंधित कार्य प्रक्रिया और व्यवस्थाओं को संचालित किया जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक ऐसे 58 प्रावधानों को चिन्हित किया जा चुका है। इन प्रावधानों के आधार पर नए प्राकृत तैयार किए जाएंगे। इसका मकसद आम जनता को एक ही जगह पर तमाम परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराना होगा। अभी तक विभिन्न अधिनियम के माध्यम से इन सेवाओं को संचालित किया जा रहा है।

मंत्रालय भविष्य में जिन व्यवस्थाओं को लागू करने की तैयारी कर रहा है, उनमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए अंक आधारित प्रणाली की शुरुआत करना, एक निश्चित भार तक के सभी माल वाहकों के लिए वाहन परमिट और इस पूरे तंत्र की निगरानी के लिए डिजिटल तंत्र स्थापित करना है। इसके अलावा देश में वाहनों के लिए एचएसआरपी की व्यवस्था सरकार पहले ही कर चुकी है। इसे मजबूत बनाने के लिए अधिनियम की धारा 192 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई को और अधिक मजबूत किया जाए। वर्तमान में इसके लिए सख्त



केंद्र सरकार कर रही है मोटर वाहन अधिनियम में व्यापक संशोधन की तैयारी

पुराने प्रावधानों को हटाकर उसकी जगह सरकार नए प्रावधान लाने की कर रही तैयारी

जल्द राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली विशेष समिति के समक्ष पेश होगी मसविदा

बदलाव

प्रावधान नहीं होने की वजह से वाहन चालक इसमें बदलाव कर रहे हैं, जिससे यह व्यवस्था कमजोर होती जा रही है।

मंत्रालय के मुताबिक दुनिया भर में सड़क सुरक्षा से संबंधित कानूनों का पाठ बच्चों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है। इसी तर्ज पर केंद्र सरकार व शिक्षा मंत्रालय ने भी एक पहल शुरू की है। सड़क सुरक्षा संबंधित अधिनियम व प्रावधान को शिक्षण प्रक्रिया से जोड़ा गया है। परिवहन क्षेत्र से संबंधित जरूरी शिक्षण जानकारीयों को कक्षा एक से पांच तक से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस पहल की मदद से बच्चों को जरूरी जानकारीयें बचपन से ही मिल पा रही हैं और भविष्य में इनकी मदद से सड़क अनुशासन व्यवस्था को लागू करने में बड़ी मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर के मंत्रियों के साथ हुई बैठक में यह रणनीति तैयार की है। मंत्रालय की योजना है कि मंत्रालय से संबंधित 100 से अधिक आन लाइन परिवहन सेवाओं को एकीकृत किया जाए, जिसमें अंतर राष्ट्रीय सेवाएं जैसी एनओसी और स्वामित्व हस्तारण जैसी सेवाओं को इस दायरे में रखा गया है। इसके अतिरिक्त देश भर में वाहन चालकों का आंकड़ा एक साथ उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय डेटा साझाकरण ढांचा तैयार किया जाएगा।

दिमाग को दुरुस्त रखने में जैविक घड़ी की अहम भूमिका

जनसत्ता ब्यूरो

मा

नव शरीर में मौजूद 24 घंटे की जैविक घड़ी चुपचाप यह समन्वय करती है कि हम कब सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं और आराम करते हैं। यह आंतरिक समय प्रबंधन प्रणाली अंगों और हार्मोन को तालमेल बैठाकर काम करने में मदद करती है। हालांकि, जब जैविक घड़ी अव्यवस्थित हो जाती है, तो इसके प्रभाव खराब गुणवत्ता वाली नींद से कहीं अधिक व्यापक हो सकते हैं और ढलती उम्र में दिमागी सेहत में गिरावट का कारण भी बन सकते हैं। साल 2025 में 79 वर्ष की औसत आयु वाले दो हजार से अधिक बुजुर्गों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों की जैविक घड़ी अधिक व्यवस्थित होती है, उनके डिमेंशिया की चपेट में आने का जोखिम लगभग 50 फीसदी तक घट जाता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम, खासकर खुले वातावरण में और दोपहर से पहले, जैविक घड़ी को व्यवस्थित रखने और डिमेंशिया का जोखिम घटाने में मददगार साबित हो सकता है। पार्क में चहलकदमी और ध्यान लगाना दिमागी सेहत को दुरुस्त रखने के सबसे आसान और कारगर तरीकों में शामिल है।

अध्ययन

क्यों अहम है जैविक घड़ी : जैविक घड़ी सोने का समय, हार्मोन का उत्पादन, हृदयगति और शरीर का तापमान सहित कई अन्य दैनिक शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। अव्यवस्थित जैविक घड़ी को अक्सर नींद की खराब गुणवत्ता से जोड़ा जाता है। विभिन्न अध्ययनों में खराब गुणवत्ता वाली नींद का डिमेंशिया और दिल की बीमारियों के बढ़ते जोखिम से सीधा संबंध पाया गया है। साल 2025 में किए गए अध्ययन में प्रतिभागियों की दिल की सेहत और रक्तचाप का भी विश्लेषण किया गया, जो अन्य कारकों के साथ-साथ नींद की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं।



जिन लोगों की जैविक घड़ी अधिक व्यवस्थित होती है, उनके डिमेंशिया की चपेट में आने का जोखिम लगभग 50 फीसदी तक घट जाता है। रोजाना 30 मिनट का सुबह व्यायाम और दोपहर से पहले, जैविक घड़ी को व्यवस्थित रखने और डिमेंशिया का जोखिम घटाने में मददगार साबित हो सकता है।

क्या है जैविक घड़ी : जैविक घड़ी (बायोलॉजिकल क्लॉक) शरीर की वह आंतरिक प्रणाली है जो नींद-जागने के चक्र, हार्मोन उत्पादन और चयापचय (मेटाबॉलिज्म) जैसी शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, यह बाहरी रोशनी और अंधेरे के अनुसार लगभग 24 घंटे के चक्र में काम करती है, और इसे मस्तिष्क में मौजूद सुपरचियास्मैटिक न्यूक्लियस (एससीएन) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

शारीरिक निष्क्रियता घातक : नए अध्ययन से पता चलता है कि नींद में खलल से उठजने वाली थकान से पैदा शारीरिक निष्क्रियता को दूर करना ढलती उम्र में दिमाग को दुरुस्त रखने का कारगर तरीका हो सकता है। दरअसल, शारीरिक सक्रियता बढ़ाने से न सिर्फ वजन नियंत्रित रखने और मोटापा घटाने में मदद मिलती है, बल्कि नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं में क्षरण की गति भी धीमी हो जाती है। अव्यवस्थित जैविक घड़ी और डिमेंशिया के बीच संबंधों के पीछे प्रतिरक्षा तंत्र का भी हाथ हो सकता है। विभिन्न अध्ययनों में देखा गया है कि व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता उसकी नींद की गुणवत्ता और जैविक घड़ी

महोत्सव



कुरमाली आदिवासी समुदाय ने मंगलवार को रांची में टुसू त्योहार से पहले मोरहाबादी मैदान में टुसू महोत्सव मनाया।

कमजोर वर्गों के बच्चों का स्कूलों में प्रवेश राज्य का दायित्व

जनसत्ता ब्यूरो

यु

कमजोर और वंचित वर्गों के छात्रों को आस-पड़ोस के स्कूलों में प्रवेश से मना न किया जाए। बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ब) की व्याख्या करते हुए न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और

प्रीम कोर्ट ने कहा है कि संबंधित राज्य सरकारों व स्थानीय अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के छात्रों को आस-पड़ोस के स्कूलों में प्रवेश से मना न किया जाए। बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ब) की व्याख्या करते हुए न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और

सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति एस चंद्रकर की पीठ ने यह अहम व्यवस्था दी है। पीठ ने यह भी कहा है कि आस-पड़ोस के स्कूलों की भी यह समान जिम्मेदारी है कि वे आरटीई कानून और संविधान के अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार) के तहत अनिवार्य रूप से 25 फीसद छात्रों को प्रवेश दें। पीठ ने इस बाबत कई निर्देश जारी किए हैं व मामलों को अनुपालन के लिए लॉन्च रखा है। पीठ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी एक पक्ष बनाया है और उसे हलफनामा दाखिल करने को कहा है। धारा 12(1)(ब) के अनुसार, निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान और विशेष श्रेणी के स्कूल कक्षा एक या प्री-

प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के कम से कम 25 फीसद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। ऐसे स्कूलों को सरकार द्वारा प्रति बच्चा खर्च के हिसाब से अनुदान मिलेगा।

पीठ ने कहा-अधिनियम की धारा 12 के तहत कक्षा की कुल संख्या के 25 फीसद तक समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को प्रवेश देने की आस-पड़ोस के स्कूलों की जिम्मेदारी में समाज की सामाजिक संरचना को बदलने की असाधारण क्षमता है। ईमानदारी से लागू करने से यह सच में बदलाव ला सकता है। यह न केवल युवा भारत को शिक्षित करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि स्थिति की समानता के प्रस्तावना उद्देश्य को सुरक्षित करने का एक ठोस उपाय भी है।

बिगड़ते पर्यावरण के बीच प्रवासी पक्षियों ने राह बदली, देरी से पहुंच रहे

सुनील दत्त पांडेय

बि

गड़ते पर्यावरण के चलते प्रवासी पक्षियों ने अपनी राह बदल दी है। उन्होंने केवल राह ही नहीं बदली बल्कि अपने आगमन के समय और तिथि में भी परिवर्तन किया है। इस बार विदेश से प्रवासी पक्षी जलवायु परिवर्तन के कारण एक पखवाड़ की देरी से उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में पहुंचे। पक्षी विज्ञानी और पर्यावरणविद प्रोफेसर दिनेश भट्ट इसकी वजह जलवायु परिवर्तन मान रहे हैं। प्रोफेसर भट्ट का कहना है कि रूस, मध्य एशिया, स्कैंडिनेवियाई और यूरेशियाई देशों से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके प्रवासी पक्षी हर साल नवंबर-दिसंबर के महीने में हरिद्वार में नीलधारा, मिस्सरपुर आदि स्थानों पर गंगा के तट पर आते हैं।

प्रवासी पक्षियों में प्रवास एक प्राकृतिक पड़ाव है। बहुत ज्यादा ठंड के महीनों में प्रवासी पक्षी अपने देश में ठंड बढ़ने के कारण भारत आते हैं, परंतु इस बार लंबे मानसून के मौसम और जलवायु परिवर्तन के चलते एवं पिछले साल नवंबर-दिसंबर में बारिश-बर्फबारी न होने के कारण प्रवासी

पक्षी विशेषज्ञ प्रोफेसर बी जोशी का कहना है कि रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध ने भी साइबेरियाई क्षेत्र से प्रवासी पक्षियों की आवाजही पर गहरा असर डाला है। चार वर्षों से लगातार बमबारी के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, जिससे जलवायु प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत खतरनाक हो गई है। रूस-यूक्रेन की तरफ से अपने मूल निवास स्थान से हरिद्वार तक लंबी उड़ान भरने वाले पक्षियों की तादाद पिछले कई सालों के मुकाबले अत्यधिक कम रही है।

जलवायु

पक्षी रूस, मंगोलिया, साइबेरिया की तरफ से उत्तराखंड में 15 से 20 दिन की देरी के बाद पहुंचे। जाड़ों के समय में स्कैंडिनेवियाई और यूरोपीय देशों के ज्यादा हिस्सों में कई दिनों तक भारी बर्फबारी होती है। इसलिए ये पक्षी कई देशों और हिमालय को पार करके उत्तरी भारत के निचले इलाकों, खासकर उत्तराखंड में नवंबर के आखिरी और दिसंबर-



जनवरी की शुरुआत में पहुंचते हैं। अंतरराष्ट्रीय पक्षी वैज्ञानिक और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के जंतु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के पूर्व प्रोफेसर डा. दिनेश भट्ट बताते हैं कि रूस, मध्य एशिया स्कैंडिनेवियाई यूरोपीय देशों में पक्षियों को बर्फबारी के कारण खाना मिलने में दिक्कत होती है और इसलिए वे हजारों किलोमीटर की यात्रा करके

कम ठंडे इलाकों में पहुंचते हैं। वसंत ऋतु की शुरुआत में तापमान बढ़ने पर प्रवासी पक्षी फरवरी के आखिर और मार्च की शुरुआत में अपने मूल स्थान पर लौट जाते हैं। भारत में आने वाले ज्यादातर प्रवासी पक्षी यूरोप और मध्य एशिया से आसमान में केंद्रीय हवाई मार्ग से आते हैं और उसी रास्ते से वापस जाते हैं। वह कभी अपना रास्ता नहीं भटकते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है कि साइबेरियाई केन पक्षियों के झुंड उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे काफी तादाद में आते थे। प्रोफेसर भट्ट इसका कारण जलवायु परिवर्तन मानते हैं। प्रोफेसर भट्ट का कहना है कि उन्होंने हरिद्वार की झिलमिल झील, देहरादून विकास नगर क्षेत्र में स्थित आसन बैराज और डाक पथर तथा ऋषिकेश में पशु लोक बैराज, पौड़ी गढ़वाल जिले में लैंसडाउन, कोटद्वार-कोलहू नदी का किनारा-राजाजी टाइगर रिजर्व, काबेट टाइगर रिजर्व, बद्रीनाथ मंदिर-शेष नेत्र झील-माण्डा पास और अन्य ऊंचे इलाकों में प्रवासी पक्षियों को लेकर विशेष अध्ययन किया है, यहां पर कई सालों से प्रवासी पक्षी लगातार आते हैं। पक्षी प्रेमी संदीप रावत ने बताया कि प्रवासी पक्षियों को इस महीने के आखिर में पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार एवं लैंसडाउन में दो दिवसीय स्नेह पक्षी महोत्सव में भी देख सकते हैं यह पक्षी महोत्सव इस साल 31 जनवरी एवं 1 फरवरी तक आयोजित होगा।

सेना का एक अधिकारी भाजपा के इशारे पर पुनरीक्षण का काम कर रहा : ममता

कोलकाता, 13 जनवरी (भाषा)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि फोर्ट विलियम स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय में तैनात कमांडेंट रैंक के एक अधिकारी भाजपा के इशारे पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का काम कर रहे हैं। अधिकारी की पहचान के बारे में और अधिक जानकारी दिए बिना मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सेना का यह अधिकारी राज्य में मतदाता सूचियों के विवादस्पद एसआइआर के मद्देनजर कमांड बेस का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहा है।

राज्य सचिवालय (नबान्न) में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बनर्जी ने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि फोर्ट विलियम में कमांडेंट रैंक के अधिकारी भाजपा को समर्थन देने के लिए एसआइआर पर काम कर रहे हैं।



दौरा	लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में स्थित एक स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए।
-------------	--

चीन को चुनौती देने के लिए निर्माण क्षेत्र मजबूत करना होगा : राहुल गांधी

नई दिल्ली, 13 जनवरी (ब्यूरो)।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत ने आईटी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कृत्रिम मेधा के कारण यह क्षेत्र आने वाले समय में चुनौतियों का सामना करेगा। ऐसे में भारत को निर्माण क्षेत्र को मजबूत करना होगा ताकि चीन के वर्चस्व को चुनौती दी जा

पेज 1 का बाकी सरकार का फैसला, दस मिनट में सामान पहुंचाने के दावों पर रोक

आय की ओर ध्यान आकर्षित किया।इस मुद्दे पर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्लिंकिट, जेटो, रिवगी और जोमेटो के अधिकारियों से बातचीत की थी। बैठक में वितरणकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और समय सीमा हटाने की बात कही गई थी। सरकार ने कंपनियों को स्पष्ट संदेश दिया कि तेज वितरण के दबाव में वितरणकर्ताओं की जान जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद सभी कंपनियों ने आश्वासन दिया कि वे अपने विज्ञापनों और सोशल मीडिया पोस्ट से वितरण की समय सीमा हटाएंगी।

हाल के संसद सत्र में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भारत के गिग वर्कर्स की परेशानियों के बारे में आवाज उठाई थी। ‘गिग वर्कर्स एसोसिएशन’ ने मंगलवार को त्वरित व्यापार मंच द्वारा दस मिनट में सामान देने के वादे को वापस लेने के फैसले का स्वागत किया, और कहा कि यह कदम इस बात को मानता है कि वितरण की बहुत कम समय सीमा कर्मियों पर असुरक्षित दबाव डालती है। एसोसिएशन ने कहा कि दस मिनट की डिलीवरी माडल ने कर्मियों को जल्दबाजी करने, सड़क पर जोखिम लेने और एम्प पर इंस्टॉल, रेटिंग

राज्यों को भारी मुआवजा देना होगा : सुप्रीम कोर्ट

लिए भी तर्क दे पाता। मुझे 2011 में जज नियुक्त किया गया था। लेकिन मैंने इंसानों के लिए इतने भावुक तर्क कभी नहीं सुने। उन्होंने पूछा कि अगर कोई आवारा कुत्ता किसी पर हमला कर दे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वकील ने जवाब दिया कि स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि आवारा कुत्ता किसी के कब्जे में नहीं होना चाहिए। अगर आप पालतू जानवर रखना चाहते हैं, तो लाइसेंस लें।न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा- अगर किसी बच्चे या बुजुर्ग को कुत्ते काटते हैं या उनकी मौत होती है, तो राज्य से भारी मुआवजा

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सेना का यह अधिकारी राज्य में एसआइआर के मद्देनजर कमांड बेस का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहा है।

राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री के बयान की पुष्टि करने के बाद मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही। बोस ने कहा, मुझे पहले

स्वयं यह सत्यापित करने दीजिए कि उन्होंने क्या कहा। यदि इससे किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो मैं निश्चित रूप से हस्तक्षेप करूंगा। राज्य के पहले से ही तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में बनर्जी की इस टिप्पणी पर सभी दलों से तीखी राजनीतिक

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल होसबाले से मिला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 जनवरी।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली के केशव कुंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकायवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। यह मुलाकात राजधानी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं के साथ बातचीत के एक दिन बाद हुई।

आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी। अनुरोध चीन की तरफ से आया था और हमने इसे मान लिया। आरएसएस मुख्यालय में हुई इस बैठक का कोई एजेंडा नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन के प्रमुख मोहन भागवत मौजूद नहीं थे क्योंकि वे यात्रा कर रहे थे। यह बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि

नितिन नबीन अगले सप्ताह अध्यक्ष पद के लिए कर सकते हैं नामांकन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 जनवरी।

भारतीय जनत पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के अगले सप्ताह पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने की संभावना है। बिहार के पांच बार के विधायक को पिछले साल 14 दिसंबर को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो सत्तारूढ़ दल में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है। उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना है क्योंकि पार्टी के किसी अन्य नेता की दावेदारी की संभावना नहीं के बराबर है।

भाजपा के एक सूत्र ने बताया, ‘चुनाव के लिए नामांकन 19 जनवरी को दाखिल किया जाएगा।’ सूत्रों के मुताबिक, यदि जरूरत पड़ी तो चुनाव यहां पार्टी मुख्यालय में कराया जाएगा। पूर्व में, भाजपा

दिल्ली में पंद्रह साल की सबसे सर्द सुबह, पारा गोता लगाकर तीन डिग्री पर

बुधवार को दिल्ली के लिए शीतलहर व बहुत घने कोहरे की ‘नारंगी चेतावनी’ जारी की है। पंजाब और हरियाणा में मंगलवार को भीषण ठंड रही। सुबह घनी धुंध के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में 11 जनवरी, 2017 को न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस और 24 जनवरी, 2016 को न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पंजाब के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ी। बटिंडा में न्यूनतम तापमान

पाक के खिलाफ जमीनी सैन्य अभियान को तैयार : सेना प्रमुख

100 से 150 आतंकवादी मौजूद हैं। सेना प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि शक्सगाम घाटी भारत की है। पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से कब्जा किए गए शक्सगाम घाटी के 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया था। भारत पाकिस्तान और चीन के बीच हुए 1963 के समझौते को अवैध मानता है। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है लेकिन पूरी

रद्द हो : न्यायमूर्ति नागरत्ना, वैध : न्यायमूर्ति विश्वनाथन

विचार किया जा सके।’ एनजीओ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि यह प्रावधान भ्रष्टाचार विरोधी कानून को कमजोर करता है, क्योंकि सरकार से अक्सर मंजूरी नहीं मिलती, जबकि वही इस कानून के तहत ‘सक्षम प्राधिकारी’ है।

केंद्र सरकार की ओर से सलितसरु जनरल तुमार मेहता ने अदालत में पक्ष रखा।पीठ ने इस मामले की सुनवाई 6 अगस्त, 2025 को पूरी कर अपना फैसला सुनिश्चित रखा था। जो करीब छह

प्रतिक्रियाएं आई हैं। भाजपा की बंगाल इकाई के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बनर्जी की टिप्पणी पर तंज करते हुए कहा, वह पश्चिम बंगाल को भारत का एक राज्य नहीं मानतीं, वह बंगाल को एक संप्रभु राष्ट्र और खुद को उसकी राष्ट्रपति समझती हैं। बनर्जी के आरोप को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (मार्कपा) के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने ‘गंभीर मुद्दा’ बताया।

निर्वाचन आयोग ने एकतरफा तरीके से 54 लाख नाम हटाए : ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान 54 लाख नाम एकतरफा तरीके से और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईंआरओ) की शक्तियों का दुरुपयोग करके हटाए गए। ममता ने दावा किया कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गए, उनमें से ज्यादातर वास्तविक मतदाता थे, जिन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस ने केंद्र में सत्तारूढ़ दल पर चीन के प्रति अपनी नीति में पाखंड दिखाने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या वह इस तरह के दौरों के दौरान बार-बार होने वाले चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाती है। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से उसकी चीन नीति पर पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करती है।

हाल के वर्षों में आरएसएस और चीनी प्रतिनिधियों के बीच बहुत कम बातचीत हुई है। खास बात यह है कि पिछले वर्ष अगस्त में मोहन भागवत की व्याख्यान शृंखला के दौरान, संघ ने चीनी

भाजपा के सूत्रों के मुताबिक, उनका निर्विरोध चुने जाने की संभावना है क्योंकि पार्टी के किसी अन्य नेता की दावेदारी की संभावना नहीं के बराबर है।

भाजपा के सूत्रों के मुताबिक, उनका निर्विरोध चुने जाने की संभावना है क्योंकि पार्टी के किसी अन्य नेता की दावेदारी की संभावना नहीं के बराबर है।

के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी जून 2019 में पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और फिर 20 जनवरी 2020 को निर्विरोध चुने जाने के बाद उन्होंने अमित शाह की जगह ली थी।

नितिन नबीन (45) भाजपा के पूर्व विधायक नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से भी जुड़े रहे हैं। नबीन बिहार में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और बिहार सरकार में दो बार मंत्री रहे हैं।

नई दिल्ली सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया, बहाली के लिए संघर्ष जारी : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 जनवरी।

कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया और लोगों से अपने ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ में शामिल होने का आग्रह किया। कांग्रेस ने ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ को काम, मजदूरी और जवाबदेही के संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष करार दिया।

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ देशभर की 25 लाख ग्राम पंचायतों और करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। इसके अलावा उन्होंने ‘काम मांगो अभियान’ पर निर्देश और मनरेगा पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक वीडियो बयान साझा किया है।

उन्होंने हिंदी में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘सरकार ने मनरेगा योजना को कुचल दिया है, जो भारत में करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा बन चुकी है। यह राष्ट्रव्यापी संघर्ष इसी के खिलाफ है, काम, मजदूरी और जवाबदेही के संवैधानिक अधिकारों

भाजपा का पलटवार

भाजपा ने मंगलवार को कहा कि उसने नई दिल्ली और बेजिंग के बीच संबंधों में सुधार के मद्देनजर एक चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ खुले तौर पर औपचारिक बैठक की। भाजपा ने आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी ने 2018 में बेजिंग में सोनिया गांधी और चीनी राष्ट्रपति शी जिंपिंग की उपस्थिति में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक गुप्त एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे।

राजनयिकों को आमंत्रित नहीं किया था, जबकि कई दूसरे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उस समय यह फैसला आयरेशन सिंदूर से जुड़ा था, जिसके बाद न तो पाकिस्तान और न ही चीन को आमंत्रित

हिमाचल के शासक बनने की कोशिश न करें बाहरी अधिकारी : विक्रमादित्य

शिमला, 13 जनवरी (ब्यूरो)।

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की एक टिप्पणी राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में माहौल गरमा गया है। विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट कर कहा, हम उपमुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मंडी के अधिभाषण से सहमत हैं।

कुछ यूपी-बिहार के आला आइएस-आइपीएस अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन अफसरों को हिमाचल से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। समय रहते हुए उनसे निपटने की आवश्यकता है, नहीं तो हिमाचल के हित निपट जाएंगे।सिंह ने कहा, हम बाहर के राज्य

की बहाली के लिए है।’ उन्होंने लोगों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। रमेश ने पोस्ट में एक लिंक साझा किया जिसके माध्यम से लोग ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ में शामिल हो सकते हैं। अभियान में शामिल होने वाले लोग पोर्टल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी जाने वाली एक याचिका पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। याचिका में लिखा है, ‘हम मनरेगा में हाल ही में किए गए उन बदलावों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराते हैं, जिनसे गारंटीशुदा रोजगार और ग्रामीण सशक्तीकरण के इसके मूल वादे को कमजोर किया जा रहा है।

मनरेगा परीचरों का संवैधानिक श्रम अधिकार है और इसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। हमारी मांगें हैं- काम की गारंटी बहाल की जाए, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन की जाए, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाया जाए, हम मनरेगा में निहित भावना और उसके उद्देश्य की रक्षा के लिए आपके तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह करते हैं।’ वेणुगोपाल ने कहा कि इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र शीघ्र ही साझा किया जाएगा।

किया गया था। इससे पहले सोमवार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा मुख्यालय आया था। इसका नेतृत्व पार्टी के विदेश विभाग की उपमंत्री सुन हैयान ने किया था। बैठक के दौरान भाजपा प्रतिनिधिमंडल की अगुआई राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने की और इसमें भाजपा और सीपीसी के बीच अंतर-दलीय संचार को बढ़ावा देने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। सोमवार को भाजपा कार्यलय का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल में भारत में चीन के राजदूत जू फीहोंग भी शामिल थे।

सूत्रों के मुताबिक 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद दोनों पार्टियों के बीच यह शायद पहली ऐसी बातचीत है। पिछली बार दोनों पार्टियों के बीच ऐसी ही बातचीत साल 2009 में हुई थी, जब भाजपा की अगुआई उसके तत्कालीन अध्यक्ष नितिन गडकरी कर रहे थे।

हिमाचल के शासक बनने की कोशिश न करें बाहरी अधिकारी : विक्रमादित्य

के अधिकारियों का पूर्णतः सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें हिमाचली अधिकारियों से सीख लेने की आवश्यकता है।

हिमाचल के हित के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।। जब तक हिमाचल में हैं, हिमाचल के लोगों की सेवा करें, शासक बनने की गलती न करें। इस टिप्पणी से उपजे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए विक्रमादित्य सिंह कहा कि वे अपनी फेसबुक पोस्ट में कही गई बातों पर कायम हैं। वे व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं हैं। वे हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की संरचना से अच्छी तरह वाकिफ हूं। हालांकि, हिमाचल प्रदेश में तैनात अधिकारी जन प्रतिनिधियां (विधायकों और सांसदों) को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

बंगाल : कोयला खदान में सुरंग धंसने से तीन की मौत, कई दबे

नई दिल्ली, 13 जनवरी (ब्यूरो)।

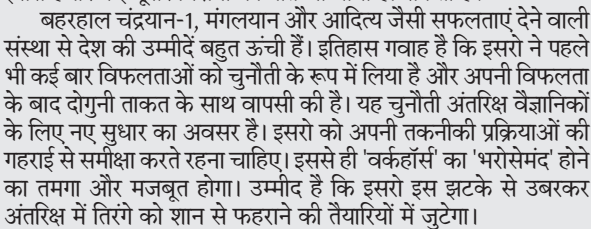
पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले के आसनसोल में कोयला खदान में अवैध खनन के दौरान सुरंग धंसने से बड़ा हादसा हुआ। कुदृती थाना क्षेत्र अंतर्गत बडीरा इलाके में बीसीसीएल की ‘ओपन कास्ट’ कोयला खदान में हुए इस हादसे में अब तक तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आरोप है कि अवैध रूप से कोयला निकालने के दौरान खदान के भीतर बनी सुरंग अचानक धंस गई, जिसमें कई मजदूर दब गए।

सूत्रों के मुताबिक हादसे के वक्त कम से कम 5 से 6 लोग खदान के अंदर मौजूद थे। घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार को मिली जानकारी के मुताबिक, मृतकों में एक महिला भी शामिल है। मृतकों की पहचान गीता बाउरी, सुरेश बाउरी और टिटु बाउरी के रूप में हुई है। वहीं घायल मजदूरों के नाम सुभाष मल्लिक और गोविंद बाउरी बताए जा रहे हैं। प्रशासन को आशंका है कि अब भी एक से दो लोग मलबे अब भी फंसे हो सकते हैं। उन्हें निकालने के लिए ‘पोकलेन’ मशीनों की मदद से तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और सीआइएसएफ की तैनाती की गई है।

महाराष्ट्र : 29 नगर निकायों के लिए कल होगा मतदान

मुंबई, 13 जनवरी (भाषा)।।

महाराष्ट्र में 29 नगर निकाय चुनावों के लिए मंगलवार को प्रचार समाप्त हो गया। सभी की निगाहें मुंबई में बीएमसी के लिए होने वाले बड़े मुकाबले पर टिकी हैं, जहां भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति ठाकरे बंधुओं की चुनौती का सामना कर रहा है। नगर निकायों के 893 वार्ड में फेल्टी 2,869 सीटों के लिए मतदान 15 जनवरी को सुबह 7.30 बजे शुरू होगा और शाम 5.30 बजे संपन्न होगा। कुल 3.48 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतगणना 16 जनवरी को होगी।



से लिए अत्यंत आवश्यक है। अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक ढाल की तरह कार्य करती है। यह दिल्ली-एनपीआई में फैलने वाले प्रदूषण, धूल और मसखरीलाहण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को जारी आदेश पर रोक लगाते हुए अरावली में खनन गतिविधियों पर रोक लगाई है तथा एसएमएफ़ कमेटी गठित किए जाने की भी निर्देश दिए हैं।

आज ज़रूरत है कि राजस्थान अब अरावली क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण, हरियाली और सौर ऊर्जा का संतुलित विकास करके पर्यावरण सुरक्षा का स्थायी मॉडल प्रस्तुत करे। सौर ऊर्जा, पौधोपयोग और प्राकृतिक संचर्चाओं के संरक्षण की संयुक्त नीति ही आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य देने की मजबूत नींव बन सकती है।

निवेश का मतलब भविष्य का अनुमान लगाना नहीं, बल्कि आज सही कीमत चुकाना है। हर दिन ट्रेड करना निवेश नहीं, बेवैनी है।

सेठ क्लारमैन अमरीकी हेज फंड मैनेजर



पेज-1 से जारी...

खोखली निगरानी

लाखों लोग वोटर लिस्ट में घुस गए। बंगाल में तो करोड़ों निकलेंगे। यहां भी वही होने वाला है। क्या यह देश की सुरक्षा का प्रमाण है।

वैसे तो आज लोग त्रस्त हैं माफिया से- हर क्षेत्र में। घुसपैठ की यह समस्या क्या माफिया अथवा तस्करी नहीं है? क्या इसमें सत्ता और पुलिस का पूर्ण सहयोग नहीं है? हालात यह हैं कि बिना आधार कार्ड कोई शहर में रह रहा है और उसका पूरा परिवार सुरक्षित भी है। सरकार उसको भी उतना ही राशन-पानी दे रही है- जितना देश के नागरिक को देती है। शिविर में जगह नहीं देना तो मात्र जनता की आंखों में धूल झोंकना ही है। प्रशासन की देशभक्ति पर गर्व करना चाहिए?

बात सिर्फ बढ़ते अपराधों की ही नहीं, घुसपैठिए प्रोक्ष रूप से देश-प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाते हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार या फिर उचित मेहताना नहीं मिलता तो उसके लिए भी ये लोग जिम्मेदार हैं जो कम पगार पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। जब अवैध रूप से लोगों को बसावट होगी तो आबादी का दबाव भी बढ़ना तय है। आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ाने की एक वजह बढ़ती घुसपैठ है ही। पार्क व दूसरे सार्वजनिक स्थल समाजकंटकों के शरणगाह भी इसीलिए बनते नजर आते हैं।

क्या पुलिस नहीं जानती कि मानव तस्करी के साथ स्थानीय माफिया को सहयोग कौन कर रहे हैं? इनमें अपराधी कौन-कौन है? लड़कियों को भ्रानों के लिए 'कमाई' कौन कर रहे हैं? क्या पुलिस केवल माफिया और देश के दुश्मनों को ही आश्रय देने वाली बन जाएगी? हर जगह देख लो- जेडीए अतिक्रमण ध्वस्त करती है- मीडिया में छाई हुई है। क्या घुसपैठियों की अवैध बसावट की ओर रुख करती है कभी। हमारे जनहित विरोधी जनप्रतिनिधि भी दबाव डालते होंगे। कोर्ट के आदेश भी नकार दिए जाते हैं। शेष क्या रह गया? जनता के नौकर जनता को ही उजाड़ने में व्यस्त हैं। यहाँ कलिंगा है क्या? क्या इन्हीं को समेटने कल्की रूप में नए अवतार प्रकट होंगे? आज तो मानो पृथ्वी ही यमलोक का पूर्ण परिचय दे रही है। सृष्टि का कटु सत्य है कि रावण के वंशजों को भी सजा पानी ही होगी। जो अन्न पेट में जाएगा, वह तो अपना काम करेगा।

गरीबों को राहत देने के बजाए उनके दुःख दर्द बढ़ाने वाले हर फरमान के पीछे मनमानी और भ्रष्टाचार की वू आती है। बड़ा काम घुसपैठियों को रोकने का ही नहीं बल्कि जो घुस आए हैं उन्हें वापस उनके ठिकाने भेजने का भी होना चाहिए। जमीनी स्तर पर सफ़ निगरानी व्यवस्था नहीं हुई तो आधार कार्ड की अनिवार्यता भी खोखली ही बन कर रहने वाली है।

जिस तेजी से भ्रष्टाचार बड़ा हो रहा है, धन बटोरा जा रहा है। लोकतंत्र की खरीद-फरोख्त बढ़ रही है- दुर्घटना, रोग, मौत के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। बढ़ते भी रहेंगे। पुलिस से न्याय की अपेक्षा है। प्रकृति पर न छोड़ा जाए तो देश स्वर्ण बन जाएगा।

पेज वन का शेष...

अफसरों की ...

जिसमें मुख्य चुनौती नवागठित धारा 17ए के खिलाफ थी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर 6 अगस्त, 2025 को फैसला बाद में सुनाने को कहा था।

राजस्थान-एमपी में 'पत्रिका' ने बनाया था मुद्दा, सरकारें हटी थी पीछे

राजस्थान व मध्यप्रदेश में अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सरकार से पूर्वानुमति संबंधी प्रस्तावित विधेयक को 'काला कानून' बताकर 'पत्रिका' ने जनता के बीच मुद्दा बनाया था। राजस्थान में तो तत्कालीन भाजपा सरकार ने अध्यादेश तो जारी किया लेकिन पत्रिका के मुद्दा बनाने के बाद विधानसभा में पेश विधेयक वापस ले लिया गया। मध्यप्रदेश सरकार ने तो कानून बनाने के प्रस्ताव स्तर पर ही कदम पीछे खींच लिए थे।

ट्रंप का ...

भारत ईरान को बासमती चावल, चाय, चीनी, दवाइयों, बिजली उपकरण व इम्पैटेशन आभूषण निर्यात करता है जबकि वहां से सूखे मेवे, केमिकल आयात करता है। बैंधक व अमरीकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने ईरान से तेल खरीदना पहले ही बंद कर दिया है।

कोर्ट ने टैरिफ रह किया तो बर्बाद हो जाएंगे: ट्रंप

ट्रंप के टैरिफ लगाने के अंशिकार को चुनौती पर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुना सकता है। इस पर ट्रंप ने चेतावनी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला देकर टैरिफ रह किया तो गड़बड़ जो

निर्यातकों प्रोब्ले - ज्यादा असर नहीं... निर्यातकों के संगठन एफआईओ के प्रमुख अजय सहाय ने कहा कि नए अमरीकी टैरिफ का भारत पर ज्यादा प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पहले से ही अमरीकी के विदेशी संपत्ति निर्यात कार्यालय (ओएफपीसी) के ईरान पर प्रतिबंधों का पालन कर रहे हैं और खाद्यान्न व दवाओं जैसी अनुमत वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रखी नींव

गांधीनगर में शुरू होगी देश की दूसरी बीएसएल-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी

कहा- खतरनाक वायरस

की जांच में आत्मनिर्भर

बनेगा भारत, विदेशों पर

निर्भरता होगी खत्म

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

अहमदाबाद. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित

शाह ने मंगलवार को गांधीनगर में

गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर

(जीबीआईआरसी) की बीएसएल-4

बायो-कंटेनमेंट फैसिलिटी की नींव

रखी। उन्होंने कहा कि पुणे की

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरलॉजी

(एनआईवी) के बाद यह भारत की

दूसरी उच्च स्तरीय लेब होगी वहीं

किसी राज्य सरकार की ओर से बनाई

जा रही यह पहली लेब है। 140 करोड़

की आबादी में अब तक देश में केवल

एक ही बीएसएल-4 लेब पुणे में थी,

जिसकी वजह से सैकड़ों किलोमीटर

दूर सैपल भेजना पड़ता था। लेकिन

नई बन रही लेब से हमें बड़ा फायदा

होगा। 11 हजार वर्ग मीटर के विशाल

कॉम्प्लेक्स में 362 करोड़ की लागत

से देश की जैविक सुरक्षा का एक

मजबूत किला बनने जा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और विज्ञान



केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से गांधीनगर के गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की बीएसएल-4 बायो-कंटेनमेंट फैसिलिटी तैयार की जा रही है। यहां पशुओं से होकर मानव तक पहुंचने वाले रोगों का भी अध्ययन करने की विश्वस्तरीय व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि एक अध्ययन के अनुसार 60 से 70 प्रतिशत बीमारियां पशुओं से होकर इंसान तक पहुंचती हैं, इसलिए भारत ने वन हेल्थ मिशन के माध्यम

से मानव और पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यक्रम शुरू किया है। अब हमारे वैज्ञानिकों को खतरनाक वायरस के सैपल जांचने के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विदेश पर निर्भरता खत्म होने से जांच में तेजी आएगी और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। बीएसएल-4 सभी जरूरतों की पूर्ति करेगी। हमें रिसर्च-बेड परमानेंट सुरक्षा की दरकार है।

एंटि माइक्रोबियल रिसर्सेस

समाज के लिए बहुत बड़ा संकट:

गृह मंत्री ने कहा कि एंटीबायोटिक

दवाओं के प्रति विकसित हो रही

प्रतिरोधकता हमारी सोसाइटी और पूरी

मानवजाति के सामने बहुत बड़ा

खतरा है।

यह एक 'साइलेंट डिजास्टर' की

तरह है। एंटी माइक्रोबियल रिसर्सेस

(एमआर) पूरे समाज के लिए बहुत

बड़ा संकट है। आने वाले दिनों में और

आने वाली पीढ़ियों के लिए फर्टाइल

ट्रांसमिशन का कारण भी बनता है।

एमआर से निपटने के लिए स्पष्ट

रोडमैप, सही समय पर उपचार व

अंतिम व्यक्ति तक जागरूकता

पहुंचाना जरूरी है।

बायोटेक में आज 10 हजार

स्टार्टअप: केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि

2014 में भारत की बायो इकॉनमी 10

बिलियन डॉलर की थी और वित्तीय

वर्ष 2024 के समाप्त होने तक यह

166 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी

है। 2014 में बायोटेक क्षेत्र में काम

करने वाले स्टार्टअप की संख्या 500

से कम थी, जो 2025 में बढ़कर 10

हजार से अधिक हो चुकी है। इस

अवधि में बायो इंक््यूबेटर की संख्या

6 से बढ़कर 95 हो गई। वहीं 125

पेटेंट फाइलिंग की जगह हम 1300

तक पहुंच चुके हैं।

नई दिल्ली. राष्ट्रीय उपभोक्ता

विवाद निवारण आयोग

(एनसीडीआरसी) ने कहा है कि

खाताधारक की गलती या

लापरवाही नहीं होने के बावजूद

खाते से रकम निकाली गई है तो

बैंक को दस दिन में रकम वापस

करनी होगी।

श्रीर्ष उपभोक्ता आयोग ने

भारतीय रिजर्व बैंक के 2017 के

सर्कुलर के प्रावधानों को स्पष्ट

करते हुए यह फैसला दिया है।

आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एपी

शाही, सदस्य भरत कुमार पांड्या

की पीठ ने एक मामले में बेंगलूरु

की महिला खाताधारक के हक में

फैसला देते हुए राज्य उपभोक्ता

विवाद निवारण आयोग के फैसले

के खिलाफ बैंक की अपील

खारिज कर दी।

बॉम्बे हाईकोर्ट

नायलॉन मांझे के

इस्तेमाल पर होगा 25

हजार रुपए का जुर्माना

मुंबई @ पत्रिका. नायलॉन मांझे

से होने पर घातक दुष्प्रभाव को

देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त

रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की

नागपुर बेंच ने निर्देश दिया कि

नायलॉन मांझे से पतंग उड़ाने हुए

पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए का

जुर्माना देना होगा। इसके अलावा

किसी विक्रेता के पास ऐसे मांझे का

स्टॉक पाए जाने पर 2.5 लाख

रुपए का जुर्माना देना होगा।

नई दिल्ली @ पत्रिका ब्यूरो.

भारत ने बच्चों के खिलाफ

अपराधों की रोकथाम के लिए

दुनिया का अपनी तरह का पहला

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ)

आधारित टूल 'रक्षा' लॉन्च किया

है। यह टूल बच्चों की टैफिकिंग,

बाल विवाह और बाल यौन शोषण

व दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (सी-

सीम) की पहचान और रोकथाम में

मदद करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना

प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग

राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने

'प्रॉस्पेक्टिड प्यूब्लिश चैप्टर सेफ्टी

टेक समिट' में इस टूल का शुभारंभ

किया। यह सम्मेलन भारत सरकार

के इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट

2026 का आधिकारिक प्री-समिट

कार्यक्रम था। जस्ट राइट्स फॉर

चिल्ड्रेन द्वारा विकसित यह टूल

देशभर के बाल-संबंधित डेटा का

विश्लेषण कर संवेदनशील क्षेत्रों का

रियल-टाइम मानचित्रण करता है।

इसके जरिए संगठित अपराधों

का शिकार को निगरानी, शोष व

गंतव्य बिंदुओं की पहचान और

ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री

से जुड़े हीट जोन का पता लगाया

जा सकेगा। मंत्री जितिन प्रसाद ने

कहा कि बच्चों के लिए सुरक्षित

और समावेशी डिजिटल भविष्य

सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी

है। वहीं भुवनेश्वर में 'रक्षा' को

तकनीक के सहारे मजबूत बाल

संरक्षण प्रणाली की दिशा में भारत

का ऐतिहासिक कदम बताया।

म्यूचुअल फंड्स

भारतीय शेयर बाजार में भारी उठापटक के बीच निवेशकों का फंड मैनेजरों पर बढ़ा भरोसा

निवेशकों ने फ्लेक्सीकैप के जरिए खेला 'सुरक्षित' दांव

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

मुंबई. छोटे निवेशकों में इस बात

को लेकर असमंजस बढ़ रहा है

कि उठापटक वाले शेयर बाजार

में कहा निवेश किया जाए। ऐसे में

वे पोर्टफोलियो के फेसले फंड

मैनेजरों पर छोड़ना ज्यादा सुरक्षित

समझ रहे हैं। इसी वजह से

फ्लेक्सीकैप फंड्स में निवेश तेजी

से बढ़ा है, क्योंकि इनमें बाजार के

हालात के हिसाब से फंड मैनेजर

के पास बड़े, मझोले और छोटे

शेयरों में निवेश की आजादी होती

है। 2025 में फ्लेक्सीकैप फंड्स

में निवेश 98% बढ़कर 80,997

करोड़ हो गया, जो 2024 में

40,962 करोड़ था। इसके उलट,

सबसे ज्यादा रिस्की थीमैटिक-

सेक्टरल फंड्स से निवेशकों का

मोहभंग हुआ। निवेश 75% घटकर

38,144 करोड़ रह गया, जो

2024 में ₹1,55,000 करोड़ था।

एसबीआई

आइएमपीएस से राशि

भेजना होगा महंगा

मुंबई @ पत्रिका. एसबीआई

के ग्राहकों के लिए ऐप-इंटरनेट

बैंकिंग के जरिए तत्काल भुगतान

सेवा (आइएमपीएस) महंगी होने

जा रही है। आइएमपीएस के

जरिए 15 फरवरी से ज्यादा रकम

भेजने पर चार्ज देना होगा। बैंक

ने साफ किया कि 25,000 रुपए

तक आइएमपीएस से ऑनलाइन

से पैसे भेजना पहले की तरह

मुफ्त रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा

धनराशि भेजने पर शुल्क लगेगा।

आइएमपीएस के जरिए एक

लाख रुपए तक भेजने पर 2

रुपए शुल्क और जीएसटी

लगेगा। एक से दो लाख रुपए पर

6 रुपए सेवा शुल्क और

जीएसटी लगेगा। वहीं, दो से पांच

लाख रुपए ट्रांसफर करने पर 10

शुल्क और जीएसटी देना होगा।

अमरीकी दबाव

रूस से तेल खरीदारी

दिसंबर में 29% घटी

मुंबई @ पत्रिका. रूस से कच्चा

तेल खरीदने के मामले में भारत

दिसंबर 2025 में तीसरे स्थान पर

आ गया। भारत का रूस से कुल

हाइड्रोकार्बन आयात 2.3 अरब

यूरो रहा, जो नवंबर के 3.3

 9057531688